चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

मूल्य 5 रुपये

1986 से प्रकाशित

05 मई-11 मई 2014

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHI/2009/30467

पैसा चुनाव जीत रहा है, मुद्दा नहीं

फोटो-प्रभात पाण्डेय

आजकल समाचारपत्रों में, टेलीविज़न चैनलों पर, एफ एम रेडियो पर, सड़कों के किनारे लगे होर्डिंग्स पर, सोशल मीडिया में मोदी और उनका विकास मॉडल ही नज़र आता है. कांग्रेस और दूसरे राजनीतिक दल इस मामले में काफी पीछे छूट गए हैं. लेकिन, भाजपा द्वारा चलाए जा रहे विज्ञापन के इस तूफानी हमले में जो रक़म खर्च की जा रही है, वह भी असाधारण है. मीडिया में भाजपा के सूत्रों के हवाले से आई ख़बरों के मुताबिक़ यह रक़म पांच हज़ार करोड़ रुपये है, हालांकि विपक्षी दल और भाजपा के आलोचक इस खर्च को दस हज़ार करोड़ रुपये से ज़्यादा आंक रहे हैं. क्या है मोदी लहर, मोदी के विकास मॉडल और इस चुनाव में हावी मुद्दों का सच, पढ़िए इस रिपोर्ट में...

शशि शेखर

अक्सर राह चलते आपने सड़क किनारे किसी टॉर्च बेचने वाले को देखा होगा. टॉर्च बेचने वाला जोर-जोर से बोलता है कि रात में आपको सांप न काट ले, इसलिए अपने पास टॉर्च रखिए. अब आपको अंधेरे में सांप काटे न काटे, लेकिन एकबारगी आप इस बारे में सोचेंगे ज़रूर. हो सकता है, आप टॉर्च खरीद भी लें. बस, यहीं पर टॉर्च बेचने वाले का मकसद पूरा हो जाता है. कुछ ऐसी ही कहानी आज भारतीय राजनीति में देखने-सुनने को मिल रही है. आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है, जब एक अकेला आदमी अपनी पार्टी, अपने संगठन से बड़ा बना दिया गया है. पहली बार आम चुनाव मुद्दों पर नहीं, बल्कि एक आदमी के करिश्माई (तथाकथित) व्यक्तित्व के सहारे लड़ा जा रहा है. यह तथाकथित करिश्माई व्यक्तित्व हैं नरेंद्र मोदी. पारंपरिक एवं न्यू मीडिया के जरिये मोदी के विकास पुरुष की छवि देश-दुनिया में पहुंचा दी गई. गुजरात के विकास को सर्वोत्तम मॉडल बताया गया. इस सर्वोत्तम मॉडल और उसकी असलियत की चर्चा इस स्टोरी में विस्तार से की गई है. यह सब करने के लिए मीडिया के जरिये हज़ारों करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं. कैसे, कहां और कितने पैसे खर्च हुए हैं, इसका पूरा विवरण इस स्टोरी में दिया जा रहा है. ये विवरण किसी आरोप, किसी कल्पना के आधार पर नहीं दिए गए हैं, बल्कि ये ऐसे तथ्य हैं, जिन्हें भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं ने स्वीकार किया है और ये ऐसे खर्च हैं, जिन्हें आप अपनी आंखों से देख सकते हैं.

खर्च की बात करने से पहले यह स्पष्ट करना ज़रूरी है कि चुनाव खर्च के मामले में किसी भी पार्टी के लिए कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है. इस पर अंकुश लगाने के लिए कोई ठोस मैकेनिज्म नहीं है. हां, उम्मीदवारों के लिए अधिकतम सीमा 70 लाख रुपये ज़रूर तय की गई है. पार्टियां चाहे जितना खर्च करें. इसका अर्थ यह हुआ कि पार्टियां चुनाव से पहले या चुनाव के दौरान चाहे जितना खर्च करें, इसकी कोई सीमा नहीं है. मसलन, पार्टी की तरफ़ से चुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की घोषणा की जाती है. इन स्टार प्रचारकों पर जो खर्च आता है, वह पार्टी के खाते में जाता है, न कि उम्मीदवारों के खाते में. लेकिन, इसके लिए भी एक नियम है. अगर स्टार प्रचारक जिस मंच से भाषण देता है और उस मंच पर पार्टी का उम्मीदवार भी हो, तो वह खर्च उम्मीदवार के खाते में चला जाता है. यहां यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि किसी भी राजनीतिक दल का चुनाव प्रचार चुनाव की घोषणा होने, यानी आचार संहिता लागू होने से पहले ही शुरू हो जाता है. जैसे, जबसे भाजपा ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया, तभी से मोदी

(शेष पृष्ठ 2 पर)

एनडीए में कितने दल हैं?

यह धारणा है कि नरेंद्र मोदी की वजह से भाजपा को दूसरे दलों का समर्थन नहीं मिलने वाला है. मोदी ने इसके लिए भी एक भ्रम फैलाया कि वर्तमान में एनडीए अब तक का सबसे विशाल गठबंधन है. वैसे नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में एनडीए का जिक्र नहीं करते हैं, लेकिन दो इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी ने एनडीए की बात की. दोनों ही बार अलग-अलग बयान दिए. पहली बार कहा कि एनडीए 25 दलों का गठबंधन है. दूसरी बार यह बढ़कर 30 हो गया. अब सवाल है कि आख़िर एनडीए में कितने दल हैं? क्या ये दल चुनाव आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त हैं या फिर मोदी ने सिर्फ़ नंबर बढ़ाने के लिए इन दलों को एनडीए में शामिल किया है. अगर 30 दल हैं, तो वे किन-किन राज्यों में हैं और कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं? हैरानी तो इस बात की है कि देश के बड़े-बड़े पत्रकारों ने मोदी से बातचीत तो की, लेकिन वे यह सवाल नहीं पूछ सके कि मोदी लोगों को भ्रमित क्यों कर रहे हैं.

आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया

यद्यपि ये आंकड़े 2006 से 2012 के बीच इन राजनीतिक दलों की घोषित आय के हैं, लेकिन इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चुनाव प्रचार पर होने वाले खर्च और आय के बीच कितना फर्क है? बाकी का पैसा कहां से आता है, कौन देता है, क्यों देता है और फिर अंत में वह इसकी वसूली कैसे करता है? क्या इसका जवाब हमारे राजनीतिक दल और खासकर नरेंद्र मोदी देना पसंद करेंगे?

कुल आय (करोड़ में)

	निर्धारण वर्ष						
पार्टियां	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012	कुल आय
कांग्रेस	124.93	169.36	220.81	496.88	467.57	307.08	1786.63
बीजेपी	38.34	82.49	123.78	220.02	258.01	168.01	890.65
बहुजन समाज पार्टी	9.76	----	69.74	182.02	56.98	115.70	434.20
नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी	7.37	15.8	17.39	40.01	44.85	23.31	148.73
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी	1.22	0.74	1.24	1.16	1.29	2012	7.7
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)	41.6	63.4	59.70	62.83	73.28	76.57	377.38
एआईएडीएमके	12.95	6.40	3.00	12.50	9.74	14.20	58.79
समाजवादी पार्टी	48.35	87.05	32.3	39.00	28.1	15.21	250.01
जनता दल (यू)	1.34	0.55	0.22	9.31	11.33	3.42	26.17

सोर्स: एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म-नेशनल इलेक्शन वाच.

घर का डॉक्टर

प्रकृति के अनमोल तत्वों द्वारा तैयार किया गया आयुर्वेदिक तेल राहत रूह औषधियुक्त जड़ी-बूटियों का सशक्त मिश्रण है।

- सर दर्द
- बदन दर्द
- जोड़ों के दर्द
- सर्दी जुकाम
- जले कटे एवं चर्म रोग
- चक्कर आना (समलवाई)
- दिमाग की कमजोरी
- अनिद्रा में लाभकारी

वर्ष 1881 से निरन्तर सेवा में

हरबंशराम का आयुर्वेदिक तेल

तेल राहत रूह

तिल के तेल से निर्मित

अन्य उत्कृष्ट उत्पाद

हरबंशराम भगवानदास आयुर्वेदिक संस्थान प्रा.लि.

website:www.harbanshram.com Customer Care No.- 08447 427 621

जनरल मर्चेन्ट एवं केमिस्ट शॉप में भी उपलब्ध

आम आदमी पार्टी का काला सच 03

बेबस प्रधानमंत्री की व्यथा 05

राजनीतिक चकाचौंध में फिल्मी सितारे 07

साईं की महिमा 12

पैसा चुनाव जीत रहा है, मुद्दा नहीं

पृष्ठ एक का शेष

पूरे देश में घूम–घूमकर रैली कर रहे हैं. ऐसे में इस तरह के खर्च को भी चुनावी खर्च ही माना जाएगा.

बहरहाल, सबसे पहले शुरुआत करते हैं वहां से, जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया. तभी से नरेंद्र मोदी ने देश भर में रैली करना शुरू किया. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी एक–एक रैली में 7 से 10 करोड़ रुपये का खर्च आता है. यह गणना करके बताया गया है कि उनकी रैली में मंच, गाड़ियां, तकनीकी टीम, कैमरा, क्रेन समेत अन्य कई खर्च शामिल होते हैं. देश के सारे चैनलों को मोदी की पर्सनल टेक्निकल एवं कैमरा टीम के लोग मोदी के रैली के विजुअल उपलब्ध कराते हैं. यह टीम नरेंद्र मोदी की हरेक रैली में साथ चलती है. एक उदाहरण लेते हैं, पटना की हुंकार रैली का. कथित तौर पर इस रैली के लिए 6000 बसें, 20,000 एसयूवी, 11 ट्रेनें बुक कराई गई थीं. 30 फीट का एक डायनेमिक स्क्रीन लगा था. विशेष मंच तैयार किए गए थे. मोटे तौर पर हिसाब लगाएं, तो एक बस का किराया 5 हज़ार से 15 हज़ार रुपये होता है. औसतन इस खर्च को 10 हज़ार भी मान लिया जाए, तो 6 हज़ार बसों का किराया होता है 6 करोड़ रुपये. इसी तरह 20 हज़ार यूएसवी का किराया बनता है 4 करोड़ रुपये. 11 ट्रेनें सरकारी दर पर भी बुक कराई जाएं, तो उनका किराया बनता है क़रीब एक करोड़ रुपये. इस हिसाब से सिर्फ़ पटना की हुंकार रैली में लोगों को लाने के लिए ट्रांसपोर्ट पर 11 करोड़ रुपये खर्च किए गए. संभव है कि यह खर्च थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि आम तौर पर राजनीतिक दलों को ट्रांसपोर्टर सस्ती दरों पर वाहन मुहैया करा देते हैं, यानी ये 11 करोड़ रुपये 8 करोड़ भी हो सकते हैं. अन्य मदों मसलन हेलिकॉप्टर, बैनर, नाश्ता, पानी एवं सुरक्षा आदि का खर्च शामिल कर लें, तो यह एक बहुत बड़ी रकम हो जाती है. मोदी इस तरह की दर्जनों रैलियां आचार संहिता लागू होने से पहले कर चुके हैं और चुनाव ख़त्म होने तक क़रीब दो सौ के आसपास रैलियां कर चुके होंगे. चुनाव से पहले वाली मोदी की रैलियों का खर्च भारतीय जनता पार्टी के खाते में डालें, तो यह एक बहुत बड़ी रकम होगी. हालांकि, इस रकम का पक्का हिसाब लगाना कठिन है, लेकिन हुंकार रैली की तर्ज पर मोदी ने बड़े–बड़े शहरों में दर्जनों मेगा रैलियां की हैं. पटना की हुंकार रैली पर होने वाले खर्च को मानक मान लिया जाए, तो बड़े–बड़े शहरों में हुईं उनकी रैलियों पर होने वाले खर्च का एक अंदाजा तो लगाया ही जा सकता है. इसके अलावा, चुनाव के दौरान स्टार प्रचारक होने के नाते मोदी की रैली का खर्च पार्टी के खाते में जाएगा. हालांकि, जिन मंचों पर पार्टी का उम्मीदवार मौजूद होगा, वहां का खर्च उस उम्मीदवार के खाते में चला जाएगा.

लेकिन, रैलियों पर होने वाला यह खर्च एक झांकी भर है. असली खर्च इसके आगे शुरू होता है. इसे आप एडवर्टिजमेंट वार (युद्ध) भी कह सकते हैं. इसे आप गोएबल्स थ्योरी का व्यवहारिक प्रयोग भी कह सकते हैं. थोड़ा संशोधन करते हुए यह कह सकते हैं कि यहां अगर पूर्णत: झूठ का प्रचार नहीं हो रहा, तो पूरा सत्य भी सामने नहीं लाया जा रहा है. यानी अर्द्धसत्य को पूर्णसत्य बनाकर लगातार इस तरह पेश किया जा रहा है, मानो वही अंतिम सत्य हो. यह अर्द्धसत्य दरअसल, एडवर्टिजमेंट के रूप में पिछले कई महीनों से टीवी पर दिखाया जा रहा है. भाजपा की ओर से 10 से 30 सेकेंड के क़रीब 25 एडवर्टिजमेंट बनाए गए हैं. टीवी एडवर्टिजमेंट रेट के मुताबिक, 30 सेकेंड के एड के लिए 80 हज़ार रुपये लगते हैं. भाजपा ने तीन महीने के लिए 2000 स्पॉट प्रतिदिन हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं के चैनल पर बुक कराए हैं. इसके अलावा, गुजरात विकास से जुड़े एड पहले से ही आ रहे हैं. अब अगर इसका औसत हिसाब लगाएं, तो एक दिन में 12 करोड़ रुपये एडवर्टिजमेंट पर खर्च हो रहे हैं. इस हिसाब से तीन महीने में टीवी एडवर्टिजमेंट पर भाजपा की ओर से क़रीब 11 सौ करोड़ रुपये खर्च हो चुके होंगे.

इसके अलावा, भाजपा ने देश भर में 15,000 होर्डिंग लगाए हैं. 3 लाख से 15 लाख रुपये माहवार किराए की दर से तीन महीने के लिए ये होर्डिंग लगाए गए हैं. इस मद में क़रीब 2 हज़ार करोड़ रुपये से अधिक की लागत आ रही है. प्रिंट मीडिया के लिए भी भाजपा ने जबरदस्त रूप से एडवर्टिजमेंट बांटने की योजना बनाई. देश के 50 अख़बारों में 40 दिन तक, प्रतिदिन 4 से 5 एडवर्टिजमेंट दिए गए. इसके लिए क़रीब 500 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है. मैग्जीन वाले शिकायत न करें, इसका इंतजाम भी भाजपा ने किया है. मैग्जीन के लिए अलग से 150 करोड़ रुपये का एडवर्टिजमेंट बजट रखा गया है. अकेले टी–20 वर्ल्डकप के लिए ही 150 करोड़ रुपये का एडवर्टिजमेंट दिया गया. इस बहती गंगा में कोई प्यासा न रहे, इसके लिए इंटरनेट, एफएम रेडियो आदि के लिए अलग से 35 करोड़ रुपये का एडवर्टिजमेंट तैयार किया गया.

अब यहां सवाल उठता है कि बिहार में नीतीश कुमार ने भी विकास किया. वहां भी सड़क, बिजली, सरकारी नौकरियों में महिलाओं की संख्या में बढ़ोत्तरी, क़ानून–व्यवस्था में सुधार, महिला सशक्तिकरण जैसे काम होते हुए दिखे. लेकिन, इस चुनाव में तक़रीबन हरेक सर्वेक्षण नीतीश कुमार को 3 से 4 सीटें दे रहा है. तो क्या इस चुनाव में विकास का मुद्दा गौण हो गया है? दूसरी तरफ़, मोदी इसी बिहार या उत्तर प्रदेश में जाकर विकास के नाम पर, गुजरात के विकास की बात करके वोट मांग रहे हैं. क्या ये दोनों बातें अंतर्विरोधी नहीं हैं? जाहिर है, नरेंद्र मोदी के विकास की बात मीडिया के जरिये फैलाई जा रही है, जहां एडवर्टिजमेंट के नाम पर हज़ारों करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं. अगर इतना ही पैसा या मीडिया मैनेजमेंट का हुनर नीतीश कुमार के पास होता, तो शायद वह भी मीडिया और एडवर्टिजमेंट के जरिये अपनी विकास गाथा का ढिंढोरा पीट–पीटकर छाए रहते.

यानी इस चुनाव में भाजपा की ओर से जिस विकास की बात कही जा रही है, वह मीडिया के जरिये, हज़ारों करोड़ रुपये खर्च करके गढ़ी गई है, क्योंकि अगर सचमुच इस चुनाव में विकास एक मुद्दा होता, तो नीतीश कुमार इस चुनावी दौड़ में इतने पीछे नहीं दिखते. क्या यह सही नहीं है कि उत्तर प्रदेश, बिहार या अन्य राज्यों में एक बार फिर राजनीतिक समीकरण यानी जातीय समीकरण ने विकास के मुद्दे को इस चुनाव में गौण कर दिया है? सवाल है कि जिस विकास की बात मोदी अपने भाषणों में करते हैं, उसका मतलब क्या है? कैसा विकास और किसका विकास? सवाल है कि जो युवा वर्ग इन चुनावी एडवर्टिजमेंट के मायाजाल में फंस कर मोदी के समर्थन में आएगा, उसे मोदी कहां से रोज़गार देंगे? महंगाई को कैसे कम करेंगे, कितने दिनों में कम करेंगे, इसकी रूपरेखा क्या है उनके पास? मोदी मैन्यूफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग के जरिये रोज़गार सृजन की बात करते हैं. चीन हमारे यहां अपने माल की डंपिंग कर रहा है. हमारी विदेशी मुद्रा चीन जा रही है. ऐसे में मोदी क्या करेंगे? क़रीब 48 बिलियन डॉलर का हम सिर्फ़ सेलफोन जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान का आयात कर रहे हैं. क्या हम भारत में सेलफोन नहीं बना सकते? हम डॉलर में भुगतान करते हैं. सेलफोन के लिए हमें चीन की ज़रूरत है. क्या नरेंद्र मोदी ने इसका कोई समाधान देने की बात कही है? मोदी भारत को विश्वगुरु बताते हैं. वह कहते हैं कि हम बड़ी संख्या में शिक्षक तैयार करके विदेशों में भेज सकते हैं. लेकिन, सवाल है कि इस देश में जबसे शिक्षा का अधिकार क़ानून लागू हुआ है, तबसे सभी बच्चों को शिक्षा देने के लिए पर्याप्त संख्या में न तो शिक्षक हैं और न स्कूल. नेशनल नॉलेज कमीशन के मुताबिक, अभी भी देश में सैकड़ों विश्वविद्यालयों और हज़ारों प्रोफेसरों की ज़रूरत है. ऐसे में शिक्षक तैयार करके विदेश भेजने की बात हास्यास्पद नहीं है, तो और क्या है?

गुजरात के औद्योगिक विकास से किसका फायदा हुआ? सवाल है कि यही मॉडल पूरे देश में लागू करके मोदी किसका विकास करना चाहेंगे? गुजरात मॉडल से गुजरात के आदिवासियों, दलितों और ग़रीबों का कितना भला हुआ? गुजरात में 80 हज़ार दलितों ने अभी हाल में बौद्ध धर्म अपनाया है. गुजरात के आदिवासियों के नाम पर आने वाली विकास योजनाओं का हश्र और भी खराब है. उदाहरण, केंद्र सरकार ने आदिवासी लड़कों एवं लड़कियों के लिए छात्रावास बनाने की योजना शुरू की थी. इसके तहत गुजरात सरकार को वर्ष 2010–11 में 1296.43 लाख रुपये का अनुदान मिला, लेकिन मोदी सरकार प्रदेश में एक भी छात्रावास नहीं बनवा सकी . वर्ष 2011–12 में यही स्थिति रही. उसी तरह 2012–13 में भी 187.06 लाख रुपये मिले, लेकिन छात्रावास का निर्माण नहीं हो सका. कुछ यही कहानी गुजरात आश्रम स्कूल योजना की रही. आदिवासी बच्चों की शिक्षा के लिए आश्रम स्कूल की स्थापना के लिए 2010–11 में 1887.53 लाख रुपये मोदी सरकार को मिले. सरकार ने इस धनराशि से 8 विद्यालय खोले, लेकिन उसके बाद इस योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही बरती गई. वर्ष 2011–12 में भी केंद्र सरकार की ओर से 15 करोड़ रुपये की धनराशि राज्य सरकार के खाते में आई, लेकिन ये रुपये खजाने की शोभा बढ़ाते रहे. आंकड़ों के अनुसार, आदिवासी इलाकों में वोकेश्नल ट्रेनिंग के लिए वर्ष 2011–12 में केंद्र सरकार की ओर से 228.96 लाख रुपये गुजरात सरकार को मिले, लेकिन उसे खर्च नहीं किया गया. यही स्थिति आगामी वर्षों में भी रही. इससे जाहिर होता है कि आदिवासियों के कल्याण के लिए गुजरात सरकार कितनी गंभीर है.

मुसलमानों के संदर्भ में मोदी का व्यवहार ऐसा है, मानो वह कहना चाहते हों कि मुसलमान उन्हें वोट न दें, तो भी कोई बात नहीं है. ऐसा शायद इसलिए भी है, क्योंकि जब मोदी ने सद्भावना उपवास शुरू किया, तब मंशा यह थी कि इससे उनकी छवि थोड़ी नर्म बनेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. अब खुद उनके या उनके सिपहसालार अमित शाह के बयान से यही लगता है कि उन्हें इस देश की 20 फ़ीसद आबादी की कोई चिंता नहीं है. सवाल है कि इतनी बड़ी आबादी को अलग–थलग करके आप कैसे और कितना विकास कर सकते हैं? बहरहाल, इस चुनाव में बातें विकास की भले हो रही हों, लेकिन जिस तरीके से धनबल का इस्तेमाल हो रहा है, वह विकास के मुद्दे पर भारी पड़ रहा है. बेशक गुजरात में भी विकास हुआ है और नरेंद्र मोदी को इसका श्रेय मिलना चाहिए. संभव है कि उन्हें इस लोकसभा चुनाव में फायदा भी मिल जाए या मिलता हुआ दिख रहा है, लेकिन इस चुनाव में सचमुच अगर बात सिर्फ़ विकास की होती, तो उस सूची में महाराष्ट्र भी आता, बिहार भी आता, हरियाणा भी आता, तमिलनाडु भी आता, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि विकास यहां भी हुआ है. नीतीश कुमार ने भी बिहार को विकास की पटरी पर लाने का काम किया है, लेकिन आज चुनावी सर्वेक्षणों में वह कहीं भी शामिल होते नहीं दिख रहे हैं. तो फिर क्या इस चुनाव में जीत के लिए विकास से इतर भी कई चीजें चाहिए? जाहिर है, पैसा वह चीज है, जो आज इस चुनाव में मुद्दों पर भारी पड़ गया. ■

साथ में शफ़ीक़ आलम

shashishekhar@chauthiduniya.com

फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

राज्य की वार्षिक योजनाओं से ज़्यादा पैसा प्रचार में!

भाजपा सिर्फ़ विज्ञापन की मद में जो धनराशि खर्च कर रही है, वह केंद्रीय योजना आयोग द्वारा देश के कई छोटे राज्यों को वर्ष 2013–14 के लिए आवंटित की गई वार्षिक योजनाओं की रक़म से कहीं ज़्यादा है. वर्ष 2013–14 के लिए केंद्रीय योजना आयोग ने वार्षिक योजना के तहत गोवा को 4700 करोड़, मणिपुर को 3650 करोड़, मिजोरम को 2500 करोड़, नगालैंड को 2000 करोड़, हिमाचल प्रदेश को 4400 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. इस आम चुनाव में चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में एक लोकसभा उम्मीदवार द्वारा खर्च की जाने वाली धनराशि की अधिकतम सीमा 40 लाख से बढ़ाकर 70 लाख रुपये कर दी है. हालांकि यह अलग बहस है कि चुनाव आयोग के रिकॉर्ड के अनुसार, 2009 के आम चुनाव में ज़्यादातर उम्मीदवारों ने तयशुदा राशि का आधा ही खर्च किया. तो फिर व्यय सीमा बढ़ाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? बहरहाल, भाजपा ने लोकसभा की सभी सीटों से अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किए हैं. फिर भी अगर 70 लाख रुपये प्रति सीट की दर से 543 सीटों का हिसाब लगाया जाए, तो कुल 382 करोड़ रुपये बनते हैं. चुनाव व्यय को सीमित रखने के लिए चुनाव आयोग की तमाम सतर्कता के बावजूद ऐसी स्थिति है. अब यह सवाल उठना लाजिमी है कि अगर यह सतर्कता न होती, तो क्या होता? ऐसा नहीं है कि इस मामले में भाजपा ही एकमात्र राजनीतिक दल है, जो निर्धारित सीमा से अधिक व्यय कर रही हो, इसमें दूसरे तमाम राजनीतिक दल भी शामिल हैं. सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के तत्वावधान में कराए गए एक अध्ययन के मुताबिक, 16वीं लोकसभा के लिए 543 सदस्यों के चुनाव में कुल 30,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जो अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में खर्च हुए 42,000 करोड़ रुपये के बहुत नज़दीक है. ऐसी स्थिति उन लोगों के तर्क को पुख्ता करती है, जो चुनाव में स्टेट फंडिंग की वकालत करते हैं.

काला धन वापस कैसे लाएंगे?

नरेंद्र मोदी ने काले धन के मामले पर अभी से ही उलझाना शुरू कर दिया. एक टीवी इंटरव्यू में मोदी ने कहा कि सरकार बनने के बाद वह आकलन करेंगे कि विदेशी बैंकों में काला धन है या नहीं? और अगर है, तो कितना है? उन्होंने कहा कि इसके लिए एक लीगल टीम बनाई जाएगी, क़ानून बदलना होगा, दूसरे देशों के साथ संधि करनी पड़ेगी. वैसे यही बात तो कांग्रेस पार्टी भी अब तक कहती आई है. पहला सवाल यह है कि क्या मोदी को अब तक यह नहीं मालूम है कि विदेशी बैंकों में देश का काला धन है? अगर दूसरे देशों के साथ संधि न हो पाई, तब क्या होगा? कहने का मतलब यह कि मोदी काले धन पर साफ़–साफ़ क्यों नहीं बोल रहे हैं? दूसरी बात यह है कि मोदी देश के अंदर फैले काले धन के बारे में कुछ क्यों नहीं बोलते?

अपरिपक्व बयान

नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को लेकर जो बयान दिए हैं, उनका पाकिस्तानी राजनयिकों ने स्वागत किया है. मोदी ने पाकिस्तान को यह इशारा दिया है कि विदेश नीति में वह अटल बिहारी वाजपेयी की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे. सवाल यह है कि क्या चुनाव हो गए हैं? क्या भाजपा चुनाव जीत चुकी है? नरेंद्र मोदी को यह समझना चाहिए कि देश में अभी भी एक सरकार है, विदेश मंत्रालय है. भारत की राजनीति का एक अहम पहलू है कि विदेश नीति को लेकर देश में विवाद नहीं होता. सरकार किसी भी दल की आए, लेकिन विदेश नीति के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाती. मोदी ने चुनाव के दौरान ही इस तरह के बयान देकर भारत सरकार की अवहेलना की है. इस तरह का बयान अगर चुनाव नतीजे आने के बाद दिया जाता, तब भी कोई बात होती, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान ऐसे बयान देकर मोदी ने अपने बड़बोलेपन और अपरिपक्वता का परिचय दिया है.

ब्यूरोक्रेसी में हलचल का मतलब?

देश में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन दिल्ली के मंत्रालयों में काम ठप्प पड़ चुका है. ऐसा लग रहा है कि सरकारी तंत्र छुट्टी पर चला गया है. वरिष्ठ अधिकारियों ने यह मान लिया है कि नई सरकार आने वाली है और वह बिल्कुल नए तरीके से चलने वाली है. कई अधिकारी अभी से ही भारतीय जनता पार्टी और मोदी के नज़दीकियों से रिश्ते बनाने में जुटे हैं. ऐसा माना जा रहा है कि सत्ता परिवर्तन के साथ–साथ देश में अधिकारियों की बड़े पैमाने पर छुट्टी और तबादले की प्रक्रिया शुरू होगी. कई अधिकारी तो ऐसे हैं, जो पिछले कई सालों से चुप थे, वे अब फाइलों में सरकारी नीतियों पर ही सवाल उठाने लग गए हैं. वे इसलिए सवाल उठा रहे हैं, ताकि अगली सरकार को बता सकें कि वे पिछली सरकार के चहेते अधिकारी नहीं थे. अगर नई सरकार आने के बाद बड़े पैमाने पर अधिकारियों का तबादला हुआ, तो यह एक गलत प्रथा की शुरुआत होगी. अधिकारी वर्ग का ग़ैर–राजनीतिक रहना ज़रूरी है. यह हमारे प्रजातंत्र की ज़रूरत है. ब्यूरोक्रेसी का राजनीतिकरण ख़तरनाक है. चुनाव नतीजे आने में ज़्यादा दिन शेष नहीं हैं. यह तभी पता चलेगा कि क्या ये अधिकारी भारतीय जनता पार्टी या मोदी के इशारे पर ऐसा कर रहे हैं या फिर नई सरकार के सामने अपने नंबर बढ़ाने के लिए दिखावा कर रहे हैं. देखिए, चुनाव के बाद क्या होता है?

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 06 अंक 09
दिल्ली, 05 मई–11 मई 2014
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय
संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार–झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना–800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

ब्यूरो चीफ (लखनऊ)
अजय कुमार
जे–3/2 डालीबाग कॉलोनी, हजरतगंज, लखनऊ–226001
फोन : 0522–2204678, 9415005111

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के– 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के–2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301

फोन न.

संपादकीय	0120–6451999
	6450888
विज्ञापन व प्रसार	022–42296060
	+91–8451050786
	+91–9266627379
फैक्स न.	0120–2544378

पृष्ठ–16+4 (बिहार–झारखंड, उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड) हर शुक्रवार को प्रकाशित

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

आम आदमी पार्टी का काला सच

आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता अरविंद केजरीवाल की असलियत सामने आने लगी है. सत्ता की ख़ातिर पहले उन्होंने अन्ना हज़ारे को धोखा दिया, उसके बाद दिल्ली की जनता को. और, अब वह अपनी पार्टी के नेताओं को भी नज़रअंदाज़ करने लगे हैं. ख़ुद को बेहद मामूली शख्स बताने वाले केजरीवाल को अरब देशों और फोर्ड फाउंडेशन के माध्यम से बेशुमार धन मिल रहा है. अश्विनी उपाध्याय आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं और उनके ही नाम से चुनाव आयोग में यह पार्टी पंजीकृत है. क्या है पूरा मामला? इसी मसले पर चौथी दुनिया के संपादक समन्वय *डॉ. मनीष कुमार* ने अश्विनी उपाध्याय से एक लंबी बातचीत की. पेश हैं उसके मुख्य अंश...

अरविंद केजरीवाल से आपकी पुरानी दोस्ती थी, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि आप आम आदमी पार्टी से अलग हो गए?

पिछले कई महीनों से कुछ बातों को लेकर हमारा विरोध चल रहा था. हमारा पारिवारिक रिश्ता है, लेकिन हमारे लिए सत्ता पहले नहीं, बल्कि देश पहले है. अब वे लोग रास्ता भटक गए हैं, उनमें देश के लिए कोई जज्बात बचे नहीं हैं. उनके लिए भ्रष्टाचार अब कोई मुद्दा नहीं है और भ्रष्टाचार के नाम पर वे लोगों को धोखा दे रहे हैं.

केजरीवाल को लेकर आपकी इतनी नाराज़गी क्यों है?

मैं आपको दो-तीन उदाहरण देता हूं. दिल्ली में एक लोकायुक्त क़ानून है, जो सबसे बढ़िया है. केजरीवाल मुख्यमंत्री बने, अगर उनकी नीयत साफ़ होती, तो वह उसमें बदलाव कर सकते थे. केजरीवाल जिस लोकपाल की ढफली बजाते हैं, उसकी धाराएं अगर वह चाहते, तो लोकायुक्त क़ानून में डाल सकते थे. अगर उसका नाम लोकायुक्त ही रहता, तो इससे क्या फ़र्क़ पड़ता? भ्रष्टाचार नाम से नहीं, बल्कि धाराओं से कम होता है. उन्होंने (केजरीवाल) ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनकी मंशा ठीक नहीं थी. दूसरी बात, मुख्यमंत्री बनने के पहले केजरीवाल ने जनता को बेवकूफ बनाया कि हम जनमत संग्रह कराएंगे, लेकिन इस्तीफ़ा देते समय उन्होंने ऐसा नहीं किया.

आख़िर केजरीवाल ने अचानक इस्तीफ़ा क्यों दे दिया?

दरअसल, चार लोगों की मीटिंग हुई थी, जिसमें योगेंद्र यादव, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और मनीष सिसौदिया शामिल थे. यहां तक कि उसमें प्रशांत भूषण

भी शामिल नहीं थे. उन्हीं चार लोगों ने मिलकर यह फ़ैसला लिया था.

इस तरह के फ़ैसले लेने के पीछे मुख्य वजह क्या है?

उनकी मानसिकता यह थी कि वे चारों तरफ़ जाएंगे और सभी जगहों से चुनाव लड़ेंगे. दरअसल, वे देश में खिचड़ी सरकार बनने की इच्छा रखते हैं. ऐसा इसलिए, क्योंकि हंग पार्लियामेंट बनने की स्थिति में उन लोगों को एक बड़ी डील मिलने वाली है. किसी तरह देश अस्थिर सरकार की ओर बढ़ जाए, यही उनका एजेंडा है. यानी देश में सत्ता विरोधी लहर के तहत पड़ने वाला वोट किसी तरह तितर-बितर हो जाए, ताकि मतदाताओं के बीच अराजकता फैल जाए.

इसका मतलब कि केजरीवाल ने जन-लोकपाल की वजह से इस्तीफ़ा नहीं दिया. इस बात में कितनी सच्चाई है कि उनके दफ्तर में जम्मू-कश्मीर के आतंकवादी आते हैं, नक्सली आते हैं. क्या आम आदमी पार्टी के दफ्तर में आपने उन्हें कभी देखा है?

हां आते हैं. कनॉट प्लेस स्थित ऑफिस में भी आते हैं, प्रो-टेररिस्ट आते हैं. कभी-कभी आतंकवादी भी आते हैं. नक्सली प्रशांत भूषण के जंगपुरा स्थित ऑफिस में भी आते और मीटिंग करते हैं. जो तड़ीपार हैं, भगोड़े हैं, जिन्हें पुलिस जम्मू, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं असम में ढूंढ रही है, ऐसे लोग भी आते हैं. मैं यह बात पूरी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूं.

कुछ लोगों के मन में धारणा है कि केजरीवाल व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं. क्या उनके पास वाकई ऐसी कोई योजना है या फिर महज दिखावा है?

नहीं, ऐसी चर्चा तो हमारे यहां नहीं होती है. इसे लेकर कभी कोई मीटिंग नहीं हुई. हालांकि आरटीआई वगैरह की चर्चा हम लोग पहले करते थे. आरटीआई में हम लोग ग्राउंड वर्क करते थे कि कहां आरटीआई डाली जाए, लेकिन देश की इकोनॉमी और विदेश नीति पर कभी कोई चर्चा नहीं हुई.

आशुतोष और आशीष खेतान जैसे लोगों को टिकट देने के पीछे क्या वजह थी?

वहां सिर्फ़ चार आदमी हैं और वही सब कुछ हैं. पार्टी में प्रशांत भूषण की भी नहीं चलती. कुमार विश्वास को भी आजकल किनारे कर दिया गया है. अरविंद केजरीवाल, योगेंद्र यादव, मनीष सिसौदिया और संजय सिंह ही फरमान जारी करते हैं. इसके अलावा पार्टी में किसी की विशेष अहमियत नहीं है. हम लोगों ने छह महीने पहले यह चर्चा की थी कि पार्टी किन-किन जगहों से चुनाव लड़े. ज़्यादातर लोगों की राय यह थी कि एडीआर की रिपोर्ट में जहां टॉप 35 करप्ट और टॉप 35 क्रिमिनल हैं, उन सीटों पर पार्टी चुनाव लड़े, लेकिन अचानक यह फ़ैसला हुआ कि पार्टी 350 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जो बढ़कर 450 सीटें हो गईं. कांग्रेस और भाजपा से ज़्यादा जगहों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार खड़े हैं.

आख़िर इस निर्णय के पीछे मुख्य वजह क्या थी?

केवल एक ही एजेंडा है कि देश में खिचड़ी सरकार बने. जबसे अरविंद मुख्यमंत्री बने हैं, तबसे योगेंद्र यादव परेशान हैं. उन्हें लगता है कि जब अरविंद मुख्यमंत्री बन सकता है, तो मैं क्यों नहीं. हरियाणा में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं और वहां पार्टी ने बतौर मुख्यमंत्री योगेंद्र यादव के नाम का ऐलान कर दिया है. कांग्रेस की जो हालत दिल्ली में है, वही हालत हरियाणा में है.

केजरीवाल ने वाराणसी से चुनाव लड़ने का फ़ैसला क्यों किया?

केवल मीडिया में बने रहने के लिए. उनका एक ही मक़सद है, सुर्ख़ियों में बने रहना. लिहाज़ा, वह मीडिया में बने रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं.

वाराणसी में आम आदमी पार्टी के कितने कार्यकर्ता हैं?

हमारे जो फुलटाइम वर्कर हैं, वही दिल्ली से बनारस गए हैं. पार्टी ने जून-जुलाई में दिल्ली के हर विधानसभा क्षेत्र में दस-दस कार्यकर्ता नियुक्त किए थे, जिन्हें 25 हज़ार रुपये मिलते थे. उन सभी लोगों को कैश पेमेंट मिलता था. यह कैश नवीन जिंदल की ओर से आता है. वही फंड करते हैं. चेक पेमेंट सीताराम जिंदल करते हैं.

वाड्रा के बचाव में उतरे एक शख्स को पार्टी का टिकट मिला, आख़िर उसे टिकट देने की कहानी क्या है?

आपको याद होगा वाड्रा के नाम पर अरविंद केजरीवाल ने मीडिया में खूब नाम कमाया. लोगों को लगा कि अरविंद ईमानदार आदमी है, क्योंकि वह वाड्रा की आलोचना कर रहा है. खेमका का तबादला हो गया, उसके बाद युद्धवीर आया उसकी जगह. उसने आते ही रिपोर्ट बनाई कि वाड्रा की जमीन ठीक है. उसने री-स्टोर कर दिया, जो पहले से कैंसिल था और खेमका के ख़िलाफ़ उसने चार्जशीट तैयार कर दी. योगेंद्र यादव का गांधी परिवार से काफी पुराना संबंध है. वह पहले एनएसी में थे, सिब्बल की यूजीसी में भी थे और कम से कम चालीस अन्य कमेटियों में रहे पिछले दस वर्षों में. योगेंद्र यादव ने युद्धवीर से कहा, आप पहले उसे (वाड्रा) क्लीनचिट दीजिए और फिर नौकरी से अपना इस्तीफ़ा. इसके बदले हम आपको टिकट दे देंगे. वजह, कांग्रेस उसे टिकट नहीं दे सकती थी, इसलिए आम आदमी पार्टी से युद्धवीर को टिकट मिला.

कबीर और पीसीआरएफ संस्था पर आरोप लगते रहे हैं कि उन्हें फोर्ड फाउंडेशन की ओर से पैसे मिलते हैं, सच्चाई क्या है?

हमारी पार्टी के संविधान में लिखा हुआ है कि एक ही आदमी को चुनाव का टिकट मिलेगा और एक आदमी कोर कमेटी में रहेगा. इसलिए प्रशांत भूषण कोर कमेटी के सदस्य हैं, लेकिन शांति भूषण नहीं हैं. हालांकि पीछे से वह पूरा सपोर्ट करते हैं, लेकिन ऑन पेपर उनका नाम नहीं है. कविता रामदास मुखिया हैं फोर्ड फाउंडेशन की. उनके पिता एल रामदास, माता ललिता रामदास, बहन सागरी रामदास आम आदमी पार्टी की कोर कमेटी में शामिल हैं. क्या कोई आम आदमी नहीं बचा भारत में कि फोर्ड फाउंडेशन का पूरा कुनबा आपने पार्टी में शामिल कर लिया? जिस युद्धवीर ने वाड्रा को क्लीनचिट दी, वह हमारी लैंड इक्वीजिशन कमेटी में है. अब वह बताएगा कि जमीनें कैसे अधिग्रहीत की जाएंगी. जो योगेश दहिया सहारनपुर के किसानों का 300 करोड़ रुपये मुआवजा खा गया, वह हमारा एग्रीकल्चर रिफॉर्म बनाएगा. अब मैं फोर्ड की कहानी बताता हूं. यह कबीर की रिपोर्ट है, जिसकी जांच हुई है. अगर सबकी जांच हो, तो कई मामले सामने आएंगे. 12 नवंबर, 2007 को उसका रजिस्ट्रेशन हुआ और 2005 में 44 लाख रुपये मिल गए यानी दो साल पहले. 2006 में 32 लाख रुपये मिल गए कबीर के नाम पर यानी संगठन बना नहीं और पैसे मिलने शुरू हो गए. इस मेहरबानी का मतलब क्या है. यह है कबीर की असलियत. मुझे तकलीफ इस बात की है कि पार्टी में रहकर भी मैं आम आदमी पार्टी की असलियत देर से जान पाया. भारत की आम जनता को जब इसका पता चलेगा, तब तक काफी देर हो चुकी होगी. इस देश की हालत सोवियत रूस जैसी होने वाली है, उसी तरह पंद्रह टुकड़ों में बंट जाएगा यह देश, क्योंकि वे हर जगह जनमत संग्रह कराने की बात करते हैं. वे वोट की खातिर कुछ भी करने को तैयार हैं. केजरीवाल ने दिल्ली में झाड़ू यात्रा निकाली थी. एक दिन पहले वह ओखला में पहुंचती है, जहां बटला हाउस है. वहां लोगों से वह कहते हैं कि मारे गए लड़के निर्दोष थे, इसकी जांच होनी चाहिए. अगले दिन झाड़ू यात्रा द्वारका पहुंचती है और वह मोहन चंद शर्मा की पत्नी माया शर्मा से कहते हैं कि मुझे बहुत दुःख है कि आपके पति आतंकवादियों को मारते हुए शहीद हो गए. इस तरह का दोहरा चरित्र आपने कहीं देखा है? दरअसल, अरविंद केजरीवाल की असलियत यही है. योगेंद्र यादव गुड़गांव के अहीरवाल क्षेत्र में कहते हैं कि मैं यादव हूं, कृष्ण का वंशज हूं, जबकि मेवात इलाके में अपना हुलिया बदल कर वह मुसलमानों से कहते हैं कि मेरे बचपन का नाम तो सलीम है. अब वहां उन्हें सब लोग सलीम भाई, सलीम भाई बुलाते हैं. इतना दोहरा चरित्र तो किसी पार्टी और नेताओं का नहीं रहा होगा. जब कमाल फारूकी ने बोला कि यासीन भटकल निर्दोष है, तो मुलायम सिंह को भी शर्म आई और उन्होंने उसे महासचिव पद से हटाते हुए पार्टी से बाहर कर दिया. उस आदमी को केजरीवाल ने बरेली से टिकट पक्का कर दिया. रजा मुजफ्फर भट्ट, जो कहता है कि अफजल गुरु निर्दोष, भटकल निर्दोष और कसाब निर्दोष, उसे श्रीनगर से टिकट मिल गया. सोनी सोरी, जो एस्सार और जिंदल का पैसा पहुंचाती थी नक्सलियों तक, उसे बस्तर से आम आदमी पार्टी का टिकट दे दिया गया.

आम आदमी पार्टी पर आरोप लगते रहे हैं कि वह फोर्ड फाउंडेशन के इशारे पर काम करती है. क्या कोई विदेशी नागरिक आपके यहां काम करता था, जिसका बायोडाटा आपको संदिग्ध लगा हो?

हां, एक लड़की मनीष सिसौदिया के यहां काम करती थी कबीर संस्था में. मैं तो पीसीआरएफ में काम करता था.

आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आंदोलन से पहले कितने विदेशी दौरे किए?

फॉरेन टूर उनका काफी फ्रीक्वेंट रहा है. अगर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसौदिया और योगेंद्र यादव का वर्ष 2004 से लेकर अब तक का विदेश यात्रा वाला डाटा सामने आ जाए, तो बहुत बड़ा खुलासा हो जाएगा. भारत में किसी पार्टी को अरब देशों से पैसा नहीं आता, लेकिन मैं जानता हूं कि विधानसभा चुनाव के दौरान अरब देशों से पैसा आया और आम आदमी पार्टी ने उसे पानी की तरह बहाया. इसी तरह फोर्ड फाउंडेशन का पैसा आता है. अरविंद केजरीवाल को बताना चाहिए कि वह अरब देश क्या करने जाते हैं, जर्मनी और अमेरिका क्यों जाते हैं? मैंने अरविंद केजरीवाल से यही पूछा था कि आप दस जनपथ में काम करने वाले आशीष तलवार के साथ जर्मनी क्या करने गए थे, लेकिन उन्होंने आज तक इसका जवाब नहीं दिया.

अरविंद केजरीवाल किस मकसद से जर्मनी और अमेरिका जाते थे?

एक बड़ी डील की कहानी उससे जुड़ी हुई है. दरअसल, एक पेपर उनके हाथ लग गया था, सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंट के 400 करोड़ रुपये के घोटाले का. उसी पेपर के जरिये वह एनएसी में इंट्री करना चाहते थे. अगर उनकी नीयत सही होती, तो वह उस पेपर को पुलिस को देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. बाद में जब सोनिया गांधी को लगा कि यह तो ख़तरनाक आदमी है, तो उन्होंने आशीष तलवार के साथ केजरीवाल को विदेश भेज दिया. उसके बाद योगेंद्र यादव को एनएसी में ले लिया गया.

आम आदमी पार्टी की नेता संतोष कोली की मौत को भी कई लोग संदिग्ध मान रहे हैं. आपका क्या मानना है?

निश्चित रूप से संतोष कोली की मौत को लेकर एक रहस्य है. केजरीवाल ने संतोष कोली को शहीद का दर्जा देकर उसके नाम पर दिल्ली चुनाव में वोट मांगे. उन्होंने कहा था कि हम इसकी जांच कराएंगे, लेकिन 49 दिनों तक सरकार में रहने के बावजूद उन्होंने संतोष कोली की मौत की उच्चस्तरीय जांच नहीं कराई. इसका मतलब कहीं न कहीं दाल में कुछ काला ज़रूर है.■

चौथी दुनिया के संपादक समन्वय डॉ. मनीष कुमार और आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे अश्विनी उपाध्याय के बीच हुई पूरी बातचीत देखने के लिए इस लिंक पर जाएं :-

http://www.chauthiduniya.com/2014/04/aam-aadmi-party-exposed-2.html

तमाम सर्वे भी इस ओर इशारा कर रहे हैं कि जदयू दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगा. ये हालात नीतीश की उलझनें और भी उलझा रहे हैं. ग़ौरतलब है कि सरकार के कामकाज से लेकर टिकट वितरण तक का जो सफर है, उसमें जदयू के कई नेताओं ने खुलकर, तो कई नेताओं ने पर्दे के पीछे से नीतीश कुमार को चुनौती देने का काम किया है.

16 मई को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद बिहार एवं झारखंड की राजनीति में भूचाल आना तय है. दलबदल क़ानून के कारण दो-तिहाई विधायकों के समर्थन के बिना पार्टी का टूटना मुश्किल है और उतने जदयू विधायकों का जुगाड़ तो और भी मुश्किल है, इसलिए गेम प्लान बदला जा रहा है. अगर लोकसभा चुनाव के नतीजे जदयू के पक्ष में ठीक नहीं निकले, तो सारा फोकस जदयू विधायक दल का नेता बदलने में लगा दिया जाएगा. अगर साठ विधायकों का भी जुगाड़ हो गया, तो फिर नेता बदल दिया जाएगा. इस कवायद में सरकार भी बनी रह जाएगी और सबसे बड़ी बात यह होगी कि जदयू का अस्तित्व बरकरार रहेगा. लेकिन, अगर नीतीश कुमार ठीकठाक सीटें लाने में कामयाब रहे, तो यह उनके लिए संजीवनी का काम करेगा और उनके ख़िलाफ़ सारी नाराज़गी धरी की धरी रह जाएगी.

डोल रहा नीतीश और हेमंत का सिंहासन

सरोज सिंह

बिहार एवं झारखंड में मतदान और चुनाव प्रचार का काम चरम पर है और जीत एवं हार के दावों से सत्ता के गलियारे गुलजार हैं. लेकिन, इस राजनीतिक कवायद के बीच एक और राजनीतिक कहानी की पटकथा लिखने की कोशिश बड़े ही गुप्त तरीके से जारी है और इस पटकथा के क्लाइमेक्स की अंतिम लाइनें इशारा कर रही हैं कि बिहार में नीतीश कुमार और झारखंड में हेमंत सोरेन का सिंहासन डोल रहा है. बिहार में अब तक जो वोट डाले गए हैं, उसका लब्बोलुआब यही है कि नीतीश कुमार की पार्टी यहां बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं करने जा रही है. बताया तो यह भी जा रहा है कि उनके गृहक्षेत्र नालंदा में भी जदयू को कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ रहा है. तमाम सर्वे भी इस ओर इशारा कर रहे हैं कि जदयू दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगा. ये हालात नीतीश की उलझनें और भी उलझा रहे हैं. ग़ौरतलब है कि सरकार के कामकाज से लेकर टिकट वितरण तक का जो सफर है, उसमें जदयू के कई नेताओं ने खुलकर, तो कई नेताओं ने पर्दे के पीछे से नीतीश कुमार को चुनौती देने का काम किया है.

मंत्री परवीन अमानुल्ला यह कहकर अलग हुईं कि सिस्टम ऐसा है कि काम करने की आज़ादी नहीं है. उधर चुनावी बयार में रेणू कुशवाहा, पूनम यादव एवं सुजाता कुमारी ने पार्टी का साथ छोड़ा, तो दल ने भी उन तीनों को निष्कासित कर दिया. अन्नू शुक्ला और छेदी पासवान ने भी पार्टी छोड़ दी है. जमुई में चुनावी मंच पर मंत्री नरेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री के सामने ही जिस तरह से हुंकार भरी, उससे साफ़ हो गया कि लोकसभा चुनाव में टिकट वितरण को लेकर सब ठीक नहीं है. नरेंद्र सिंह नहीं चाहते थे कि उदय नारायण चौधरी जमुई से जदयू के प्रत्याशी हों, लेकिन नीतीश ने उनकी भावना का सम्मान नहीं किया. इसलिए जब मंच पर उन्होंने उदय नारायण चौधरी की जमानत जब्त करा देने जैसी बात कही, तो किसी को आश्चर्य नहीं हुआ. रमई राम हाजीपुर से चुनाव लड़ना चाहते थे, पर उन्हें दरकिनार करके रामसुंदर दास को टिकट दिया गया. इसी तरह वृषिण पटेल का दावा वैशाली से दरकिनार कर दिया गया. उनकी नाराज़गी आगे क्या गुल खिलाएगी, उसे देखना दिलचस्प होगा. बताया जा रहा है कि छपरा से सलीम परवेज को टिकट देने से अली अनवर भी बहुत खुश नहीं हैं. इन सबसे अलग विधायकों का एक बड़ा तबका ऐसा भी है, जो सरकार में लगातार अपनी उपेक्षा और कुछ चाटुकारों की सलाह में आकर भाजपा से गठबंधन तोड़ने के फ़ैसले को पचा नहीं पा रहा है. बिहार में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं. इन चार सालों में विधायकों के हाथों में इतनी कम ताकत थी कि वे चाहकर भी अपने समर्थकों और क्षेत्र के लिए बहुत कुछ नहीं कर पाए. इसे लेकर क्षेत्र में उनके प्रति नाराज़गी है.

नीम पर करेला यह चढ़ गया कि भाजपा के साथ गठबंधन टूटने से क्षेत्र का चुनावी सामाजिक समीकरण ध्वस्त हो गया. जिताऊ सामाजिक-जातीय समीकरण ध्वस्त हो जाने से अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में जदयू के बहुत से विधायकों का चुनावी सफर बेहद कठिन हो गया है. दर्जनों विधायक ऐसे हैं, जिनका मौजूदा समीकरण में जीतना लगभग नामुमकिन है. ऐसे विधायकों की बेचैनी काफी बढ़ गई है. उन्हें सूझ नहीं रहा है कि वे क्या करें. लोकसभा चुनाव में अगर करारी हार हुई, तो हालात और भी बदतर हो जाएंगे. जानकार बताते हैं कि 16 मई को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद बिहार एवं झारखंड की राजनीति में भूचाल आना तय है. हाल यह है कि नतीजे आने से पहले ही नाराज़ विधायकों की गोलबंदी शुरू हो गई है. सूत्रों पर भरोसा करें, तो हाजीपुर और पटना में ऐसी कई बैठकें हो चुकी हैं. तैयारी 60 से 70 विधायकों को गोलबंद करने की है. कितने विधायक गोलबंद होंगे, यह तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तो साफ़ है कि मंशा यह है कि पार्टी के तौर पर जदयू को कोई आंच न आए. दलबदल क़ानून के कारण दो-तिहाई विधायकों के समर्थन के बिना पार्टी टूटना मुश्किल है और उतने जदयू विधायकों का जुगाड़ तो और भी मुश्किल है, इसलिए गेम प्लान बदला जा रहा है.

अगर लोकसभा चुनाव के नतीजे जदयू के पक्ष में ठीक नहीं निकले, तो सारा फोकस जदयू विधायक दल का नेता बदलने में लगा दिया जाएगा. अगर साठ विधायकों का भी जुगाड़ हो गया, तो फिर नेता बदल दिया जाएगा. इस कवायद में सरकार भी बनी रह जाएगी और सबसे बड़ी बात यह होगी कि जदयू का अस्तित्व बरकरार रहेगा. जानकार बताते हैं कि अगर नतीजे खराब रहे, तो इस प्लान के सफल होने की संभावना बढ़ जाएगी. भाजपा के लिए यह अच्छी स्थिति होगी कि जदयू विधायक दल का नेता नीतीश कुमार की जगह कोई दूसरा बन जाए. भाजपा फिर आगे की राजनीति की संभावना भी तलाश सकती है. कुछ जानकारों का कहना है कि अव्वल तो ऐसी स्थिति आने की संभावना कम है और अगर ऐसे हालात बने भी, तो नीतीश कुमार विधानसभा भंग करने की सिफारिश करके चुनाव में जाने का फ़ैसला कर सकते हैं, लेकिन यह तब होगा, जब लोकसभा चुनाव के नतीजे नीतीश कुमार के पक्ष में बेहद खराब होंगे. वहीं अगर नीतीश कुमार ठीकठाक सीटें लाने में कामयाब रहे, तो यह उनके लिए संजीवनी का काम करेगा और उनके ख़िलाफ़ सारी नाराज़गी धरी की धरी रह जाएगी. ■

feedback@chauthiduniya.com

टीएमसी के हाथ में सरकार बनाने की चाबी

लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद झारखंड में एक बार फिर प्रदेश सरकार पर संकट के बादल आने वाले हैं. 81 सदस्यीय विधानसभा में राजद के 4, जेएमएम के 18 और कांग्रेस के 16 विधायक हैं. गठबंधन सरकार के ख़िलाफ़ सबसे पहले बगावत का बिगुल फूंकने वाले पूर्व मंत्री ददई दुबे ने इस्तीफा दिया और फिर सरकार से निकाले जाने के बाद मंत्री चंद्रशेखर दुबे ने कांग्रेस से भी इस्तीफा दे दिया. तृणमूल कांग्रेस में शामिल होकर धनबाद सीट से चुनाव मैदान में उतरे दुबे ने बाद में विधानसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया. बंधु तिर्की, चमरा लिंडा एवं ददई दुबे जैसे नेता इस समय तृणमूल कांग्रेस में हैं. लोकसभा चुनाव के नतीजे आने वाले दिनों में राज्य में तृणमूल कांग्रेस की ताकत और राजनीति तय करेंगे. लोकसभा चुनाव में बंधु तिर्की, चमरा लिंडा एवं ददई दुबे जैसे नेताओं के प्रदर्शन पर पार्टी का भविष्य टिका है.

लोकसभा चुनाव के नतीजे ही आगामी विधानसभा चुनाव का प्लॉट भी तय करेंगे. लोकसभा चुनाव में अगर तृणमूल कांग्रेस ने सम्मानजनक प्रदर्शन किया, तो विधानसभा चुनाव में भी कोण बनाने की कोशिश होगी. झारखंड पार्टी के एनोस एक्का और जय भारत समानता पार्टी के मधु कोड़ा ने विधानसभा चुनाव को देखते हुए ही दांव लगाया है. अगर लोकसभा चुनाव में इन नेताओं ने अपनी-अपनी सीट पर जलवा दिखाया, तो विधानसभा चुनाव में भी इसका असर दिखेगा. आने वाले समय में इन दलों के नेता अपना पूरा ध्यान विधानसभा चुनाव पर फोकस करेंगे. उधर, सरकार कैसे बचेगी और कैसे गिरेगी, इसकी पूरी रणनीति भी विपक्षी दलों ने बना ली है. अब देखना यह होगा कि कौन किसे राजनीति में पस्त करता है. *-मंगलानंद*

फोटो-*प्रभात पाण्डेय*

लगभग एक साल पहले से मोदी के उत्तर प्रदेश की किसी सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही थीं. माना जा रहा था कि ऐसा करने से सबसे ज़्यादा सीटों वाले उत्तर प्रदेश के भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश आ जाएगा. इसीलिए पार्टी के थिंक टैंक ने मोदी को उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ाने का निर्णय लिया.

दो नावों की सवारी, करदाताओं पर भारी

नवीन चौहान

भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र दामोदर भाई मोदी 16वीं लोकसभा के लिए हो रहे चुनाव में दो निर्वाचन क्षेत्रों, वड़ोदरा और वाराणसी से चुनाव मैदान में उतरे हैं. वड़ोदरा सीट से ज़्यादा लोगों की नज़र वाराणसी सीट पर है. वह इस चुनाव में दो सीटों से लड़ने वाले एकमात्र शख्स नहीं हैं. उत्तर प्रदेश में भाजपा को चुनौती दे रही सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव भी दो लोकसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ रहे हैं. वह अपनी पारंपरिक सीट मैनपुरी के अलावा मुस्लिम बाहुल्य आजमगढ़ से भी चुनाव लड़ रहे हैं. दोनों की अपनी-अपनी राजनीतिक समझ है.

लगभग एक साल पहले से मोदी के उत्तर प्रदेश की किसी सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही थीं. माना जा रहा था कि ऐसा करने से सबसे ज़्यादा सीटों वाले उत्तर प्रदेश के भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश आ जाएगा. इसीलिए पार्टी के थिंक टैंक ने मोदी को उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ाने का निर्णय लिया. उधर मुलायम सिंह की मंशा यह थी कि प्रदेश के मुस्लिम मतदाताओं को किसी तरह अपनी पार्टी के पक्ष में किया जाए. किसकी रणनीति सफल साबित हुई, यह तो 16 मई को मतगणना के बाद मालूम होगा, लेकिन एक बात पूरी तरह साफ़ है कि अपने राजनीतिक करियर को किसी भी प्रकार की अनिश्चितता से बचाने के लिए पार्टियों के मुखिया या प्रमुख नेता इस नियम का सेफ्टी वाल्व की तरह उपयोग करते रहे हैं, जो अंततः देश की आम जनता की जेब पर भारी पड़ता है.

अनुमान है, इस बार के आम चुनाव को आयोजित करने में अनुमानित खर्च 3500 करोड़ रुपये आएगा. इस हिसाब से एक सीट पर चुनाव का कुल खर्च लगभग 64 करोड़ रुपये आएगा. नेताओं की सहूलियत का खामियाजा करदाताओं को ही भुगतना पड़ता है. दो या उससे ज़्यादा सीटों से चुनाव लड़ने का इतिहास बहुत पुराना है. भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जनसंघ के युवा कार्यकर्ता के रूप में वर्ष 1957 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के तीन लोकसभा क्षेत्रों बलरामपुर, मथुरा एवं लखनऊ से चुनाव मैदान में उतरे थे. उन्हें बलरामपुर से जीत हासिल हुई थी, लखनऊ में वह दूसरे स्थान पर रहे थे, जबकि मथुरा में उनकी जमानत जब्त हो गई थी. अटल बिहारी वाजपेयी का एक से ज़्यादा सीटों से लोकसभा चुनाव लड़ने का सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं हुआ. उन्होंने 1991 में मध्य प्रदेश के विदिशा और उत्तर प्रदेश के लखनऊ से चुनाव लड़ा और दोनों ही सीटों पर उन्हें जीत हासिल हुई. 1996 में भी उन्होंने लखनऊ और गांधी नगर से लोकसभा चुनाव लड़ा और दोनों सीटों पर विजयी हुए.

देश में सबसे ज़्यादा समय तक शासन करने वाली कांग्रेस में भी यह परंपरा रही है. पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 1980 में आंध्र प्रदेश की मेंडक और उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से लोकसभा चुनाव लड़ी थीं. जनता पार्टी की सरकार के धराशायी हो जाने के बाद इंदिरा गांधी को संदेह था कि कहीं उन्हें 1977 के चुनाव की तरह मुंह की न खानी पड़े. 1977 में वह इलाहाबाद से चुनाव मैदान में उतरी थीं, जिसमें उन्हें विजयी घोषित कर दिया गया था, लेकिन राज नारायण ने हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में इंदिरा गांधी के निर्वाचन को चुनौती दी. हाईकोर्ट ने राज नारायण के पक्ष में फ़ैसला दिया और इंदिरा गांधी का निर्वाचन निरस्त कर दिया. इसी वजह से इंदिरा गांधी ने 1980 का चुनाव दो सीटों से लड़ने का फ़ैसला किया. हालांकि, वह दोनों जगहों से विजयी हुईं और सत्ता पर एक बार फिर काबिज हो गईं.

वर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी दो बार दो सीटों से लोकसभा चुनाव लड़ चुकी हैं. 1999 में वह उत्तर प्रदेश की अमेठी और कर्नाटक की बेल्लारी सीट से लोकसभा चुनाव लड़ी थीं और दोनों जगहों पर जीत हासिल की थी. बेल्लारी की सीट उन्होंने

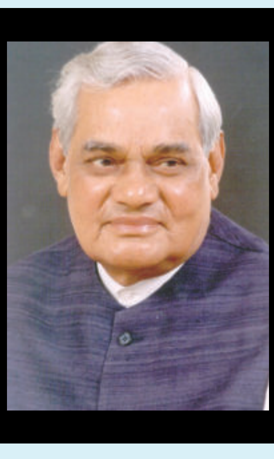

रिक्त कर दी थी. 2004 में यह कहानी फिर दोहराई गई और सोनिया गांधी अपने परिवार की परंपरागत सीटों अमेठी एवं रायबरेली से चुनाव मैदान में उतरीं. उन्हें दोनों जगह जीत हासिल हुई. उन्होंने अमेठी सीट खाली कर दी, जिसके उपचुनाव में राहुल गांधी ने पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा और सांसद निर्वाचित हुए. मुलायम सिंह 1999 के चुनाव में संभल और कन्नौज सीटों पर ताल ठोंकते नज़र आए. दोनों ही सीटों पर उन्हें जीत हासिल हुई. उनके द्वारा कन्नौज सीट खाली करने के बाद अखिलेश वहां से चुनाव लड़े और जीत हासिल कर पहली बार लोकसभा पहुंचे. अखिलेश ने 2009 के आम चुनाव में कन्नौज और फिरोज़ाबाद सीट पर जीत हासिल की. फिर उन्होंने फिरोज़ाबाद सीट खाली कर दी.

क्या कहता है क़ानून

पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट-1951 की धारा 33 (7) के अनुसार, वर्तमान में कोई भी व्यक्ति दो सीटों से चुनाव लड़ सकता है. यदि वह दोनों सीटों से चुनाव जीत जाता है, तो उसे इसी एक्ट की धारा 70 के अनुसार, 10 दिनों के अंदर कोई एक सीट खाली करनी होगी. 1996 में क़ानून में संशोधन के बाद ही दो सीटों पर लड़ने का प्रावधान आया. इससे पहले कोई भी व्यक्ति एक साथ कई सीटों से चुनाव लड़ सकता था. संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप के अनुसार, देश के राजनीतिज्ञ इस प्रावधान के माध्यम से चुनावी प्रक्रिया का दुरुपयोग कर रहे हैं. इस प्रावधान का उपयोग उम्मीदवार

सांसद बनने की राह में आ रहे जोखिम को कम करने के लिए करते हैं. यह एक बीमा पॉलिसी की तरह है, जिसका प्रीमियम देश की जनता को देना पड़ता है.

चुनाव आयोग का रुख

2004 में चुनाव आयोग ने दो जगहों से चुनाव लड़ने वाला प्रावधान ख़त्म करने की अनुशंसा की थी. 2010 में केंद्रीय चुनाव आयोग से क़ानून एवं न्याय मंत्रालय की कोर कमेटी ऑन इलेक्ट्रोरल रिफॉर्म्स ने इस संबंध में सुझाव मांगे थे. जवाब में चुनाव आयोग ने दो जगहों से चुनाव लड़ने के प्रावधान का विरोध किया था और इसे ख़त्म करने की अनुशंसा की थी. इस कमेटी की रिपोर्ट धीरे से ठंडे बस्ते में डाल दी गई. जाहिर है, राजनीतिक दलों में ऐसे सकारात्मक बदलाव करने की इच्छाशक्ति नहीं है. यह प्रावधान बनाए रखने का कोई भी तर्कसंगत कारण नहीं है. चुनाव आयोग ने यह भी कहा था कि यदि कोई उम्मीदवार दो जगहों से चुनाव जीतता है, तो उसे खाली की गई सीट पर उपचुनाव कराने के लिए आवश्यक खर्च सरकार के खजाने में जमा करा देना चाहिए. लोकसभा के लिए यह धनराशि 10 लाख और विधानसभा के लिए 5 लाख रुपये होगी. चुनाव आयोग के इस सुझाव पर उस समय एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई, लेकिन इस मुद्दे पर पार्टियों के बीच एक राय नहीं बन पाई. बीजू जनता दल के सांसद विजयंत जय पांडा का कहना है कि किसी भी व्यक्ति को कितनी भी सीटों पर चुनाव लड़ने की अनुमति होनी चाहिए और जीते गए उम्मीदवार द्वारा बाकी सीटें खाली करने पर वहां दूसरे नंबर पर रहे उम्मीदवार को विजेता घोषित कर देना चाहिए. इससे खर्च में कमी आएगी और उपचुनाव आयोजित करने की ज़रूरत नहीं रहेगी. ■

feedback@chauthiduniya.com

बेबस प्रधानमंत्री की व्यथा

इसमें कोई शक नहीं कि देश की जनता प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के विषय में अच्छी राय नहीं रखती. इस दुनिया में कई लोग कम बोलते हैं, उनमें से एक हमारे प्रधानमंत्री भी हैं. जनता को इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बतौर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह देश की सेवा करने की बजाय सोनिया और राहुल गांधी के आदेशों का पालन करें, यह उन्हें शोभा नहीं देता. पिछले दस वर्षों में मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री पद की गरिमा को जिस तरह धूमिल किया है, उसे भुला पाना शायद संभव नहीं होगा.

अभिषेक रंजन सिंह

बचपन में एक कहानी सुनी थी. किसी गांव में बरगद का एक पुराना वृक्ष था, जिसके नीचे एक सांप रहता था. वह सांप गांव में रहने वाले लोगों और जानवरों को डंसता था. गांव वाले उस सांप से काफी परेशान थे. एक दिन उस गांव में एक साधु आया. गांव वालों ने साधु से मिलकर अपनी समस्या बताई. वह साधु सांप से मिलने पहुंचा. साधु ने सांप से कहा, तुमसे लोग भयभीत हैं, इसलिए तुम किसी को मत डंसो. सांप ने साधु की बात मान ली और उसने लोगों को डंसना छोड़ दिया. कई महीने बाद वह साधु फिर उसी गांव में पहुंचा, तो उसने देखा कि बरगद के उस वृक्ष के नीचे काफी भीड़ लगी है और वह सांप घायल अवस्था में पड़ा हुआ है. साधु ने उस सांप से पूछा, तुम्हारी यह हालत किसने बनाई? सांप ने कहा, महात्मन, आपने ही तो मुझे डंसने से मना किया था. साधु ने कहा, हां, मैंने डंसने से मना किया था, लेकिन फुंफकारने से नहीं. डंसना हिंसा है, लेकिन फुंफकारना अपने रक्षार्थ ज़रूरी है. अगर तुमने ऐसा किया होता, तो तुम्हारी हालत ऐसी नहीं होती.

आज प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की हालत उसी सांप की तरह है, जिसने फुंफकारना भी छोड़ दिया है. प्रधानमंत्री मनमोहन को देखकर अब जनता को आक्रोश नहीं आता, बल्कि उनके ऊपर लोगों को दया आने लगी है. देश की जनता ने मनमोहन सिंह के कई उपनाम भी रखे हैं. कोई उन्हें हुक्म का गुलाम कहता है, तो कोई रोबोट, कोई मोम का पुतला, तो कोई उन्हें बेजुबान कहता है. हालांकि जनता का एक बड़ा हिस्सा ऐसा भी है, जो मनमोहन सिंह के लिए इससे भी तल्ख बातें कहता है. निश्चित रूप से किसी व्यक्ति के विषय में ऐसी टिप्पणियां करना अभद्रता माना जाता है. वह भी उस व्यक्ति के बारे में, जो पिछले दस वर्षों से इस देश का प्रधानमंत्री है.

वैसे यहां सवाल यह उठता है कि आख़िर देश की करोड़ों जनता प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के विषय में ऐसी नकारात्मक राय क्यों रखती है. इसका सीधा जवाब है कि प्रधानमंत्री जनता की कसौटी पर खरे नहीं उतर सके. पिछले दिनों प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से जुड़ीं दो किताबें प्रकाशित हुईं. एक किताब संजय बारू ने लिखी है, जो संप्रग प्रथम सरकार में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रह चुके हैं. दूसरी किताब पूर्व कोयला सचिव पी सी पारख ने लिखी है. इन किताबों में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की लाचारी और नाकामियों के बारे में तफ्सील से लिखा गया है. प्रधानमंत्री के बारे में इतनी बातें लिखी गईं, लेकिन खुद मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने इस बारे में कोई बयान नहीं दिया. हालांकि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार पंकज पचौरी ने उनका बचाव करते हुए कहा कि पिछले दस वर्षों में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में देश ने उम्मीद से कहीं ज़्यादा प्रगति की है. उनके मुताबिक़, अपने दस वर्षों के कार्यकाल में प्रधानमंत्री ने एक हज़ार से अधिक भाषण दिए हैं. यूपीए सरकार की तारीफ़ करते हुए उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार में ग़रीबी उन्मूलन के साथ-साथ ग्रामीण विकास और रोज़गार की दिशा में भी कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं. पंकज पचौरी ने भले ही प्रधानमंत्री का बचाव किया हो, लेकिन उनकी बातों से देश की जनता कतई इत्तेफाक नहीं रखती. वैसे भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सलाहकार पंकज पचौरी से यही उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि वह प्रधानमंत्री कार्यालय में नौकरी करते हैं. प्रधानमंत्री बेशक निकम्मे और लाचार हों, इससे उन्हें कोई फर्क़ नहीं पड़ता. उनका काम है अपने प्रधानमंत्री का बचाव करना, क्योंकि इसीलिए उन्हें अच्छी-ख़ासी तनख्वाह मिलती है.

चौथी दुनिया के पाठकों को हम यह जानकारी देना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार पंकज पचौरी एनडीटीवी न्यूज चैनल में पत्रकार रह चुके हैं. एनडीटीवी में रहते हुए पंकज पचौरी ने कांग्रेस और गांधी परिवार की हिमायत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी. गांधी परिवार की कृपा से उन्हें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का मीडिया सलाहकार बनाया गया. इसकी एवज़ में पंकज पचौरी को लालबत्ती युक्त सरकारी गाड़ी, लुटियंस जोन में एक बंगला और लाखों रुपये महीने की सैलरी मिलने लगी. कहने का आशय यह कि पंकज पचौरी ने जिस तरह प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का बचाव किया है, उसमें कोई नई बात नहीं है, क्योंकि वह भी नौकरी कर रहे हैं. वही नौकरी, जो मनमोहन सिंह पिछले दस वर्षों से कर रहे हैं.

बकौल पंकज पचौरी कि मनमोहन सिंह ने पिछले दस वर्षों में एक हज़ार भाषण दिए हैं, उसी तरह हास्यास्पद है, जैसे कोई यह कहे कि रेगिस्तान में पिछले कई दिनों से भारी बारिश हो रही है और वहां चारों तरफ़ हरियाली देखी जा सकती है. असल में पंकज पचौरी के इस दावे का लोग मजाक उड़ा रहे हैं. वह मनमोहन सिंह को एक अच्छा वक्ता और मीडिया फ्रेंडली बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के समय कांग्रेस की किसी जनसभा को मनमोहन सिंह संबोधित नहीं कर रहे हैं. इतना ही नहीं, मनमोहन सिंह की एक अदद पोस्टकार्ड आकार की तस्वीर भी किसी पोस्टर या होर्डिंग में कांग्रेसी उम्मीदवार नहीं लगा रहे हैं, जबकि नई सरकार चुने जाने तक वह देश के प्रधानमंत्री हैं. यह लिखते हुए मुझे भी तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि इस देश में दिवंगत नेताओं की तस्वीर भी लगाने की परंपरा रही है, लेकिन कांग्रेस ने तो मनमोहन सिंह को ज़िंदा रहते हुए उन्हें भुला दिया. ख़ैर, इसे कांग्रेस पार्टी की मजबूरी भी कह सकते हैं, क्योंकि पार्टी नेताओं को यह बखूबी पता है कि अगर किसी रैली में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मौजूद रहेंगे और कोई भाषण देंगे, तो इससे कांग्रेस का वोट बढ़ेगा नहीं, बल्कि उसमें गिरावट आ जाएगी.

मनमोहन सिंह अपनी इस दुर्दशा के लिए स्वयं ज़िम्मेदार हैं. बेशक सोनिया गांधी की कृपा से वह प्रधानमंत्री बने, लेकिन उन्हें कम से कम इस बात का भान होना चाहिए था कि देश की जनता की नज़रों में प्रधानमंत्री का पद काफ़ी बड़ा होता है. देश की जनता अपने प्रधानमंत्री से यह अपेक्षा करती है कि इस पद पर बैठा शख्स गंभीर फ़ैसले लेने में सक्षम हो, वह जनता से रूबरू हो, लेकिन अफसोस! पिछले दस वर्षों में मनमोहन न तो देश के बेहतर प्रधानमंत्री बन सके और न एक अच्छे अर्थशास्त्री. ■

arsingh@chauthiduniya.com

कर्नाटक में पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा और उनके बेटे एचडी कुमारास्वामी इस पार्टी के मुख्य चेहरे हैं. 2013 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा से अलग होकर पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने अपनी एक अलग पार्टी बनाई थी, कर्नाटक जनता पक्ष. हालांकि, लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने अपनी पार्टी का विलय भाजपा में कर लिया है.

लोकसभा चुनावों में दक्षिण भारत की राजनीति

चंदन कुमार

देश में 16वीं लोकसभा का चुनाव अपने पड़ाव की ओर आगे बढ़ रहा है. एक तरफ भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के रथ पर सवार चुनावों में विजय की नई गाथा लिखने को बेताब है, तो दूसरी ओर कांग्रेस पिछले 10 वर्षों के शासन काल का हिसाब-किताब के जरिए अच्छे नतीजों की उम्मीद कर रही है. चुनावों की इस गुणा-गणित को हम दक्षिण भारत के नजरिए से देखें, तो दोनों प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियां कांग्रेस और भाजपा के लिए दक्षिण भारत में पाने के लिए कम और खोने के लिए अधिक है. हालांकि, दोनों दल वहां की क्षेत्रीय पार्टियों से गठबंधन के जरिए चुनावी रणनीति में जीत की किरण देख रहे हैं. आइए जानते हैं कि दक्षिण भारत की राजनीति में कौन-से दल और नेता मुख्य भूमिका में हैं. दक्षिण भारत की राजनीति में आमतौर पर राष्ट्रीय पार्टियों कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षा क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा अधिक होता है. हालांकि, भाजपा और कांग्रेस दोनों ने गठबंधन के जरिए कुछ सफलता हासिल की है. उत्तर भारत में जहां क्षेत्रों का काफी महत्व होता है, वहीं दक्षिण भारत में जाति, भाषा और जातीयता की भी काफी अहमियत है.

आंध्रप्रदेश

आंध्रप्रदेश में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं. राजनीतिक दलों की बात करें, तो छोटी-बड़ी कुल 30 से अधिक पार्टियां हैं. हर पार्टी का अपने क्षेत्र विशेष में एक खास दबदबा है. हालांकि, इन सभी में पांच या छह पार्टियां ही ऐसी हैं, जो प्रदेश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. इन पार्टियों में कांग्रेस, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन, तेलुगूदेशम पार्टी, तेलंगाना राष्ट्र समिति, बहुजन कम्युनिस्ट पार्टी, हैदराबाद स्टेट प्रजा पार्टी, जय तेलंगना पार्टी, लोकसत्ता पार्टी, नव तेलंगना पार्टी, मन्ना पार्टी (इंडिया), पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट (हैदराबाद), तेलंगना कम्युनिस्ट पार्टी, तेलंगाना जनता पार्टी, लेबर पार्टी, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी प्रमुख हैं.

साल 1953 में आंध्रप्रदेश के गठन के बाद यहां लगभग 30 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही. कांग्रेस पार्टी के गढ़ में पहली सेंध 1980 में लगी. दरअसल, तेलुगू फिल्मों के महानायक नंदमुरली तारक रामाराव (एनटीआर) ने आंध्रप्रदेश में क्षेत्रीय पार्टी तेलुगूदेशम पार्टी का गठन किया और 1983 का विधानसभा चुनाव भारी बहुमत से जीता. वे आंध्रप्रदेश में पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने. आज आंध्रप्रदेश और तेलंगाना की राजनीति में तेलुगूदेशम की अहम भूमिका है. आंध्रप्रदेश के चुनावी मैदान में आज कांग्रेस के अलावा वाइएसआर कांग्रेस, तेलंगाना राष्ट्र समिति, भाजपा, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन जैसे दल भी मैदान में हैं. हालांकि, जानकारों की मानें तो हालिया घटनाक्रम के कारण राज्य में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में इस बार क्षेत्रीय दल को ही सफलता मिलेगी. आंध्रप्रदेश के विभाजन का विरोध करने वाले वाइएसआर कांग्रेस को आंध्रप्रदेश में बड़ी सपलता की उम्मीद की जा रही है, वहीं तेलंगाना क्षेत्र में टीआरएस को सफलता की बात की जा रही है. आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री एन किरण रेड्डी ने राज्य के एकीकरण के मुद्दे पर पार्टी से इस्तीफा देकर अपनी नई पार्टी समैक्यआंध्र पार्टी बनाई. हालांकि, उन्होंने चुनाव न लड़ने का फैसला किया है. उधर, पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी के बेटे जगन मोहन रेड्डी ने भी नेतृत्व विवाद के बाद कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई वाईएसआर-कांग्रेस. आंध्रप्रदेश में जगनमोहन रेड्डी भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए बहुत बड़ी चुनौती माने जा रहे हैं. वहीं, 10 वर्षों से राज्य की सत्ता से बाहर रहने वाले चंद्रबाबू नायडू के हाथों में तेलुगूदेशम पार्टी की कमान है और उन्होंने भाजपा के साथ मिलकर राज्य में गठबंधन किया है. तेलंगाना राष्ट्र समिति की बात करें, तो साल 2001 में के चंद्रशेखर राव ने इसका गठन किया था और वे इसके अध्यक्ष हैं. तेलंगाना क्षेत्र में उनका खासा प्रभाव माना जा रहा है. वहीं, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन की राजनीति को भी यहां खारिज नहीं किया जा सकता है. असदुद्दीन ओवैशी इसके चेयरपर्सन हैं और लोकसभा में भी वे ही अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं. हैदराबाद क्षेत्र में ओवैशी का प्रभाव अच्छा खासा माना जाता है. इसकी स्थापना 1927 में हुई थी.■

कर्नाटक

कर्नाटक में लोकसभा की कुल 28 सीटें हैं. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शुमार प्रदेश की प्रमुख पार्टियों में शुमार होता है. कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में जी परमेश्वर, नंदन निलेकणि, वीरप्पा मोइली, केएच मुनियप्पा, धरम सिंह इन चुनावों में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं. भारतीय जनता पार्टी दूसरी बड़ी पार्टी है और प्रह्लाद जोशी, बीएस येदियुरप्पा, श्रीरामुलु, अनंत कुमार, सदानंद गौड़ा की भूमिका इन चुनावों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है. जनता दल (सेक्युलर) तीसरी प्रमुख पार्टी है और प्रदेश में इसकी अगुवाई पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा कर रहे हैं. जेडी (एस) 1999 में जनता दल से टूटकर बनी थी. कर्नाटक की राजनीति में जनता दल ने जितनी सफलता हासिल की, उतनी उसे केंद्रीय राजनीति में नहीं मिली. भाजपा और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टियों की भी अच्छी-खासी पैठ यहां रही है. फिलहाल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, तो इससे पहले भाजपा सत्ता में थी. कर्नाटक के मुख्य राजनीक दलों की बात करें, तो भाजपा और कांग्रेस के बाद नाम आता है, जनता दल (एस) का. पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा और उनके बेटे एचडी कुमारास्वामी इस पार्टी के मुख्य चेहरे हैं. 2013 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा से अलग होकर पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने अपनी एक अलग पार्टी बनाई थी, कर्नाटक जनता पक्ष. हालांकि, लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने अपनी पार्टी का विलय भाजपा में कर लिया है. इसके अलावा कर्नाटक मक्काल पक्ष और सर्वोदय कर्नाटक पक्ष जैसी पार्टियां भी राज्य में सक्रिय हैं, लेकिन लोकसभा चुनावों में इन्हें खास फायदा नहीं होने वाला है. जानकारों का मानना है कि यहां दलित, आदिवासी, ईसाई और पिछड़े वर्ग की संख्या 45 प्रतिशत से भी अधिक है और राजनीतिक दलों की निगाह इन वोटों पर अधिक रहती है. हालांकि, यहां की राजनीति में लिंगायत और वोक्कालिग्स दो जातीय समूहों का दबदबा अधिक है.■

तमिलनाडु

39 लोकसभा सीटों वाले तमिलनाडु में दो प्रमुख क्षेत्रीय दलों का ही कब्जा रहा है. ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कषगम (एआईएडीएमके) और द्रविड़ मुनेत्र कषगम (डीएमके). भारत में क्षेत्रीय दलों का उद्भव एक तरह से 1967 में उस वक्त हुआ, जब तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के संस्थापक सीएन अन्नादुरई मुख्यमंत्री बने. हालांकि, 1972 में एमजी रामचंद्रन की अगुवाई में द्रमुक से टूटकर एक और नई पार्टी बनी ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक). तमिलनाडु के दोनों क्षेत्रीय पार्टियां राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. द्रमुक के नेता एम करुणानिधि और अन्नाद्रमुक की जे जयललिता का ही वर्चस्व राज्य की राजनीति में देखने को मिलता है. तमिलनाडु की राजनीति मेंकरुणानिधि के बेटे एमके स्टालिन और अलागिरि की भी खास भूमिका है. लेकिन, पिछले दिनों करुणानिधि ने अलागिरि को पार्टी से निकाल दिया और इसका असर लोकसबा चुनावों में देखने को मिल सकता है. इसके अलावा विदुथलई चिरुथैगल काची पार्टी और उनके नेता टी थिरुमवल्लवन, एमडीएमके के वाइको, कांग्रेस के केवी थांगकाबालु, पीएमके के अंबुमणि रामदॉस, सीपीआई (एम) के जी रामाकृष्णन और सीपीआई के था पंडियन की भूमिका राज्य की राजनीति में अहम मानी जाती है. ■

केरल

केरल में लोकसभा की कुल 20 सीटें हैं और यहां की राजनीति में दो प्रमुख गठबंधन दलों का दबदबा रहता है. एक, कांग्रेस की अगुवाई वाला यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) और दूसरा, सीपीआई (एम) की अगुवाई वाला लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ). कांग्रेसी नेता के करुणाकरण ने 1970 में यूडीएफ गठबंधन बनाया था. फिलहाल कांग्रेस पार्टी की कमान ओमान चांडी की हाथों में है. यहां के मतदाताओं में मुसलमानों और ईसाइयों को यूडीएफ का वोटबैंक माना जाता है, तो पिछड़ा समुदाय आमतौर पर एलडीएफ के कोर वोटर माने जाते हैं. पश्चिम बंगाल के बाद केरल वामपंथियों का दूसरा बड़ा गढ़ माना जाता है. केरल में कांग्रेस की अगुवाई वीएम सुधीरन कर रहे हैं. यूडीएफ गठबंधन में शामिल दलों और संगठनों में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, केरल कांग्रेस, सोशलिस्ट जनता (डेमोक्रेटिक) पार्टी, केरल कांग्रेस (बी), रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (बेबी जॉन), केरल कांग्रेस (जैकब), सीएमपी हैं. वहीं, एलडीएफ गठबंधन की अगुवाई वामपंथी नेता वीएस अच्युतानंदन कर रहे हैं. ■

दक्षिण भारतीय फिल्म और राजनीति

राजनीति और फिल्म का गहरा नाता है. अगर उत्तर भारत में देखें, तो सुनील दत्त से लेकर, अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, गोविंदा, जया बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, राज बब्बर, हेमा मालिनी, जयाप्रदा जैसे अभिनेताओं ने राजनीति में कदम रखा. लेकिन, इनमें से अधिकांश अभिनेता फिल्मों की तरह राजनीति में उतने सुपरहिट नहीं है, जितने दक्षिण भारतीय अभिनेता. दक्षिण भारत इस लिहाज से भी अलग है कि यहां कई अभिनेताओं ने अपनी अलग पार्टी की शुरुआत की और वे दक्षिण की सत्ताधारी या विपक्षी पार्टी के रूप में स्थापित हैं. इसका प्रत्यक्ष प्रमाण एमजी रामचंद्रन और एनटी रामाराव हैं. तमिलनाडु में एमजी रामचंद्रन फिल्मों से जब राजनीति में आए, तो वे पहले डीएमके के सदस्य बने और 1972 में उन्होंने पार्टी छोड़ अपनी अलग पार्टी अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (एडीएमके) बनाई. आंध्रप्रदेश में एनटी रामाराव ने 1982 में फिल्मों से राजनीति में कदम रखा और तेलुगूदेशम पार्टी बनाई. पार्टी बनाने के बाद हुए विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने भारी बहुमत हासिल किया और वे 1983 से 1995 तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे.

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शुरुआती दिनों में पूरे भारत में कांग्रेस और जनता पार्टी ने राज्यों में शासन किया. पूरे भारत को देखें, तो दक्षिण भारतीयों को द्रविड़ और उत्तर भारतीयों को आर्य माना जाता है. शुरुआत में दक्षिण भारतीय पार्टियों का उदय इसी भेदभाव, भाषा और पिछड़ों के आरक्षण के मुद्दे पर हुआ. तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कषगम यानी द्रमुक के गठन का आधार भी यही था. अरिगनार अन्ना के नेतृत्व में यह बना और कई लोगों ने इसका समर्थन किया. उन्हीं समर्थकों में एक नाम था, तमिल फिल्मों के स्क्रीनप्ले राइटर एम करुणानिधि. दरअसल, वे एक पत्रकार व राजनेता थे, जिन्होंने फिल्मों में भी काम करना शुरू किया था. एमजी रामचंद्र (एमजीआर) और करुणानिधि बहुत अच्छे मित्र थे. करुणानिधि की वजह से ही उन्होंने फिल्मों से राजनीति में कदम रखा. उन दिनों एमजीआर फिल्मों के पर्दे पर जब आ जाते, तो लोगों में गजब की हलचल हुआ करती थी. राजनीति में भी उन्होंने अपनी इस बेइंतहा लोकप्रियता का बखूबी इस्तेमाल किया. हालांकि, बाद में डीएमके और करुणानिधि से असहमति के बाद उन्होंने अपनी नई पार्टी अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (एडीएमके) बनाई. राजनीति पर आधारित फिल्मों से एमजीआर को राजनीति में नई ऊंचाइयों पर पहुंचने का सुनहरा अवसर मिला. तमिलनाडु में जो प्रभाव एमजीआर का था, वही असर आंध्रप्रदेश में एनटीआर का था. दक्षिण भारतीय फिल्मों के दो दिग्गजों ने फिल्मों के साथ-साथ राजनीति में भी वो मुकाम हासिल किया, जो आज किसी भी अभिनेता के लिए आसान नहीं है. विजयकांत और चिरंजीवी ने भी अपनी पार्टी बनाई. चिरंजीवी ने प्रजा राज्यम पार्टी बनाई और बाद में कांग्रेस में उसका विलय कर दिया. विजयकांत ने तमिलनाडु में डीएमडीके (देसीय मुरपोक्कु द्रविड़ कषगम) बनाई और उसने इन चुनावों में एनडीए के साथ गठबंधन किया है. तमिलनाडु में ही जे जयललिता फिल्मों में अभिनेत्री रही हैं और रुपहले पर्दे में एमजीआर और उनकी जोड़ी काफी पसंद की जाती थी. दरअसल, दक्षिण भारत के लोगों में फिल्मों और अपने अभिनेताओं के प्रति जुनून होता है. दक्षिण भारतीय अभिनेताओं के प्रशंसकों और समर्थकों की तादाद काफी अधिक होती है, इतिहास में उनका गहरा विश्वास होता है और यही कारण है कि वे राजनीति में आने से हिचकिचाते नहीं हैं. ■

> पश्चिम बंगाल की एथलीट ज्योतिर्मयी सिकदर 2004 में सीपीआई(एम) के टिकट पर पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ीं और जीत दर्ज कराई.

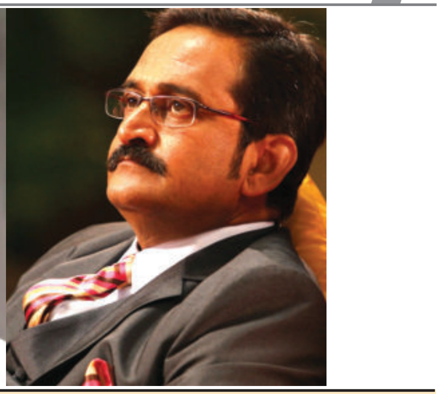

राजनीतिक चकाचौंध में फिल्मी सितारे

फिल्मी सितारों का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोलता है. अपनी लोकप्रियता को भुनाने में ये सितारे भी पीछे नहीं रहते. 2014 के लोकसभा चुनाव में कई पार्टियों के टिकट पर फिल्मी सितारे चुनाव लड़ रहे हैं. पार्टियां कई बार अपनी जीत के लिए इन्हें एप्रोच करती हैं तो इन सितारों को भी पॉवर और पैसा आकर्षित करता है.

प्रियंका प्रियम तिवारी

ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में फिल्मस्टार्स राजनीति की तरफ रुख कर रहे हैं, अधिकतर देशों में फिल्मस्टार्स अपनी लोकप्रियता के दम पर राजनीति में कदम रख रहे हैं. कुछ स्टार्स ने थोड़े दिन राजनीति करने के बाद तौबा कर ली तो कुछ स्टार्स अच्छे राजनेता साबित हुए. अमेरिका की राजनीति में हॉलीवुड के फिल्मी सितारे मौजूद हैं. वहां वे मेयर, गवर्नर और राष्ट्रपति तक बन चुके हैं. संयुक्त राज्य अमेरिका के दो बार राष्ट्रपति रहे रोनाल्ड रीगन इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं. राजनेता होने से पहले उन्होंने रेडियो और फिल्म में काम किया था. वर्तमान में 25 से अधिक अमेरिकी सांसद फिल्मी दुनिया से ही हैं. इंग्लैंड में भी चार संसद सदस्य फिल्मी सितारे हैं. फिलीपींस की राजनीति में तो 30 प्रतिशत राजनेता किसी न किसी तरह फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं. रूस में भी एक गवर्नर फिल्मी दुनिया से हैं. कनाडा की राजनीति में तो एक दर्जन से अधिक उच्च पदों पर फिल्मी कलाकार हैं. वहीं श्रीलंका में लगभग 14 सांसद फिल्मी दुनिया से हैं. वहां के राष्ट्रपति महिन्दा राजपक्षे भी फिल्मी दुनिया से हैं. ये आकड़े लगातार बढ़ रहे हैं.

रवि किशन (कांग्रेस) भोजपुरी फिल्मों के अमिताभ बच्चन कहे जाने वाले रवि किशन की जौनपुर में लोकप्रियता को देखते हुए कांग्रेस ने रवि किशन को उनके क्षेत्र से टिकट दिया है. कांग्रेस लोकसभा चुनाव में अपनी जीत दर्ज कराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है. चूंकि भोजपुरी बेल्ट में रवि किशन खुब लोकप्रिय हैं, ऐसे में कांग्रेस को उम्मीद है कि रवि किशन मतदाताओं को जरूर लुभा पाएंगे और यहां से जीत दर्ज करेंगे.

चंडीगढ से आप की उम्मीदवार गुल पनाग और भाजपा से किरण खेर भ्रष्टाचार को मुद्दा बना कर लड़ने वाली आम आदमी पार्टी भी स्टार पॉवर को समझती है तभी उसने चंडीगढ़ से अभिनेत्री गुल पनाग को उम्मीदवार बनाया है. उनके अपोजिट यहां से भाजपा की उम्मीदवार अभिनेत्री किरण खेर हैं. नई-नई राजनेता बनीं गुल पनाग अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए खुब मेहनत कर रही हैं. मिस इंडिया रह चुकी 35 वर्षीय गुल लोगों से मिलने के लिए तड़के 5 बजे उठ कर अपने दिन की शुरुआत करती हैं. गुल पनाग एक अच्छी वक्ता होने के अलावा स्पोर्ट्स पर्सन और समाज सेविका भी हैं. दो नेत्रियों की जंग में कांग्रेस ने यहां से पवन कुमार बंसल को उम्मीदवार बनाया है. पवन कुमार बंसल यहां से 4 बार सांसद रह चुके हैं, जबकि बसपा ने यहां से जन्नत जहां को उम्मीदवार बनाया है.

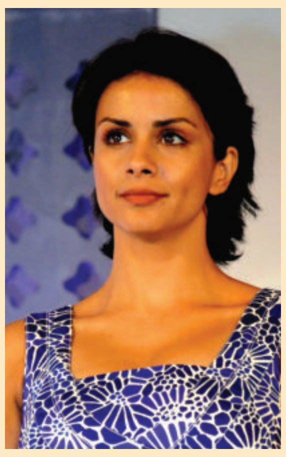

मुनमुन सेन (तृणमूल कांग्रेस) बांग्ला, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, मराठी, कन्नड़ जैसी कई भाषाओं की फिल्मों में काम कर चुकीं मुनमुन सेन को ममता बनर्जी ने बकुंडा लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है. बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रदेश से तमाम ऐसे चेहरों को उम्मीदवार बनाया है, जिनसे वोट खींचने की उन्हें जरा भी उम्मीद है. उन्होंने ग्लैमर वर्ल्ड के कई चेहरे को पार्टी में शामिल किया है.

देव (तृणमूल कांग्रेस) बंगाली अभिनेता देव को ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के घटाल लोकसभा से उम्मीदवार बनाया है. युवा वोट को गोलबंद करने के लिए ममता बनर्जी ने देव को टिकट दिया है. देव अभिनेता और गायक हैं. वह युवाओं में काफी लोकप्रिय हैं.

परेश रावल (भारतीय जनता पार्टी) हिंदी फिल्मों के जाने-माने अभिनेता परेश रावल को भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के अहमदाबाद ईस्ट से अपना प्रत्याशी बनाया है.

नगमा नगमा को कांग्रेस ने मेरठ सीट से उम्मीदवार बनाया है. नगमा ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत वर्ष 2003 में की थी और उन्हें एक बार राज्य सभा सदस्य के लिए भी चुना गया था. नगमा ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत सलमान खान के साथ फिल्म बागी से की थी. नगमा भोजपुरी और दक्षिण भारतीय सिनेमा में भी लोकप्रिय हैं.

स्मृति ईरानी (भारतीय जनता पार्टी) अमेठी लोकसभा सीट पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को चुनौती देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने स्मृति ईरानी को टिकट दिया है. समृति ने यहां से नामांकन दाखिल करते समय कहा कि उनका मुकाबला सीधे राहुल गांधी से है आम आदमी पार्टी से नहीं. इस बार अमेठी इतिहास रचेगा, क्योंकि इस बार राहुल को यहां से पराजय का सामना करना पड़ेगा. अब देखते हैं कि स्मृति राहुल के गढ़ में उन्हें पराजित करती हैं या उन्हें पराजय का सामना करना पड़ेगा.

राखी सावंत (राष्ट्रीय आम पार्टी) आइटम गर्ल राखी सावंत ने बहुत कोशिश की भाजपा से चुनाव लड़ने की लेकिन उनकी दाल वहां नहीं गली. अब वे अपनी राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय आम पार्टी बनाकर नॉर्थ वेस्ट विधानसभा से चुनाव लड़ रही हैं. उन्होंने बताया कि हालांकि वह भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहती थीं, लेकिन भाजपा ने उन्हें वेस्ट बंगाल के श्रीरामपुर से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया था, लेकिन उनके साथ भाषा की समस्या थी. वह हिंदी और मराठी ही बोल पाती हैं. वेस्ट बंगाल की क्षेत्रीय भाषा की जानकारी न होने पर उन्हें लगा की वह भला मतदाताओं को कैसे अपनी बात समझा पाएंगी.

महेश मांजरेकर और कमाल आर खान अभिनेता और फिल्म मेकर महेश मांजरेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की टिकट पर मुंबई के नॉर्थ-वेस्ट से चुनाव लड़ रहे हैं. उनके अपोजिट कांग्रेस से गुरुदास कामत हैं. गुरुदास कामत कांग्रेस के यूनियन मिनिस्टर और जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, जबकि शिवसेना से इस क्षेत्र के उम्मीदवार हैं गजानन किर्तिकर. वहीं प्रोड्यूसर एक्टर कमाल आर खान भी इस क्षेत्र से समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार हैं, जबकि आम आदमी पार्टी ने यहां से मयंक गांधी को उम्मीदवार बनाया है.

जावेद जाफरी (आम आदमी पार्टी) आम आदमी पार्टी ने बॉलीवुड के मशहूर एक्टर जावेद जाफरी को लखनऊ लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है. वह लखनऊ सीट पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह को टक्कर देंगे. जावेद जाफरी बेहतरीन डांसर और कॉमेडियन हैं.

बाबुल सुप्रियो बंगाली अभिनेता (भारतीय जनता पार्टी) गायक और अभिनेता बाबुल सुप्रियो आसनसोल वेस्ट बंगाल से भाजपा के उम्मीदवार हैं.

बप्पी लाहिड़ी बप्पी लाहिड़ी जाने माने संगीत निर्देशक और गायक है. उनकी लोकप्रियता को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें कोलकाता के हुगली जिले के श्री रामपुर से उम्मीदवार बनाया है.

मनोज तिवारी भोजपुरी गायक और अभिनेता मनोज तिवारी बिहार और उत्तर प्रदेश में काफी लोकप्रिय हैं. उनकी लोकप्रियता को देखते हुए भाजपा ने उन्हें दिल्ली की नार्थ-ईस्ट लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है. इससे पहले मनोज तिवारी समाजवादी पार्टी की टिकट से गोरखपुर से चुनाव लड़ चुके हैं.

राज बब्बर अभिनेता राज बब्बर कांग्रेस से फिरोजाबाद के एमपी हैं. उन्होंने समाजवादी पार्टी प्रमुख की पत्नी डिंपल यादव को हराया था. अब वह गाजियाबाद से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं.

विनोद खन्ना पंजाब के गुरुदासपुर से भारतीय जनता पार्टी ने विनोद खन्ना को उम्मीदवार बनाया है. लोकसभा चुनाव में वह दो बार विजयी रहे थे. विनोद खन्ना ने 1997 में भाजपा ज्वाइन की थी और 1998 में गुरुदासपुर से लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी. इसके बाद वह केंद्रीय मंत्री बने. 2004 में भी उन्होंने गुरुदासपुर से एकबार फिर जीत दर्ज की लेकिन 2009 के लोकसभा चुनाव में वह हार गए थे.

शत्रुघ्न सिन्हा शत्रुघ्न सिन्हा बिहार के पटना साहिब से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं. वे यहां के वर्तमान सांसद भी हैं. वह केंद्रीय मंत्री और साथ ही तीन बार राज्य सभा सदस्य भी रह चुके हैं.

हेमा मालिनी ड्रीमगर्ल हेमा मालिनी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, क्लासिकल डांसर और कोरियोग्राफर भी हैं. उन्होंने 2004 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी. वह पार्टी की कर्मठ सदस्य हैं. मार्च 2010 में वह पार्टी की जनरल सेक्रेटरी चुनी गईं. वह मथुरा से भाजपा उम्मीदवार हैं.

प्रकाश झा राजनीतिक और सामाजिक मुद्दे पर गंगाजल, अपहरण, राजनीति, चक्रव्यूह, आरक्षण और सत्याग्रह जैसी फिल्में बना चुके फिल्म निर्देशक प्रकाश झा को जनता दल यूनाइटेड ने पश्चिमी चम्पारण से लोकसभा का टिकट दिया है. झा ने लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर बेतिया सीट से 2009 के लोकसभा चुनाव में भाग्य आजमाया था, लेकिन उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था.

सिद्धांत महापात्रा (बीजेडी) बीजेडी से गंजम जिले के चतरपुर से सिद्धांत महापात्रा उम्मीदवार हैं.

विश्वजीत चटर्जी (टीएमसी) साउथ दिल्ली से जाने माने अभिनेता विश्वजीत चटर्जी तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

राजनीति की पिच पर खेलते खिलाड़ी

खिलाड़ियों का राजनीति में आना नई बात नहीं है. इस चुनाव में भी अलग-अलग खेलों से कुछ खिलाड़ी राजनीतिक मैदान की बाजी मारने को आतुर हैं. राजनीति में खिलाडियों को पहचान भी आसानी से मिल जाती है क्योंकि वे पहले से जाने-पहचाने चेहरे होते हैं. प्रत्येक पार्टी इनके फेस वैल्यू को भुनाना भी चाहती है. लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता. कई मशहूर और लोकप्रिय खिलाड़ी भी राजनीतिक खेल में मात खा चुके हैं. यह चुनाव भी ऐसे ही कई खिलाड़ियों की किस्मत की नई इबारत लिखेगा.

धर्मेंद्र कुमार सिंह

लोकसभा चुनाव आते ही राजनीति के गलियारों में हलचल तेज हो जाती है और राजनेताओं का एक से दूसरी पार्टी में आना-जाना शुरू हो जाता है. कई राजनीतिज्ञ अपनी पार्टी छोड़ दूसरी पार्टी में शामिल होने लगते हैं, तो कई नए लोग राजनीतिक पार्टियों से जुड़कर राजनीति में भाग्य आजमाने के लिए आते हैं. खिलाड़ी भी इससे अछूते नहीं हैं. हाल में कई खिलाड़ी भी राजनीतिक पार्टियों में शामिल हुए हैं. कई दिग्गज खिलाड़ी पहले से राजनीति में हैं, जिन्होंने अपनी शुरुआत चुनाव लड़ कर की है. अब यह देखना होगा दिलचस्प होगा कि ये नए खिलाड़ी राजनीतिक पिच पर कितना कामयाब हो पाते हैं. हमने खेल मैदान का मैदान छोड़कर राजनीति में भाग्या आजमाने आए कुछ खिलाड़ितों पर एक नजर डालने की कोशिश की है.

क्रिकेट के मैदान से राजनीति में आए कीर्ति आजाद के पिता भागवत झा आजाद बिहार के मुख्यमंत्री थे. कीर्ति आजाद 1993 में दिल्ली गोलमार्केट विधानसभा सीट से विधायक रहे हैं. इसके बाद वह भाजपा के टिकट पर 1999 और 2009 में दरभंगा सीट से सांसद चुने जा चुके हैं. कीर्ति भाजपा के टिकट पर इस बार भी दरभंगा लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में हैं. वहीं भारतीय टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन उत्तरप्रदेश की मुरादाबाद लोकसभा सीट से कांग्रेस के सांसद हैं और इस बार उनको कांग्रेस ने राजस्थान के सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा है. अब यह देखना होगा कि अजहरूद्दीन कि क्या इस बार भी वे पहले वाला करिश्मा दिखा पाते हैं? अजहरुद्दीन ने 2009 में ही कांग्रेस में शामिल हुए थे. उसी साल उन्हें पार्टी का टिकट भी थमा दिया गया था. नवजोत सिंह सिद्धु ने 2004 में अमृतसर लोकसभा सीट से भाजपा के टिकट पर पहली बार चुनाव लड़ा था तभी से वह वहां के सांसद हैं, लेकिन इस बार भाजपा ने उनको टिकट नहीं दिया है. उनकी जगह पार्टी ने अमृतसर से राज्यसभा सांसद व राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली को टिकट दिया है. भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी चेतन चौहान सन्यास लेने के बाद भाजपा से जुड़े और अमरोहा लोकसभा सीट से 1991 में चुनाव लड़ा. वहां से जीत हासिल की. चौहान दो बार भाजपा के टिकट चुनाव जीतकर वहां के सांसद रहे हैं और उन्हें तीन बार लोकसभा चुनाव में हार का सामना भी करना पड़ा. विनोद कांबली राजनीति में आए, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली. उन्होंने 2009 में मुंबई के बिखरोली विधानसभा सीट से लोकभारती पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन चुनाव हार गए. भारतीय क्रिकेट टीम के सफल कप्तानों में शुमार किए जाने वाले मंसूर अली खान पटौदी ने 1971 में विशाल हरियाणा पार्टी के टिकट पर गुड़गांव से लोकसभा चुनाव लड़ा, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा. उसके बाद 1991 में कांग्रेस के टिकट पर उन्होंने भोपाल से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन वहां भी हार गए. भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाडी युवराज सिंह के पिता भी क्रिकेटर ही थे. योगराज सिंह ने 2009 में आईएनएलडी के टिकट पर पंचकुला से हरियाणा विधानसभा का चुनाव लड़ा और उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा. पश्चिम बंगाल की एथलीट ज्योतिर्मयी सिकदर 2004 में सीपीआई(एम) के टिकट पर पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ीं और जीत दर्ज कराई. उन्होंने एक बार फिर 2009 में उसी सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन वह चुनाव हार गईं. ज्योतिर्मयी ने 1998 के बैंकॉक एशियन गेम्स में 800 और 1500 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक हासिल किया था. निशानेबाज जसपाल राणा भी 2009 में भाजपा के टिकट पर उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल से चुनाव लड़े, लेकिन उनको चुनाव में हार मिली. उसके बाद राणा ने 2012 में कांग्रेस का दामन थाम लिया. जसपाल राणा ने एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक हासिल किया है. केन्द्र में कांग्रेस की अगुवाई वाली युपीए सरकार ने सचिन को राज्यसभा के लिए नामित किया और सचिन को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा सांसद के रूप में मनोनीत किया गया है. सचिन ने 24 साल के सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय करियर को पिछले साल नवम्बर में मुंबई में वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट खेलकर अलविदा कहा था. सचिन ने 200 टेस्ट मैच और 463 वनडे मैच खेले हैं. खिलाड़ी से नेता बनने की चाहत धीरे-धीरे बढ़ती ही जा रही है. निशानेबाज रहे राज्यवर्धन सिंह राठौर ने राजस्थान में भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह और पार्टी के पीएम प्रत्याशी नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में भाजपा में शामिल होकर राजनीति की शुरुआत की है. भाजपा ने उन्हें जयपुर गांव लोकसभा सीट से चनाव मैदान में उतारा है. राज्यवर्धन एथेंस ओलंपिक में भारत के एकमात्र पदक जीतने वाले खिलाड़ी थे. वर्ष 2004 में उनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. भारतीय हॉकी के पूर्व कप्तान और सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी धनराज पिल्ले आप मे शामिल होकर राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं. पिल्ले को 1999-2000 में सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न से नवाजा गया और 2000 में उन्हें देश पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है. क्रिकेट में असफल रहने के बाद मोहम्मद कैफ राजनीति में भाग्य आजमाएंगे. कैफ कांग्रेस के टिकट पर उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद फूलपूर लोकसाभा सीट से चुनाव मैदान में हैं. हमें यह देखना होगा कि कैफ राजनीति में सफल होते हैं या क्रिकेट की तरह फ्लॉफ हो जाते हैं. कैफ ने आखिरी मैच दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2006 में एक दिवसीय मैच खेला था. कैफ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से खराब प्रदर्शन के कारण बाहर चल रहे हैं. भारतीय फुटबाल टीम के स्टार खिलाड़ी रहे बाइचुंग भूटिया और प्रसून बनर्जी ने ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस में शामिल होकर राजनीति की शुरुआत की है. दोनों ही फुटबाल खिलाड़ी रहे हैं. इस बार दोनों ही टीएमसी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं. बाइचुंग भूटिया दार्जिलिंग लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में हैं, तो प्रसून बनर्जी हावड़ा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
CHAUTHI DUNIYA

चौथी दुनिया की हर खबर अब आपके Android फोन पर भी उपलब्ध,
Play Store से Download करें | CHAUTHI DUNIYA APP

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

www.kamalmorarka.com

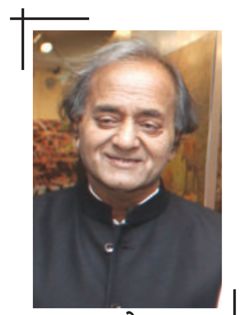

कमल मोरारका

आम आदमी गुजरात में मुद्रास्फीति कम होते हुए देखना चाहता है, कम क़ीमत पर सब्जियां मिलें, यह चाहता है. ठीक है, यह सब आपके हाथ में नहीं है, लेकिन कम से कम सरकार तो आपके हाथ में है. क्या आपने नौकरशाही का आकार छोटा कर दिया है? कम से कम उन निचली जगहों पर, जहां से रोज-रोज जनता का वास्ता पड़ता है. मोदी के पास रिकॉर्ड पर दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है. उनका गुडलक है कि विभिन्न घोटालों की वजह से आज, आज़ादी के बाद से, पहली बार कांग्रेस अपनी सबसे खराब स्थिति में है. कांग्रेस पार्टी के लिए यह एक दुःखद बात है. लेकिन, एक ऐसी स्थिति की कल्पना कीजिए, जहां वास्तव में कांग्रेस पार्टी गायब हो जाती है.

कांग्रेस मुक्त भारत या भ्रष्टाचार मुक्त?

चुनाव ख़त्म होने के क़रीब है. नतीजे 16 मई को आ जाएंगे. नतीजे हमेशा अप्रत्याशित होते हैं. कौन जीतता है, कौन हारता है और कौन सत्ता में आता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यह मतदाताओं का निर्णय होता है और सभी को उसका सम्मान करना चाहिए. हालांकि, निराशाजनक तथ्य यह है कि जो सत्ता में आने को इच्छुक हैं, उनका स्वयं का व्यवहार, आचरण और भाषा वह नहीं है, जिसकी अपेक्षा की जाती है. ये लोग प्रेरणादायक नहीं हो सकते. पहले नरेंद्र मोदी की बात करें. उन्होंने खुले तौर पर इस चुनाव को एक व्यक्तित्व युद्ध में बदल दिया है. वह अपने भाषणों में खुद के लिए वोट मांगते हैं, न कि भाजपा और उसके मूल्यों के लिए. वह कहते हैं, मुझे वोट दें और मैं आपको शासन दूंगा. ठीक है, स्वीकार किया, लेकिन आप करते क्या हैं? वह कहते हैं, मैं आपको एक कांग्रेस मुक्त भारत दूंगा. उन्हें पता है कि वह क्या बोल रहे हैं? यह कांग्रेस मुक्त भारत क्या है? क्या वह सत्ता में आने के बाद सारे कांग्रेसियों को मार देंगे? वह क्या करने जा रहे हैं? वह यह बोल सकते हैं कि मैं कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दूंगा. चुनाव का मतलब भी यही होता है.

कांग्रेस मुक्त भारत का मतलब क्या? और, विडंबना यह है कि वह वाराणसी में अपना नामांकन भरने से पहले मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा को माला पहनाते हैं. कौन थे मालवीय जी? वह आज़ादी की लड़ाई के दौरान एक कांग्रेसी थे. मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी जैसे लोग अभी तक यह नहीं समझ सके हैं कि भारतीय लोकतंत्र का अर्थ क्या है? वह पिछले 13 वर्षों से गुजरात चला रहे हैं. वह कहते हैं, मैं कम से कम सरकार और अधिकतम शासन में विश्वास करता हूं. ठीक है, लेकिन बताइए कि गुजरात में आपने कौन सी सरकार का आकार कम कर दिया है? क्या वहां एक राशनकार्ड तीन दिनों में जारी किया जा सकता है? मैं अहमदाबाद जाता हूं, वहां रहने के लिए क्या एक दिन में अपना ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकता हूं? पश्चिमी देशों में ऐसा होता है और यहां भी होना चाहिए. लेकिन, यह सिर्फ़ कहने की बातें हैं. गुजरात में भी ऐसा नहीं होता, क्योंकि बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की वजह से यह संभव नहीं है. नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैंने टाटा की नैनो कार के लिए चीजों को आसान बनाया, लेकिन आम आदमी को इससे कैसे मदद मिलती है?

आम आदमी गुजरात में मुद्रास्फीति कम होते हुए देखना चाहता है, कम क़ीमत पर सब्जियां मिलें, यह चाहता है. ठीक है, यह सब आपके हाथ में नहीं है, लेकिन कम से कम सरकार तो आपके हाथ में है. क्या आपने नौकरशाही का आकार छोटा कर दिया है? कम से कम उन निचली जगहों पर, जहां से रोज-रोज जनता का वास्ता पड़ता है. मोदी के पास रिकॉर्ड पर दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है. उनका गुडलक है कि विभिन्न घोटालों की वजह से आज, आज़ादी के बाद से, पहली बार कांग्रेस अपनी सबसे खराब स्थिति में है. कांग्रेस पार्टी के लिए यह एक दुःखद बात है. लेकिन, एक ऐसी स्थिति की कल्पना कीजिए, जहां वास्तव में कांग्रेस पार्टी गायब हो जाती है. अगर ऐसा होता है, तो यह देश के लिए एक दुःखद बात होगी. यह देश की ज़रूरत है कि यहां कम से कम दो से तीन मजबूत पार्टियां हों, जो अन्य पार्टियों पर चेक एंड बैलेंस रख सकें. एक-एक पार्टी का शासन, चाहे वह कांग्रेस का हो या भाजपा का, विनाशकारी है. और, एक व्यक्ति का शासन तो और भी ज़्यादा विनाशकारी है.

इंदिरा गांधी आज भी, बांग्लादेश की जीत के बावजूद, अपने तानाशाही तौर-तरीकों और भ्रष्टाचार के लिए जानी जाती हैं. क्यों? लोग व्यक्तिवाद को पसंद नहीं करते हैं. हालांकि, इंदिरा गांधी निश्चित रूप से इस देश की एक बहुत सक्षम एवं योग्य प्रधानमंत्री थीं. नरेंद्र मोदी उनका नाम नहीं ले सकते, लेकिन खुद के लिए इंदिरा गांधी की शैली अपनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी के साथ वह कांग्रेस मुक्त भारत भी चाहते हैं. वह पटना जाकर अलेक्जेंडर और तक्षशिला की बात करते हैं. जाहिर है, उन्होंने इतिहास या भूगोल का अध्ययन नहीं किया था. एक व्यक्ति, जो भारत पर राज करना चाहता है यानी दुनिया की आबादी के सातवें हिस्से पर, के पास बेहतर तथ्य होने चाहिए. एक चीज, जो बदल सकती है, उन्हें उसी के बारे में बोलना चाहिए. उन्हें बोलना चाहिए कि वह एक भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे. अगर वह ऐसा कर पाते हैं, तो यह एक बड़ी बात होगी, लेकिन वह कांग्रेस मुक्त भारत देना चाहते हैं. मुझे नहीं लगता कि उन्हें सही तथ्य मिल पाते हैं. हम केवल आशा कर सकते हैं कि अगर भाजपा या मोदी के नेतृत्व में सरकार आती है, तो एक अच्छा माहौल बनेगा और वे रचनात्मक कामों में व्यस्त हो जाएंगे.

पहले मोदी कहते थे कि वाड्रा मामले में क़ानून अपना काम करेगा, लेकिन अब वह बदले की बात कर रहे हैं. मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने अब तक जो किया है, वह सही है. अभी तक उनके पास जो ग्राउंड फीडबैक आ रहे हैं, वे अच्छे नहीं हैं. इसलिए चिड़चिड़ापन दिख रहा है. यही कारण है कि प्रियंका गांधी एक बयान देती हैं और पूरी की पूरी भाजपा उन पर बयानबाजी शुरू कर देती है. मैं यह सब समझ नहीं पा रहा हूं और यह भारत जैसे परिपक्व लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए. 1952 से अब तक 62 साल हो गए, चुनाव होते हुए. मैं सोचता हूं कि हमें परिपक्व होना पड़ेगा. चुनाव लगभग ख़त्म हो गया है. अगले चुनाव से पहले हमारे पास सभ्य तरीके से चुनाव का संचालन करने के लिए नियम होने चाहिए. किसी भी टेनिस मैच या चुनाव में एक जीतता है और एक हारता है. इस पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए. जो सत्ता में नहीं आता, वह भी विपक्ष में बैठता है. अब भी यही होगा. मैं कामना करता हूं कि देश को नेतृत्व देने के आकांक्षी लोग भविष्य के चुनावों में अपने मुद्दे और विकसित करेंगे तथा बेहतर भाषा का उपयोग करेंगे. ■

feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

इस समय देश के हर न्यूज चैनल पर नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू आ रहा है. मोदी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, यह टीवी चैनलों ने मान लिया है. उसी अंदाज में इंटरव्यू लेने वाले सवाल कर रहे हैं, मानो वे नरेंद्र मोदी की कितनी कृपा के पात्र हैं, यह दर्शाना चाह रहे हैं. अख़बारों के इंटरव्यू ईमेल से हो रहे हैं और अख़बार यह लिख रहे हैं कि मोदी के जवाब बहुत बेबाक और साफ़ हैं.

अगर टीवी चैनल और अख़बार यह दावा करें, तो उससे असहमत कैसे हुआ जा सकता है, लेकिन इन सारे सवालों में देश के ग़रीब, वंचित, दलित और मुसलमान गायब हैं. इन वर्गों की हालत कैसे सुधारी जाए, इसके बारे में न कोई सवाल है और न प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का कोई बयान है. एक और वर्ग गायब है उच्च वर्ग, जिसमें ब्राह्मण, ठाकुर, कायस्थ और व्यापारी आते हैं. उसमें जो ग़रीब तबका है, उसका

देश नरेंद्र मोदी से क्या चाहता है

जीवन किस तरीके से अच्छा बनेगा, इसका भी कोई उत्तर इन इंटरव्यूज में नहीं मिलता. अब तक एक बड़ा सवाल सवर्ण ग़रीबों का उठाया जाता रहा है और राजनीतिक दल, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के लोग यह कहते रहे हैं कि ग़रीबों का मतलब सिर्फ़ दलित, मुसलमान या आदिवासी नहीं हैं. सवर्णों में भी ग़रीब हैं और उनके लिए कोई सरकार क्या कर रही है? लेकिन अब, जब खुद भारतीय जनता पार्टी अप्रत्यक्ष रूप में और नरेंद्र मोदी प्रत्यक्ष रूप में सत्ता में आते दिख रहे हैं, तब भी इन सवालों का जवाब न दिया जाना कई तरह के संदेह पैदा करता है.

पहला संदेह तो यह कि देश को ग़रीबी के भंवरजाल से निकालने का कोई भी स्पष्ट नक्शा न भारतीय जनता पार्टी के पास है और न नरेंद्र मोदी के पास. मैं बहुत ध्यानपूर्वक पत्रिकाओं और समाचार-पत्रों को देख रहा हूं. इनमें से कोई भी आर्थिक नीतियों पर सवाल नहीं उठा रहा है और जब हमने यह सवाल उठाया कि देश में चीन से बना माल बाज़ारों में अटा पड़ा है. मोबाइल फोन या मोबाइल फोन के हेडफोन या हैंड्स-फ्री तार जैसी चीजें हम चीन से मंगाते हैं और उसे हिंदुस्तान में बनाने का कोई भी संकल्प नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी की तरफ़ से न आए, तो फिर आर्थिक नक्शा क्या होगा या विकास का नक्शा क्या होगा, यह समझ में आ सकता है. जैसे ही हमने यह लिखा, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के लोग चिल्लाने लगे कि मोबाइल हम देश में ही बनाएंगे. इसका मतलब न किसी तरह की कल्पना है और न किसी तरह का रोडमैप सामने है.

नरेंद्र मोदी के इंटरव्यूज में भारत का किसान गायब है. किसान को फसल का दाम कैसे मिलेगा, फसल या खेती लाभकारी कैसे होगी, खेती की जमीन को छिनने से कैसे बचाया जाएगा और किसान की फसल कैसे बिचौलियों के जाल से मुक्त होकर सीधे उपभोक्ता तक पहुंचेगी, इसका भी नक्शा नरेंद्र मोदी जी के किसी भी इंटरव्यू में नहीं दिखाई दिया. आज भी देश का सबसे बड़ा उद्योग कृषि है, जो 70 प्रतिशत से ज़्यादा देश की अर्थव्यवस्था में योगदान करती है. इतना ही नहीं, सिर्फ़ कृषि है, जिसकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था स्थिर है. बाकी देशों में जहां कृषि नहीं है, वहां की सरकारों एवं व्यापारियों ने मिलकर अपनी अर्थव्यवस्था बर्बाद की और हमारे देश की अर्थव्यवस्था को भी बर्बाद करने की पूरी कोशिश हुई, पर सिर्फ़ कृषि ने उसे बचाए रखा. वह कृषि नरेंद्र मोदी के आर्थिक विकास में कहीं दिखाई नहीं देती.

क्या उत्पादन का बुनियादी केंद्र औद्योगिक इकाई का प्राथमिक केंद्र नहीं बन सकता? एक ब्लॉक में पैदा होने वाला कच्चा माल उसी ब्लॉक में प्रॉसेस होकर बाज़ार में पहुंचे, क्या यह योजना नहीं बनाई जा सकती? अगर यह योजना बने, तो गांव से नौजवानों का शहरों की तरफ़ पलायन रुक जाएगा और गांवों को स्वावलंबी बनने में मदद मिलेगी. एक ब्लॉक के सभी गांवों में रोज़गार के अवसर भी पैदा होंगे और तकनीक का इस्तेमाल गांव के लिए शुरू होगा. ये सारी बातें श्री नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू में कहीं नज़र नहीं आतीं.

पिछले 10 सालों में देश के जल, जंगल और जमीन को बुरी तरह से मल्टीनेशनल कंपनियों के हाथों में बेचा गया है, जिनमें बहुतों में चेहरा देशी पूंजीपतियों का है. जल, जंगल और जमीन राष्ट्रीय संपदा हैं और इन्हें न देशी पूंजीपति और न विदेशी पूंजीपति को बेचा जाएगा, इसका कोई संकल्प नरेंद्र मोदी के किसी इंटरव्यू में दिखाई नहीं देता. पिछले 10 सालों में जल, जंगल, जमीन अर्थात खनिज संपदा और प्राकृतिक संपदा की जमकर लूट हुई है. यहां तक कि नदियों को बड़े पूंजीपतियों के हाथों बेच दिया गया है. आज भी गांव वालों या देश की बहुसंख्यक आबादी की समझ में नहीं आता कि नदियां कैसे बेची जा सकती हैं. नदियां तो प्रकृति की देन हैं या ईश्वरीय देन हैं, पर ये नदियां बेची गई हैं. इन नदियों के बेचने में अरबों की दलाली चली है. उसी तरीके से खनिज संपदा को मनमाने ढंग से लूटा गया है और इन्हें लूटने में केंद्रीय स्तर पर केंद्र सरकार और राज्य स्तर पर राज्य सरकारें भी शामिल हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के दल की भी सरकारें शामिल हैं.

कई प्रदेशों में, जिनमें मध्य प्रदेश का उदाहरण सबसे प्रमुख है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े लोग खदानों की हेराफेरी में शामिल पाए गए. यह पैसा इतने कमाल की चीज है कि अच्छे-अच्छे को ईमानदार से बेईमान बना देता है. नरेंद्र मोदी पर सामान्य जनता अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था या अच्छे गवर्नेंस की आशा में विश्वास कर रही है. कांग्रेस के प्रधानमंत्री और कांग्रेस मंत्रिमंडल ने देश में यह भ्रम पैदा कर दिया है कि अब व्यवस्था को सुधारा नहीं जा सकता और लूट एक सर्वव्यापी अवसर के रूप में सामने आई है. इसे रोकने के लिए लोग नरेंद्र मोदी की तरफ़ देख रहे हैं. नरेंद्र मोदी की तस्वीर उनके प्रचार तंत्र ने कुछ इस तरह की बना दी है कि नरेंद्र मोदी के आते ही व्यवस्था में सब कुछ सुचारू रूप में चलने लगेगा. लेकिन सुचारू रूप से कैसे चलेगा, इसका कोई संकेत नरेंद्र मोदी के किसी इंटरव्यू में नज़र नहीं आता.

यह कहा जा सकता है कि हम नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी की आलोचना कर रहे हैं. भारतीय जनता पार्टी भी इसे इसी रूप में देखेगी, लेकिन हमारी मजबूरी यह है कि हम पत्रकार हैं और चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, जयललिता हों, ममता बनर्जी हों, वामपंथी हों या फिर समाजवादी हों, अगर वे सत्ता में आ रहे हैं, सत्ता में आने के दावेदार हैं, तो हमें उनके किए हुए कामों के कमजोर पहलू लोगों के सामने लाने ही होते हैं. यह आलोचना नहीं है, यह हमारा कर्तव्य है और इस कर्तव्य के तहत हम जब देखते हैं, तो हमें यह दिखाई देता है कि भावी प्रधानमंत्री का दावा करने वाला व्यक्ति देश को स्पष्ट संदेश नहीं दे रहा है. अब अगर यह कहें कि राहुल गांधी भी कोई संदेश या कोई स्पष्ट राह नहीं दिखा रहे हैं, तो आपको कोई चिंता नहीं होती. मैं इसे कुतर्क मानता हूं. राहुल गांधी की समझ के बारे में पिछले 6-7 सालों में राय बनी है कि उनमें न देश की समस्याओं की समझ है और न समझने की इच्छाशक्ति है. इसलिए राहुल गांधी अपने अधकचरे भाषण लिखने वाले सलाहकारों पर निर्भर हैं और वह देश को जो बोलते हैं, वही अधकचरापन बोलते हैं. पर नरेंद्र मोदी को लेकर चिंता इसलिए होती है, क्योंकि वह गंभीरतापूर्वक प्रधानमंत्री पद की तरफ़ बढ़ते दिख रहे हैं. हज़ारों करोड़ रुपये खर्च करके उनके प्रचार तंत्र ने देश के लोगों में उनकी महाबली की तस्वीर बना दी है. अब यह महाबली साबित नहीं करेगा कि वह महाबली है, तो देश आंतरिक तनाव के दौर में पहुंच जाएगा. मैं जिसे आंतरिक तनाव कहता हूं, वह दरअसल, देश में छीना-झपटी के दौर का पहला हिस्सा है. जिस तरीके से ग़रीबी और अमीरी के बीच का अंतर बढ़ रहा है और जिस तरह ग़रीब को यह लग रहा है कि उसकी इस स्थिति के ज़िम्मेदार नौकरशाह और राजनेता हैं, उससे देश में छीना-झपटी का दौर जल्दी आने का डर पैदा हो रहा है.

महाबली नरेंद्र मोदी के राज्य का कोई भी आकलन देश के किसी भी अख़बार और टीवी चैनल ने नहीं किया. वहां की विषमता का अध्ययन किसी भी अख़बार या टीवी चैनल ने नहीं किया. शायद इसके लिए भी कोई न कोई पैकेज बना होगा. टीवी चैनलों और अख़बारों के प्रचार से अगर लोगों के पेट में रोटी पहुंच जाए, तो क्या बात है! लेकिन जिन पेटों में रोटी नहीं पहुंचेगी और जिन हाथों को काम नहीं मिलेगा, वे आशा की इतनी बड़ी ऊंचाई को बहुत जल्दी छोटा करने की सोचने लगेंगे. इसलिए नरेंद्र मोदी के सामने हर दिन चुनौतियों का पहाड़ खड़ा हो रहा है. शायद इन चुनौतियों के बारे में नरेंद्र मोदी खुद नहीं सोच पा रहे होंगे और यह ख़तरा नरेंद्र मोदी के सामने है कि वह जिन आशाओं को पैदा कर रहे हैं, अगर उन आशाओं को पूरा करने का कोई साफ़ नक्शा उनके पास नहीं है, तो उनके ख़िलाफ़ एक बड़ा जनांदोलन भविष्य के गर्भ में पनप रहा है.

अगर इन संभावनाओं को नकारने या कुचलने का काम नरेंद्र मोदी धार्मिक ध्रुवीकरण से करेंगे, तो वह इस देश में दंगों और नरसंहारों की तरफ़ मुड़ जाएगा. इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि नरेंद्र मोदी हर हालत में देश की समस्याओं की प्राथमिकता तय करें और उन प्राथमिकताओं के आधार पर अपना संकल्प दोहराएं. संकल्प दोहराएं या न दोहराएं, पर उनके हल की तरफ़ क़दम बढ़ाएं. देश इस समय नरेंद्र मोदी से यही चाह रहा है, वर्ना विकास और विनाश का रास्ता एक ही बिंदु से मुड़ता है और अगर सावधान न रहे, तो विकास से गुजरने की जगह हम विनाश के दौर से गुजरने लगेंगे.■

editor@chauthiduniya.com

एस पी सिंह और एम जे अकबर

सुरेंद्र प्रताप सिंह व एम जे अकबर, दो ऐसे शख्स हैं, जिनके बारे में पत्रकारिता में रुचि रखने वालों को जानना ही चाहिए. पर यह भी सच है कि इन दोनों के बारे में संपूर्णता से शायद ही कोई बता सके. उतना ही बताया जा सकता है, जितना अनुभव हुआ हो. आज हमारे बीच एस पी सिंह नहीं हैं, पर वे जितने दिन हमारे बीच रहे, इतिहास बनाते रहे. अकबर हमारे बीच हैं, लेकिन उन्होंने कभी अपने बारे में लिखा नहीं और न ही दूसरों ने उनके बारे में लिखा. पत्रकारिता का सुनहरा काल इन दोनों को मिलाकर ही जाना जा सकता है, क्योंकि ये एम जे अकबर ही थे, जो एस पी को कोलकाता लाए, रविवार की ज़िम्मेदारी सौंपी, उन्हें आज़ाद छोड़ दिया और इस बात का अवसर दिया कि वे उन्हें संडे के संपादक के तौर पर अक्सर रविवार के संपादक के रूप में शह देते रहें. दोनों ने एक-दूसरे को शह दी, पर सबसे खूबसूरत बात उनके रिश्ते की यह रही कि दोनों में से किसी ने एक-दूसरे को मात नहीं दी.

संपादक के रूप में सुरेंद्र प्रताप सिंह के नाम की शैली किसी भी संपादक से अलग थी. काम करते समय वे धीर-गंभीर रहते थे, पर अचानक मजाक में गंभीर बात कह देते थे, जब तक सामने वाला सोचे कि उसे क्या प्रतिक्रिया देनी है, तब तक वे स्वयं हंस देते थे, सामने वाला सहज हो जाता था. रविवार उन दिनों हिंदी क्षेत्र में आतंक सा बन गया था और सोचा जा सकता है कि संपादक की छवि लोगों में कैसी बनी होगी. एस पी का सामना जब किसी अंजान आदमी से होता था, तो पहले तो वह विश्वास ही नहीं कर पाता था कि यही व्यक्ति रविवार का संपादक है. मैं उन दिनों लखनऊ में था, एस पी लखनऊ आए थे और मुख्य सचिव उनसे किसी भी तरह मिलना चाहते थे. मैं उन्हें लेकर सचिवालय गया. मुख्य सचिव के चपरासी ने कहा कि सर संपादक जी को तो लाइए, मैंने उससे कहा कि यही संपादक जी हैं, तो उसने विश्वास ही नहीं किया. मुझे उसने दोबारा कहा, साहब, संपादक जी? मेरे पुनः विश्वास दिलाने पर भी वह अविश्वास से ही भरा रहा. जब मुख्य सचिव के साथ उसने उन्हें चाय पीते देख लिया, तभी शायद वह भरोसा कर पाया. एस पी का व्यक्तित्व औघड़ का व्यक्तित्व था. एक ओर ज्ञान का अपार खजाना, दूसरी ओर इतनी सहजता कि लगता ही नहीं था कि दोनों एक ही व्यक्ति हैं. शायद इसीलिए उनके मित्रों में राजनेताओं के साथ-साथ प्रधानमंत्री निवास का माली भी था. उनका संपर्क इतना विशाल था कि सूचनाएं उनके पास तैरकर आ जाती थीं. हम सभी उनके संपर्क क्षेत्र को देखकर हैरान रहते थे. राज्यों में, उनका एक स्रोत उनके संवाददाता थे, तो दूसरा स्रोत कुछ और भी था. अगर कभी संवाददाता कुछ अलग कहने की कोशिश करता भी था, तो वे बिना बताए क्रास चेक कर लेते थे. अलग-अलग दलों के राजनेताओं से उनका व्यक्तिगत संबंध कुछ इस तरह था कि दलों की अंदरूनी ख़बरें उनके पास घटने की योजना के साथ ही आ जाती थीं.

उनकी सबसे बड़ी ताकत शायद उनका मित्रवत व्यक्तित्व था. लोग उनके पास दोस्त की तरह जाते थे और जो नहीं जाते थे, वे दोस्त बनकर वापस आते थे. वे जितनी सहजता से चंद्रशेखर से बात करते थे, उतनी ही आत्मीयता से साउथ एवेन्यू टैक्सी स्टैंड के ड्राइवर से बातें करते थे. इस ड्राइवर ने उन्हें बड़ी कहानियां बताई थीं, सांसदों और मंत्रियों को लेकर, क्योंकि वह उन घटनाओं का गवाह रहा था. एस पी ने कभी उनका पत्रकारिता में इस्तेमाल नहीं किया, हमें भी नहीं करने दिया, क्योंकि कुछ-कुछ जानकारियों को उन्होंने हमें भी बताया था.

एक बार वे लखीमपुर खीरी में दुधवा के जंगलों में गए. जैसे ही उत्तर प्रदेश सरकार को पता चला, उसने एक पुलिस इंस्पेक्टर उनके साथ लगा दिया. जंगल में पहली शाम थी. एस पी ने बातें छेड़ीं और धीरे से बीच में कहा कि अफीम, गांजा और चरस के नशे के बारे में उन्हें नशेड़ियों ने क्या बताया है. वह इंस्पेक्टर सुनता रहा. आधे घंटे बाद बोला, सर, चरस देखनी हो, तो दिखाऊं? एस पी ने कहा, दिखाओ, फिर मेरी ओर देखकर मंद मुस्कान फेंकी. उसने जेब से चरस निकाली, उसे सिगरेट की पन्नी पर रखकर जलाया और फिर सिगरेट में भरकर कैसे पिया जाता है, दिखाया. वही इंस्पेक्टर आधे घंटे बाद तोते की तरह एस पी को बता रहा था कि दुधवा के जंगलों में क्या-क्या होता है, कौन-कौन अधिकारी और नेता इसमें

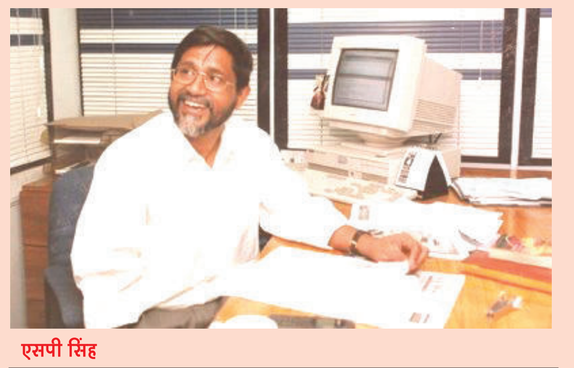

एसपी सिंह

हिस्सेदार हैं, नेपाल सीमा से क्या-क्या आता है और क्या-क्या जाता है. हम वहां सात या आठ दिनों तक थे और उतने दिनों वह इंस्पेक्टर एस पी के संवाददाता से ज़्यादा उनके नज़दीक था. सांसद लालमुनि चौबे के पास एस पी से संबंधित ऐसी कई कहानियां हैं, जिनमें एस पी कभी पात्रों को संपादक लगे ही नहीं और वे उन्हें अपने अंतरंग की तरह जानकारी आसानी से देते रहे.

एस पी में ख़बर पहचानने की अद्‌भुत क्षमता थी. वे प्रतिदिन ज़्यादा से ज़्यादा अख़बार पढ़ते थे. अखबारों में भी राज्यों और ज़िलों से निकलने वाले अख़बार ज़्यादा होते थे. उन्होंने यह शक्ति विकसित कर ली थी कि उन्हें अंदाजा हो जाता था कि कौन सी रिपोर्ट बड़ी ख़बर बन सकती है और उनकी नज़र वहीं आकर रुक जाती थी. एसपी में एक आदत और थी, वे स्वयं अख़बारों की कतरनें काटकर उनकी फाइल बनाकर रखते थे. पहले वे निशान लगाते थे कि कौन सी ख़बर काटने लायक है. यह प्रक्रिया आज के लोगों को यह सीख देती है कि आप यदि पूरी ख़बर पढ़ेंगे नहीं, तो क्या निशान लगाएंगे और क्या कतरनें काटेंगे.

शायद इसीलिए जब उनका फोन या खत के रूप में एक छोटा नोट संवाददाता के पास पहुंचता था कि अमुक घटना पर रिपोर्ट लिखो, तो वह संवाददाता चकरा जाता था. हममें से किसी की आदत नहीं थी कि हम ज़िलों से निकलने वाले समाचार-पत्रों या साप्ताहिकों को पढ़ें. एक बार एस पी लखनऊ आए और मुझे सख्त तरीके से इनका महत्व समझाया. तभी से मैंने अपनी आदत बनाने की कोशिश की. मैं सूचना विभाग जाता था और जो भी ज़िलों से आया समाचार-पत्र मिल जाता था, पढ़ अवश्य लेता था. ज़्यादा पढ़ने से मुझमें भी यह गुण विकसित हुआ कि ख़बरों के तत्व को पहचानूं. आज जब मुझे साथी कहते हैं कि आपकी नज़र सीधे वहीं कैसे रुक जाती है, जहां गड़बड़ होती है, तो मैं एस पी को तत्काल प्रणाम करता हूं, क्योंकि इसके पीछे उन्हीं की प्रेरणा और ताकत थी, जिसने थोड़ी सी शक्ति दी, क्योंकि पूर्ण सिद्ध तो वे ही थे.

संपादक के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना एक गुण है, ऐसा उनका निश्चित मत था. अगर संपादक ऐसा नहीं करता, तो वह फॉलोअप रिपोर्ट और विशेष रिपोर्ट तो बिल्कुल ही नहीं तलाश सकता. संपादक अगर नहीं पढ़ता है, तो वह अपनी टीम को नेतृत्व दे ही नहीं सकता, वह केवल अच्छा मैनेजर बनकर रह जाता है. हम सारे संवाददाता हमेशा चौकन्ने रहते थे कि कहीं एस पी हमें ऐसी जानकारी न भेज दें, जो हो तो हमारे आसपास और हमें पता ही न हो. हम उन्हें अपनी ओर से काम और बेकाम की बहुत सी जानकारियां देते रहते थे, शायद उत्साह में या अपना नंबर बढ़ाने के लिए, पर उन्होंने कभी इस पर झुंझलाहट नहीं दिखाई. हमारी हमेशा कोशिश रहती थी कि हम अपनी ओर से जो रिपोर्ट लिखें, उसमें कोई कमी न हो, पर जो रिपोर्ट एस पी की ओर से मांगी गई हो, वह तो संपूर्ण होनी ही चाहिए. लेकिन कभी-कभी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता था. एक लाइन का नोट आ जाता था कि-इस रिपोर्ट को फिर लिखो, इसमें यह छूट गया है. पहले कोफ्त होती थी, पर देखने पर एहसास होता था कि सही फ़ैसला हुआ. शायद इसी कवायद ने हममें से कइयों को पत्रकारिता के गौरवपूर्ण अध्याय का हिस्सा बनने का मौक़ा दिया.■

जारी...

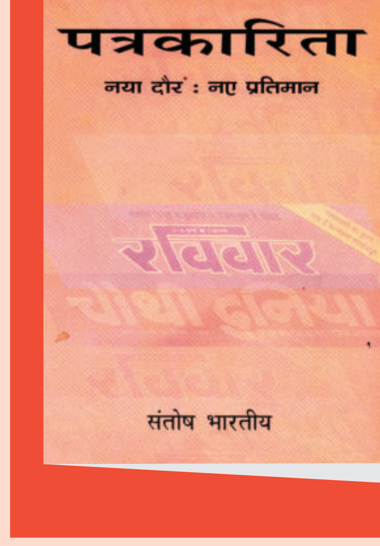

आज पत्रकारिता के मायने बदल गए हैं, बदल रहे हैं अथवा बदल दिए गए हैं, नतीजतन, उन पत्रकारों के सामने भटकाव जैसी स्थिति आ गई है, जो पत्रकारिता को मनसा-वाचा-कर्मणा अपना धर्म-कर्तव्य और कमज़ोर-बेसहारा लोगों की आवाज़ उठाने का माध्यम मानकर इस क्षेत्र में आए और हमेशा मानते रहे. और, वे नवांकुर तो और भी ज़्यादा असमंजस में हैं, जो पत्रकारिता की दुनिया में सोचकर कुछ आए थे और देख कुछ और रहे हैं. ऐसे में, 2005 में प्रकाशित संतोष भारतीय की पुस्तक-पत्रकारिता: नया दौर, नए प्रतिमान हमारा मार्गदर्शन करती और बताती है कि हमारे समक्ष क्या चुनौतियां हैं और हमें उनका सामना किस तरह करना चाहिए. चार दशक से भी ज़्यादा समय हिंदी पत्रकारिता को समर्पित करने वाले संतोष भारतीय देश के उन पत्रकारों में शुमार किए जाते हैं, जो देश और समाज से जुड़े प्रत्येक मुद्दे पर निर्भीक, सटीक, निष्पक्ष टिप्पणी करते हैं. पुस्तक-पत्रकारिता: नया दौर, नए प्रतिमान में रविवार से लेकर चौथी दुनिया तक की यात्रा के उनके विभिन्न अनुभव एवं रिपोर्ट्स संकलित हैं, जिनका प्रकाशन हम श्रृंखलाबद्ध तरीके से प्रारंभ कर रहे हैं. उम्मीद है, सुधी पाठकों और पत्रकारिता की दुनिया के साथियों को हमारा यह प्रयास पसंद आएगा.

मेघनाद देसाई

मनमोहन सिंह ने परमाणु समझौते को लेकर जॉर्ज बुश को जब मना लिया, तो सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए थे. उन्होंने अच्छे निर्णयों से पार्टी को 2009 के चुनाव में ज़्यादा अच्छी स्थिति में पहुंचने में मदद की, लेकिन गठबंधन इसके बाद दिक्कत में आ गया. कांग्रेस पार्टी के लोग यह देख नहीं सके कि आख़िर मनमोहन सिंह को दोबारा प्रधानमंत्री क्यों बनाया गया? ऐसा नहीं माना जा रहा था कि उन्हें जीत का श्रेय दिया जाएगा. इस बार ताकत धीरे-धीरे प्रधानमंत्री के हाथों से निकल गई. वहीं 2011 के मध्य में सोनिया गांधी की तबियत खराब हो गई और यूपीए-2 अपने रास्ते से भटक गया.

सिर्फ़ आरोपों से कोई कमजोर नहीं होता

आख़िर किस तरह के प्रधानमंत्री साबित होंगे राहुल गांधी? इससे पहले वह सत्तासीन होने को लेकर नकारात्मक भाव ही जताते रहे हैं. वह सत्ता को जहर का प्याला बताते रहे हैं. इसके अलावा यूपीए-1 और 2 के दौरान जो कुछ भी हुआ, उससे भी उन्होंने खुद को अलग कर लिया और बाहरी आलोचक की तरह सारी घटनाओं की आलोचना करते रहे. एक बात जो देखने वाली है कि इस चुनाव में अगर कुछ आश्चर्यजनक हो जाए और कांग्रेस अगली सरकार बनाने की अवस्था में आ जाए, तो क्या राहुल गांधी एक निर्णायक प्रधानमंत्री साबित होंगे? प्रधानमंत्री की गरिमा को चोट पहुंचाई जा रही है. न सिर्फ़ वर्तमान प्रधानमंत्री के बारे में, जो हाल में प्रकाशित दो किताबों के केंद्र बिंदु रहे, बल्कि इससे पहले के प्रधानमंत्री के बारे में भी.

हाल के समय में एकदम से अटल बिहारी वाजपेयी को सबसे कमजोर प्रधानमंत्री बताया जाने लगा है. यह वही अटल बिहारी हैं, जो कांग्रेस के सबसे प्रिय ग़ैर कांग्रेसी नेता थे. लेकिन, आख़िर किन अर्थों में वह सबसे कमजोर प्रधानमंत्री थे? क्या उन्हें कांग्रेस के मजबूत प्रधानमंत्री के मानदंड पर खरा उतरने के लिए परमाणु बम का न सिर्फ़ परीक्षण करना चाहिए था, वरन् उसे किसी देश पर चला भी देना चाहिए था? या वह इस बात के लिए कमजोर थे कि उन्होंने लाहौर बस की शुरुआत की? भारत के पास नीति वाक्य के तौर पर भले ही सत्यमेव जयते हो, लेकिन देश की राजनीति के मामले में सच्चाई बयान कर दी जाए, तो कई लोगों को झटके का सामना करना पड़ सकता है. बिना किसी दबाव के दूसरों की आत्मकथाएं लिखना, व्यक्तिगत संबंधों का खुलासा करना जैसी हरकतें पश्चिमी पत्रकार करते रहे हैं और उसका निशाना वहां के नेता बनते भी रहे हैं.

ऐसी आत्मकथाएं लिखना और व्यक्तिगत जीवन को उजागर करना पश्चिमी पत्रकारों का काम रहा है, यह हमारे लिए नहीं है. जॉन एफ कैनेडी के प्रेम संबंधों, उनकी स्वास्थ्य समस्याओं

और माफियाओं के साथ उनके रिश्तों को कभी भारतीय पत्रकारों द्वारा नहीं उजागर किया गया. हम अपने नेताओं को पवित्र देखना चाहते हैं, किसी भी तरह के प्रलोभन से रहित. एक अन्य बात यह है कि सरकार किस तरह चलाई जाती है, इसके बारे में कोई भी जानकारी न दी जाए. विशेषतः जब मामला एक विशेष परिवार से जुड़ा हो. यह जानना बहुत ही कठिन है कि नीतियां किस तरह बनाई जाती हैं. यह जानना भी बहुत कठिन होगा कि आख़िर दो जगहों से चलने वाला निर्णय तंत्र कैसे काम करता है? इस बात को थोड़ी आसानी से यूं समझा जा सकता है कि सोनिया गांधी पार्टी की अध्यक्ष थीं और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री, ये सत्ता के दो ध्रुव थे.

इस बात में कोई संदेह नहीं है कि मनमोहन सिंह वही बने, जो उन्हें सोनिया ने बनाया. यहां यह बात भी महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस ने 1989 में गठबंधन की सरकार बनाने से मना कर दिया था, लेकिन जब 2004 में ऐसी सरकार बनाने की बात आई, तो सोनिया गांधी पूरी तरह से तैयार थीं. मैं अब भी मानता हूं कि उन्होंने प्रधानमंत्री न बनकर एक बड़ी गलती की थी. उनके पास पार्टी के अन्य नेताओं से ज़्यादा राजनीतिक समझ है. सत्ता को दो भागों में बांटने का निर्णय भी बेहतरीन था. इस दौरान गठबंधन को बनाए रखने और अच्छी तरह से चलाए जाने का भी बड़ा महत्व था, क्योंकि कांग्रेस को इससे पहले गठबंधन सरकार चलाने का कोई अनुभव नहीं था. यहां पर भी ताकत के दो ध्रुव हो गए थे, पहला कैबिनेट और दूसरा गठबंधन के नेताओं की जमात. पहले के पास सत्ता के अधिकार संवैधानिक रूप से थे, लेकिन दूसरा ज़्यादा ताकतवर था. सोनिया गांधी गठबंधन के चेयरमैन के रूप में दूसरी पार्टी के नेताओं के साथ महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति और हटाने के फ़ैसले लेती थीं. मनमोहन सिंह का ए राजा पर कोई नियंत्रण नहीं था. ए राजा को मंत्री पद दिया जाना सोनिया गांधी और करुणानिधि के बीच हुई बातचीत में तय हुआ था. इस बात से कोई इंकार नहीं है कि यह सब प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर तय होता था. यह सच्चाई है कि भारतीय राजनीति में अब किसी भी प्रधानमंत्री के पास, चाहे वह मोदी भी क्यों न हों, जवाहर लाल नेहरू और इंदिरा जैसे अधिकार नहीं हैं, क्योंकि उन्हें गठबंधन की सरकार चलानी है.

इसके विपरीत अगर अटल बिहारी वाजपेयी के कार्य करने के तरीके काफी हद तक अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन से मिलते-जुलते थे. वह खुद को बड़े रणनीतिक निर्णयों तक सीमित रखते थे और बाकी निर्णय अपने स्टाफ एवं साथियों के लिए छोड़ देते थे. वह अच्छा नेतृत्व कर सके, क्योंकि वह एक करिश्माई व्यक्तित्व के मालिक थे. वहीं मनमोहन सिंह यह जानते थे कि वह मुख्य कार्यकारी हैं और सोनिया गांधी चेयरमैन. यूपीए-1 की सरकार में गठबंधन अच्छी तरह चला, क्योंकि सारी बातें स्पष्ट थीं, पार्टियों की हदें तय थीं और कांग्रेस के सदस्य शक्ति पाकर खुश थे. वे जानते थे कि मनमोहन सिंह एक नियुक्त प्रधानमंत्री हैं.

मनमोहन सिंह ने परमाणु समझौते को लेकर जॉर्ज बुश को जब मना लिया, तो सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए थे. उन्होंने अच्छे निर्णयों से पार्टी को 2009 के चुनाव में ज़्यादा अच्छी स्थिति में पहुंचने में मदद की, लेकिन गठबंधन इसके बाद दिक्कत में आ गया. कांग्रेस पार्टी के लोग यह देख नहीं सके कि आख़िर मनमोहन सिंह को दोबारा प्रधानमंत्री क्यों बनाया गया? ऐसा नहीं माना जा रहा था कि उन्हें जीत का श्रेय दिया जाएगा. इस बार ताकत धीरे-धीरे प्रधानमंत्री के हाथों से निकल गई. वहीं 2011 के मध्य में सोनिया गांधी की तबियत खराब हो गई और यूपीए-2 अपने रास्ते से भटक गया. सोचने वाली बात यह है कि अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो क्या होगा? सीधा जवाब है कि सत्ता परिवार में ही रहेगी और अगर वह केजरीवाल की तरह इस्तीफा भी दे देंगे, तो भी प्रियंका मौजूद हैं ही.■

feedback@chauthiduniya.com

निशंक को भरोसा है कि मोदी लहर के चलते धर्मनगरी हरिद्वार में उनके सभी दाग धुल जाएंगे. वहीं हरीश रावत की धर्मपत्नी रेणुका रावत को पति के जमीनी नेता होने का लाभ मिलने की आशा है.

उत्तर प्रदेश

सियासत में धर्मगुरुओं की शिरकत

संदीप कश्यप

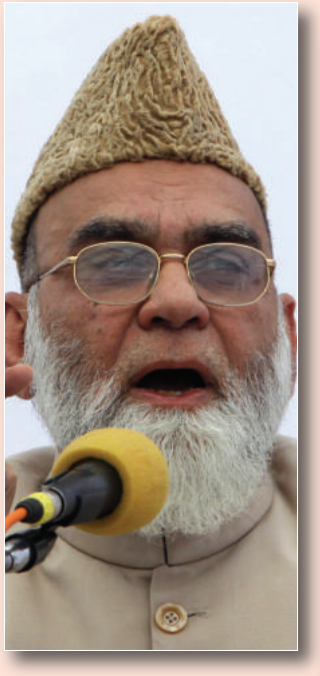

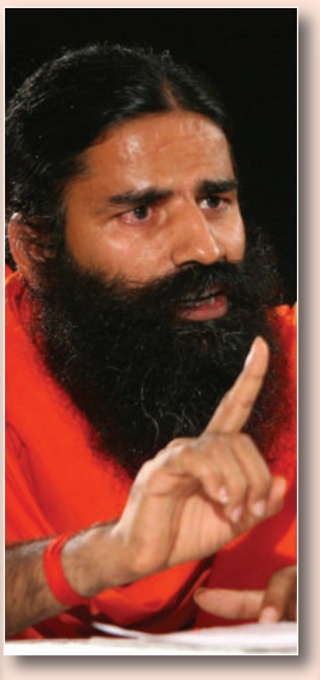

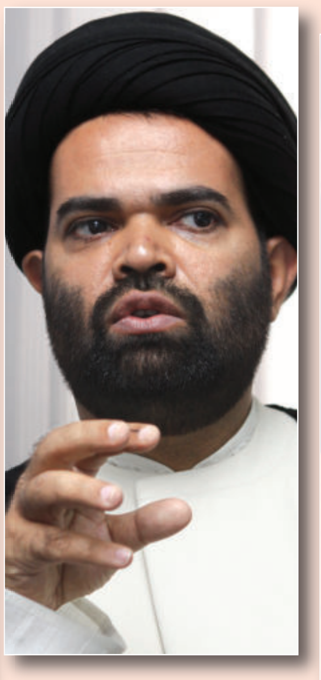

उत्तर प्रदेश का सियासी कारवां तमाम किंतु-परंतु के साथ आगे बढ़ता जा रहा है. नेता बड़े-बड़े दावे कर रहे हैं, जनता सुन रही है. कुछ जगहों पर जनता और नेताओं के बीच विरोधाभास भी देखने को मिल रहा है. राज्य की क़रीब आधी लोकसभा सीटों के मतदाता अपना फ़ैसला ईवीएम में बंद कर चुके हैं. मतदान का अंतिम दौर 12 मई को ख़त्म हो जाएगा. 16 मई को जब नतीजे आएंगे, तब नेताओं की हकीकत से पर्दा उठेगा, लेकिन जातिवाद-सांप्रदायवाद को भुनाने की तमाम दलों के नेताओं की जो कसरत राजनीति की पिच पर हुई, वह अपने पीछे कई सवाल खड़े कर गई है. आम आदमी तो यही नहीं समझ पा रहा है कि राष्ट्रभक्ति बड़ी होती है या फिर धर्म की शक्ति. चुनाव देश के विकास एवं खुशहाली के लिए हो रहा है, लेकिन नेता धर्मगुरुओं की चौखट पर दस्तक दे रहे हैं. अच्छा हुआ, जो देवबंद और नदवा जैसी ख्यातिप्राप्त संस्थाओं ने चुनावी मौसम तक अपने दरवाजे नेताओं के लिए बंद कर दिए. कुछ हिंदू एवं अन्य धर्मों के प्रमुख भी राजनीति से दूरी बनाकर चल रहे हैं, लेकिन कई धर्मगुरु ऐसे भी हैं, जिन्हें इबादत की जगह सियासत की पिच पर बैटिंग करने में ज़्यादा मजा आता है. बाबा रामदेव, योगी आदित्य नाथ, साक्षी महाराज, उमा भारती, जामा मस्जिद के इमाम अहमद बुखारी, कल्बे रुशैद, तौकीर रजा एवं मदनी आदि राजनीति के क्षितिज पर कभी तेजी से और कभी हल्के चमकते रहते हैं. धर्म के साथ रहकर राजनीति करने के कारण इन धर्मगुरुओं को आलोचना भी झेलनी पड़ती है. जामा मस्जिद के इमाम तो कब किस पार्टी के पक्ष में अपील जारी कर दें, कोई नहीं जानता. यही वजह थी समाजवादी पार्टी से नाराज़ बुखारी ने कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग करने की अपील की, तो भारतीय जनता पार्टी ने उनका विरोध किया ही, कई नामचीन मुस्लिम हस्तियां भी बुखारी के ख़िलाफ़ सामने आ गईं.

चुनाव देश के विकास एवं खुशहाली के लिए हो रहा है, लेकिन नेता धर्मगुरुओं की चौखट पर दस्तक दे रहे हैं. अच्छा हुआ, जो देवबंद और नदवा जैसी ख्यातिप्राप्त संस्थाओं ने चुनावी मौसम तक अपने दरवाजे नेताओं के लिए बंद कर दिए. कुछ हिंदू एवं अन्य धर्मों के प्रमुख भी राजनीति से दूरी बनाकर चल रहे हैं, लेकिन कई धर्मगुरु ऐसे भी हैं, जिन्हें इबादत की जगह सियासत की पिच पर बैटिंग करने में ज़्यादा मजा आता है. बाबा रामदेव, योगी आदित्य नाथ, साक्षी महाराज, उमा भारती, जामा मस्जिद के इमाम अहमद बुखारी, कल्बे रुशैद, तौकीर रजा एवं मदनी आदि राजनीति के क्षितिज पर कभी तेजी से और कभी हल्के चमकते रहते हैं. धर्म के साथ रहकर राजनीति करने के कारण इन धर्मगुरुओं को आलोचना भी झेलनी पड़ती है. जामा मस्जिद के इमाम तो कब किस पार्टी के पक्ष में अपील जारी कर दें, कोई नहीं जानता.

बुखारी के बयान का उत्तर प्रदेश में असर हुआ, उनकी अपील पर मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिए, ऐसा लगता तो नहीं है, लेकिन असलियत तो ईवीएम ही बताएंगी. बुखारी के बयान पर शिया धर्मगुरु एवं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष मौलाना कल्बे सादिक का कहना था कि उनकी नज़र में बुखारी मुनासिब शख्स नहीं हैं, वह एक बिकाऊ माल हैं. चुनाव के समय ऐसे शख्स की अपील का कोई महत्व नहीं हो सकता. सब जानते हैं कि जामा मस्जिद की इमामत भी उन्होंने हाईजैक की है. पिछले दिनों भाजपा के अध्यक्ष एवं लखनऊ से प्रत्याशी राजनाथ सिंह भी मौलाना कल्बे जव्वाद के पास गए थे, लेकिन जव्वाद ने उन्हें कोई भरोसा नहीं दिया. ऑल इंडिया मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड की अध्यक्ष शाइस्ता अंबर कहती हैं कि मुसलमान खुद समझदार हैं, सही और गलत की पहचान कर सकते हैं. ऐसे में किसी दल या नेता को वोट देने की अपील बेअसर ही रहेगी. फिर अहमद बुखारी की मुसलमान क्यों सुनें, जब वह खुद किसी एक के नहीं हैं. बुखारी की अपील पर आगबबूला हुए देवबंदी उलेमाओं का कहना था कि मुसलमान कांग्रेस पार्टी के बंधुआ मज़दूर नहीं हैं. अरबी के विद्वान मौलाना नदीमुलवाजदी ने कहा कि इमाम की अपील सरासर गलत है. दारूल उलूम वक्फ के वरिष्ठ उस्ताद मौलाना मुफ्ती आरिफ कासमी ने कहा कि जनता खुद फ़ैसला करे कि उसके वोट का सही हक़दार कौन है.

पिछले दिनों भाजपा के अध्यक्ष एवं लखनऊ से प्रत्याशी राजनाथ सिंह भी मौलाना कल्बे जव्वाद के पास गए थे, लेकिन जव्वाद ने उन्हें कोई भरोसा नहीं दिया. ऑल इंडिया मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड की अध्यक्ष शाइस्ता अंबर कहती हैं कि मुसलमान खुद समझदार हैं, सही और गलत की पहचान कर सकते हैं. ऐसे में किसी दल या नेता को वोट देने की अपील बेअसर ही रहेगी. फिर अहमद बुखारी की मुसलमान क्यों सुनें, जब वह खुद किसी एक के नहीं हैं. बुखारी की अपील पर आगबबूला हुए देवबंदी उलेमाओं का कहना था कि मुसलमान कांग्रेस पार्टी के बंधुआ मज़दूर नहीं हैं. अरबी के विद्वान मौलाना नदीमुलवाजदी ने कहा कि इमाम की अपील सरासर गलत है.

लखनऊ ईदगाह के इमाम एवं इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली का कहना था कि बुखारी भाजपा का भी समर्थन कर चुके हैं. मुसलमान मतदाता अब जागरूक हो चुके हैं, उन पर अहमद बुखारी की अपील का कोई असर नहीं पड़ने वाला. मोमिन अंसार सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद अकरम अंसारी ने कहा कि मुसलमान अब जागरूक हैं, वे राजनीतिक पार्टियों एवं उनके उम्मीदवारों को अच्छी तरह समझते हैं. अहमद बुखारी की अपील से कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि नुकसान हो सकता है. मुसलमान अब उसे वोट करेगा, जो सुरक्षा, न्याय, रोज़गार की बात करेगा. मुसलमान पिछले 65 सालों में सिर्फ़ सियासी पार्टियों की नहीं, उलेमा की नीयत भी समझ चुका है. शिया चांद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना सैफ अब्बास नकवी ने कहा कि अहमद बुखारी मुसलमानों के ठेकेदार नहीं हैं. इस तरह के उलेमा वोटरों को गुमराह करने में कामयाब ज़रूर होते हैं, लेकिन उनका ज़्यादा असर नहीं होता. चुनाव के दौरान दिल्ली के शाही इमाम का बयान बचकाना है.■

feedback@chauthiduniya.com

उत्तराखंड

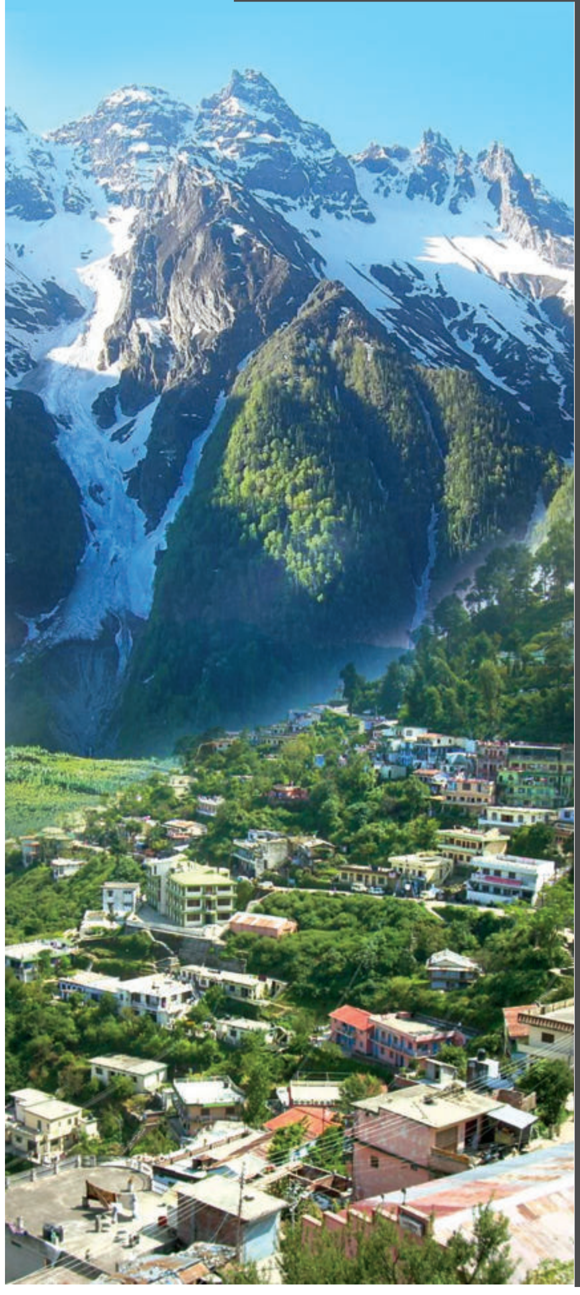

निशंक और हरक पर विवादों का साया

भाजपा नेता रमेश पोखरियाल निशंक को हरिद्वार में रेणुका रावत के सामने और कांग्रेस के डॉ. हरक सिंह रावत को पौड़ी से जनरल भुवन चंद्र खंडूडी के मुकाबले चुनाव मैदान में उतारा गया है. इन दोनों नेताओं (निशंक-हरक) का विवादों से गहरा नाता रहा है. रमेश पोखरियाल निशंक भाजपा शासन के दौरान हुए भ्रष्टाचार, तो हरक सिंह रावत निजी ज़िंदगी से लेकर भ्रष्टाचार तक के आरोपों से घिरे रहे हैं. इसलिए इन दो प्रत्याशियों को लेकर दोनों दलों को एक-दूसरे पर निशाना साधने का मौक़ा मिल रहा है.

राजकुमार शर्मा

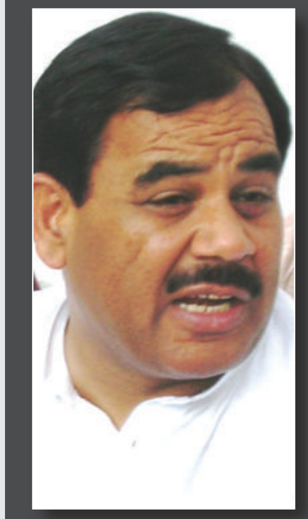

कुछ माह पहले एक स्थानीय गायिका से भी उनका नाम जोड़ा गया. बहुगुणा सरकार के जमाने में उनके आवास पर हुई एक दावत में कांग्रेस विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन ने कांग्रेस नेता विवेकानंद खंडूडी पर गोली चला दी थी. यह मामला भी काफी चर्चा में रहा. पौड़ी में भाजपा और अन्य दल इन सब मामलों को लेकर हरक सिंह को घेरने की तैयारी में हैं.

यह बात अब साफ़ हो गई है कि भाजपा-कांग्रेस दोनों में कोई भी दूध का धुला नहीं है, दोनों राष्ट्रीय दलों के दागी नेता चुनाव मैदान में हैं. भाजपा और कांग्रेस ने इस लोकसभा चुनाव में दो ऐसे नेताओं को मैदान में उतारा है, जो हमेशा विपक्ष के निशाने पर रहे हैं. भाजपा नेता रमेश पोखरियाल निशंक को हरिद्वार में रेणुका रावत के सामने और कांग्रेस के डॉ. हरक सिंह रावत को पौड़ी से जनरल भुवन चंद्र खंडूडी के मुकाबले चुनाव मैदान में उतारा गया है. इन दोनों नेताओं (निशंक-हरक) का विवादों से गहरा नाता रहा है. रमेश पोखरियाल निशंक भाजपा शासन के दौरान हुए भ्रष्टाचार, तो हरक सिंह रावत निजी ज़िंदगी से लेकर भ्रष्टाचार तक के आरोपों से घिरे रहे हैं. इसलिए इन दो प्रत्याशियों को लेकर दोनों दलों को एक-दूसरे पर निशाना साधने का मौक़ा मिल रहा है. रमेश पोखरियाल निशंक की तो पीएचडी की डिग्री विवादित रही है.

आरोप है कि निशंक बिना पीएचडी किए फर्जी तौर पर अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखते चले आ रहे हैं. पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने उनके कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार के कई मामलों को मुद्दा भी बनाया था. यहां तक कि कांग्रेस ने जिन 419 घोटालों का आरोप-पत्र बनाकर राष्ट्रपति को सौंपा था, उनमें से अधिकांश निशंक के समय के थे. स्टर्डिया भूमि घोटाला, 56 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स का आवंटन, 2011 की दैवीय आपदा और हरिद्वार का कुंभ घोटाला आदि मामलों को लेकर कांग्रेस भाजपा, खासकर निशंक को घेरती रही है. ये मामले उत्तराखंड के जाने-माने लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी ने अपने गीतों के जरिये भी उठाए थे.

देखना यह है कि इन मामलों को हरिद्वार में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी मुद्दा बना पाते हैं या नहीं. पौड़ी से कांग्रेस के प्रत्याशी हरक सिंह रावत तिवारी सरकार के समय राजस्व मंत्री थे, लेकिन जेनी कांड में फंसने के बाद उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ा था. बाद में मामले की सीबीआई जांच में वह आरोपों से बरी हो गए थे. 2007 में जब हरक नेता प्रतिपक्ष बने, तो उन पर विकास नगर में क़रीब 100 बीघा भूमि गलत तरीके से हथियाने का आरोप लगा. कृषि मंत्री बनने के बाद वह शिक्षा विभाग की इजाजत के बगैर एक बीईओ दमयंती रावत एवं एक रिश्तेदार प्रधानाचार्य यशवंत सिंह रावत को कृषि विभाग में लाने और मंत्री होने के बावजूद तराई बीज विकास निगम, पूर्व सैनिक कल्याण निगम आदि में लाभ के पद लेने के मामले में विवादित रहे. यही नहीं, पीआरओ युद्धवीर हत्याकांड में हरक सिंह नाम उछलने पर भी तत्कालीन सरकार को विपक्ष का हमला झेलना पड़ा. कुछ माह पहले एक स्थानीय गायिका से भी उनका नाम जोड़ा गया. बहुगुणा सरकार के जमाने में उनके आवास पर हुई एक दावत में कांग्रेस विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन ने कांग्रेस नेता विवेकानंद खंडूडी पर गोली चला दी थी. यह मामला भी काफी चर्चा में रहा. पौड़ी में भाजपा और अन्य दल इन सब मामलों को लेकर हरक सिंह को घेरने की तैयारी में हैं.

निशंक को भरोसा है कि मोदी लहर के चलते धर्मनगरी हरिद्वार में उनके सभी दाग धुल जाएंगे. वहीं हरीश रावत की धर्मपत्नी रेणुका रावत को पति के जमीनी नेता होने का लाभ मिलने की आशा है. निशंक को त्रिकोणात्मक संघर्ष के साथ-साथ पार्टी का भितरघात भी झेलना पड़ रहा है. उधर हरक समर्थकों का कहना है कि उन्हें युवा होने का लाभ मिल रहा है.■

feedback@chauthiduniya.com

अगर मोदी वाजपेयी की तरह विदेश नीति का मॉडल तैयार करना चाहते हैं, तो उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ेगी. हालांकि, वाजपेयी की विदेशी नीति से अगर आगाज की जाए, तो यह एक अच्छी शुरुआत कही जाएगी. दक्षिणपंथी पार्टी की पृष्ठभूमि होने के बावजूद वाजपेयी ने आवश्यकता अनुसार लचीलापन अपनाया. पाकिस्तान से कटु संबंधों के बावजूद उन्होंने वार्ता की पहल की.

चंदन कुमार

यूक्रेन से बढ़ रहा शीतयुद्ध का ख़तरा

जेनेवा संधि से निकली उम्मीद की अच्छी किरण के बावजूद यूक्रेन समस्या अब और भी खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है. हालांकि, यह कयास उसी वक्त लगाया गया, जब अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि इस समय हम किसी भी पक्ष को लेकर आश्वस्त नहीं हो सकते.

रूस, यूक्रेन और पश्चिम के बीच हुए जेनेवा संधि के तहत कहा गया था कि पूर्वी यूक्रेन में अवैध तरीके से हथियारों से लैस रूस समर्थक लोगों को हथियार डालने के लिए कहा जाएगा. साथ ही, जिन लोगों ने सरकारी इमारतों पर कब्जा किया है, वे भी समर्पण करेंगे. हालात यह है कि रूस में क्रीमिया के विलय के बाद यूक्रेन के कई सरकारी इमारतों पर हथियारबंद रूसी समर्थकों का कब्जा है और कई इलाकों में हिंसा की घटना लगातार हो रही है. सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि यूक्रेन में अस्थिरता की स्थिति पैदा हो गई. दरअसल, सारी कहानी 2014 के फरवरी महीने से शुरू होती है. यह विरोध एक व्यापारिक समझौते की उपज है. पिछले एक साल से राष्ट्रपति विक्टर यानुकोव्युच ने जोर दिया कि यूरोपीय संघ से ऐतिहासिक राजनीतिक और व्यापारिक समझौते के लिए वे इच्छुक हैं. लेकिन, पिछले साल 21 नवंबर को उन्होंने यूरोपीय संघ (ईयू) से वार्ता को निलंबित कर दिया.

ईयू से समझौते के समर्थकों का कहना था कि इससे राजनीतिक संबंध और आर्थिक विकास तेज होती. यूक्रेन की सीमा व्यापार के लिए खुल जाती और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया तेज होती. यहां ध्यान देने वाली बात है कि आखिर वो कौन-सी वजहें थीं, जिससे यूक्रेन के राष्ट्रपति को अपना कदम पीछे लेना पड़ा. इनमें सबसे बड़ी वजह थी रूस का विरोध. रूस ने अपने छोटे पड़ोसी देश को धमकी दी कि अगर वह समझौते पर आगे बढ़ता है, तो उस पर व्यापारिक पाबंदी लगा दी जाएगी. साथ ही, गैस की आपूर्ति पर भी रोक लगा दी जाएगी. वहीं, अगर वह रूस के साथ जुड़ता है तो उसे प्राकृतिक गैस पर भारी छूट मिलेगी. इसके अलावा एक और प्रमुख वजह थी, जो निहायत ही व्यक्तिगत और राजनीतिक भी थी. दरअसल, ईयू राष्ट्रपति विक्टर यानुकोव्युच से उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक विरोधी और पूर्व प्रधानमंत्री यूलिया तामोशेंको की रिहाई की मांग कर रहा था. यानुकोव्युच इसकी लगातार अनदेखी कर रहे थे. दो साल पहले यूलिया तामोशेंको को रूसी गैस समझौते में अपने पद का दुरुपयोग करने का दोषी पाया गया था और उन्हें सात साल की सजा सुनाई गई थी. इस घटना को व्यापक तौर पर राजनीतिक से प्रेरित बताया जा रहा था.

> ईयू से समझौते के समर्थकों का कहना था कि अगर यूक्रेन-ईयू के बीच समझौता होता है, तो राजनीतिक संबंध और आर्थिक विकास तेज होती. यूक्रेन की सीमा व्यापार के लिए खुल जाती. यहां ध्यान देने वाली बात हैं कि आखिर वो कौन-सी वजहें थीं, जिससे यूक्रेन के राष्ट्रपति को अपना कदम पीछे लेना पड़ा. इनमें सबसे बड़ी वजह थी रूस का विरोध. रूस ने अपने छोटे पड़ोसी देश को धमकी दी कि अगर वह समझौते पर आगे बढ़ता हैं, तो उस पर व्यापारिक पाबंदी लगा दी जाएगी. साथ ही, गैस की आपूर्ति पर भी रोक लगा दी जाएगी. अगर वह रूस के साथ जुड़ता हैं तो उसे प्राकृतिक गैस पर भारी छूट मिलेगी.

इस घटना के बाद यूक्रेन के अधिकांश लोगों में गुस्से की लहर फैल गई. वे सड़कों पर उतर आए और यानुकोव्युच के ईयू से समझौता करने की मांग करने लगे. विपक्ष की मांग जोड़ पकड़ने लगी. यहां सबसे बड़ी समस्या यह थी कि विपक्ष का नेता कोई एक शख्सीयत नहीं था. कई दलों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया था. फिर भी उनमें पहला नाम आता है वितालीं क्लित्श्चको का. वह पूर्व बॉक्सिंग चैंपियन थे. क्लित्श्चको के विरोध ने यूक्रेन में अशांति की लहर फैला दी. इसके बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति रूस भाग गए और उन्होंने रूस के साथ मिलकर एक समझौता किया. इस समझौते के तहत पुतिन ने यूक्रेन के 15 अरब डॉलर के कर्ज को माफ करने और कम कीमतों पर गैस देने की घोषणा की. इसके बावजूद जब विरोध बंद नहीं हुआ, तो उन्होंने प्रदर्शन को खत्म करने के लिए दमन विरोधी नीति अपनाई. विरोध- प्रदर्शनों के बीच विपक्षी दल संसद में एक कानून में संशोधन चाहते थे. इसके तहत राष्ट्रपति के अधिकारियों को सीमित करने और 2004 के संविधान की पुनर्बहाली की मांग की गई थी. लेकिन, संसद ने ऐसा करने से साफ इंकार कर दिया. नतीजतन हिंसा का एक लंबा दौर शुरू हो गया.

अब ताजा हालात यह है कि रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया का विलय कर लिया है. रूस का इरादा है एक दिन रूसी बोलने वाले लोगों को फिर से एक संयुक्त मुल्क में साथ लाना. इनमें यूक्रेन की सीमाओं में रहने वाले रूसी भाषी भी शामिल हैं. यह पुतिन के अपने विचारों और उनके जैसा सोचने वालों के विचारों से झलकता है. कुशल रणनीतिकार के रूप में पुतिन जानते हैं कि इस महात्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए पूरा जोर लगाना रूस के लिए नुकसानदेह हो सकता है, जैसा कि कड़े प्रतिबंध लगाने की पश्चिमी देशों की धमकी और रूसी गैस आपूर्ति से आजाद होने की यूरोप की कोशिशों में दिखता है.जेनेवा में पिछले हफ्ते यूक्रेन पर हुए समझौते पर दस्तखत करना और पश्चिमी देशों को यह दिखाना कि वह समझौते के लिए तैयार है, रूस के लिए रणनैतिक महत्व रखता है. अगले चुनाव को होने में चार साल बाकी हैं और उसमें पुतिन के फिर से 6 साल के लिए जीतने की संभावना है. इसे देखते हुए पुतिन के पास समय है जो उन्हें उनके पश्चिमी प्रतिद्वंद्वियों पर बढ़त देता है, जिनकी नीतियां उनके कार्यकाल को देखते हुए छोटी अवधि की हैं. पुतिन का लंबा खेल यह है कि वे यूक्रेन पर किसी सैन्य विवाद में फिलहाल नहीं फंसना चाहेंगे. इसका मतलब यह है कि यूरोपीय देशों को इसके लिए तैयार रहना होगा कि प्रतिबंधों से रूस के साथ उनका कारोबारी रिश्ता जटिल हो सकता है. 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद पूरी दुनिया में अमेरिका की बादशाहत कायम हो गई थी. उसके बाद यूरोपीय संघ, अमेरिका और चीन के रूप आर्थिक, सामरिक और राजनीतिक शक्ति का उदय हुआ. पुतिन अब सोवियत संघ के समय की शक्तिशाली रूस की कल्पना कर रहे हैं. वे अमेरिका, यूरोपीय संघ और चीन की ही तरह रूस को वैश्विक आर्थिक सत्ता का केंद्र बनाना चाहते हैं. यही वजह है कि पहले वे उन इलाकों को रूस में मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो पहले सोवियत संघ का हिस्सा थे. फिलहाल मामला यह है कि यूक्रेन को लेकर रूस और पश्चिमी देशों में एक तनाव की स्थिति बन चुकी है. जेनेवा संधि को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान यह बतलाता है कि यूक्रेन से एक ऐसी समस्या उत्पन्न हो गई, जो पूरी दुनिया को फिर शीतयुद्ध काल की ओर ले जाता दिख रहा है.■

feedback@chauthiduniya.com

...तो ऐसी होगी मोदी की विदेश नीति

नरेंद्र मोदी ने 9 अप्रैल को कोलकाता में अपनी रैली के दौरान पाकिस्तान के मुद्दे पर कहा कि एक तरफ भारतीय सैनिकों का गला काटा जा रहा है और दूसरी ओर पाकिस्तान के लोगों के सम्मान में भोज आयोजित किया जा रहा है. वहीं, इतालवी सैनिकों से संबंधित विवाद पर उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने दो इतालवी सैनिकों को वोट डालने के लिए अपने देश जाने दिया. यहां भारत में विचाराधीन कैदियों को अपनी मां के अंतिम संस्कार में भी शामिल होने की इजाजत नहीं दी जाती. वहीं 22 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश में चीन पर टिप्पणी करते हुए भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार मोदी ने कहा कि चीन को अपना विस्तारवादी सोच खत्म कर भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को दोनों देशों की शांति, समृद्धि और प्रगति के लिए आगे बढ़ाना चाहिए. देवयानी मामले पर अमेरिका के प्रति नरम पड़े भारत के रुख पर मोदी सवाल उठा चुके हैं. नरेंद्र मोदी के इन बयानों से अगर अंदाजा लगाया जाए, तो कुछ लोग यह मान सकते हैं कि मोदी ने विदेश नीति के मामले में एक ठोस बात कहने की जगह एक सामान्य टिप्पणी भर की है. हालांकि, उसके बाद मोदी ने विदेश मामलों पर कुछ खास बयान नहीं दिया है. एक तरह से यह सही भी है, क्योंकि अमेरिका की तरह भारत में विदेश नीति चुनाव का महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं होता है. इससे पहले मोदी ने पिछले साल अक्टूबर में विदेश नीति की आलोचना करते हुए कहा था कि मौजूदा सरकार उन जगहों पर असंवेदनशील है, जहां उसे संवेदनशील नीति अपनानी चाहिए और जहां मजबूत होना चाहिए, वहां कमजोर है. अगर ऐसा है तो चीन मामले पर मोदी की टिप्पणी को गंभीर माना जा सकता है. अगर चीन के प्रति मोदी के पुराने रुख पर नजर डालें, तो एक विरोधाभास नजर आता है. गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी ने कम से कम चार बार चीन का दौरा किया. 2011 में उन्होंने कहा भी था कि चीन और वहां की जनता के लिए उनके दिल में खास जगह है. किसी राष्ट्रवादी पार्टी के नेता का चीन की तरफ झुकाव वाला बयान कई लोगों को अजीब लग सकता है. हालांकि, बतौर एक प्रशासक मोदी ने पूरी दुनिया में अपने राज्य के लिए प्रगतिशील और सक्रिय संबंध बनाने की कोशिश की है. अपने प्रचार-प्रसार में भी उन्होंने अपनी छवि एक मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करने की कोशिश की है, न कि एक कट्टर नेता मोदी की. भाजपा जैसी राष्ट्रवादी पार्टी से जुड़ाव होने के बावजूद मोदी की विदेश आर्थिक मुद्दों पर अधिक केंद्रित होने वाली है, न कि सुरक्षा पर. हालांकि, भारत के राष्ट्रीय हित की बात करना उनकी राजनीतिक विचारधारा के मुफीद है. लेकिन, मोदी संभवतः यह समझते हैं कि बतौर प्रधानमंत्री अर्थव्यवस्था और व्यापार को सुदृढ़ करना उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए.

> गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी ने कम से कम चार बार चीन का दौरा किया. 2011 में उन्होंने कहा भी था कि चीन और वहां की जनता के लिए उनके दिल में खास जगह है. किसी राष्ट्रवादी पार्टी के नेता का चीन की तरफ झुकाव वाला बयान कई लोगों को अजीब लग सकता है. हालांकि, बतौर एक प्रशासक मोदी ने पूरी दुनिया में अपने राज्य के लिए प्रगतिशील और सक्रिय संबंध बनाने की कोशिश की है. अपने प्रचार-प्रसार में भी उन्होंने अपनी छवि एक मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करने की कोशिश की है, न कि एक कट्टर नेता की.

पिछले साल अक्टूबर के भाषण में मोदी ने भाजपा नेता और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रति सम्मान जताया था. वाजपेयी की विदेश नीति को उन्होंने शांति और शक्ति का संपूर्ण मिश्रण बताया था. वाजपेयी ने प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद 1998 में परमाणु परीक्षण किया, जिसके बाद भारत पर कई अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध लगे. उसके अगले साल करगिल में भारत और पाकिस्तान के बीच चौथी लड़ाई हुई. जंग के दो साल बाद वाजपेयी ने पाकिस्तान के सैन्य शासक और करगिल घुसपैठ के मास्टरमाइंड मुशर्रफ को वार्ता के लिए भारत आमंत्रित किया. वाजपेयी ने चीन का भी दौरा किया और कहा कि वे दोनों देशों के बीच सीमा विवाद का राजनीतिक समाधान के पक्षधर हैं. यह वाजपेयी ही थे, जिन्होंने दो दशक बाद भारत दौरे पर आने वाले किसी अमेरिकी राष्ट्रपति (बिल क्लिंटन) की अगुवाई की और इसके बाद भारत-अमेरिका संबंधों का एक नया दौर शुरू हुआ.

अगर मोदी वाजपेयी की तरह विदेश नीति का मॉडल तैयार करना चाहते हैं, तो उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ेगी. हालांकि, वाजपेयी की विदेशी नीति से अगर आगाज की जाए, तो यह एक अच्छी शुरुआत कही जाएगी. दक्षिणपंथी पार्टी की पृष्ठभूमि होने के बावजूद वाजपेयी ने आवश्यकता अनुसार लचीलापन अपनाया. पाकिस्तान से कटु संबंधों के बावजूद उन्होंने वार्ता की पहल की. वाजपेयी ने शीतयुद्ध काल के बाद की वास्तविकता का सटीक अनुमान किया और उसके साथ सामंजस्य स्थापित किया. खुद की राजनीतिक चुनौतियों के कारण मोदी व्यावहारिक रुख अपना सकते हैं. हालांकि, 2002 के गुजरात दंगा मामले में आरोपों-आलोचनाओं को झेल रहे मोदी खुद की एक ऐसी वैकल्पिक छवि पेश रहे हैं, जो सिर्फ आर्थिक विकास की बात करता है. आर्थिक चिंता तो निश्चित तौर पर प्राथमिकता में रहेगी. अगर मोदी चुनावों में विजयी होते हैं, तो उन्हें विरासत में एक ऐसी अर्थव्यवस्था मिलेगी, जिसकी जीडीपी वर्ष 2000 में 9 फीसदी से इस साल के आखिरी तिमाही में 4.7 फीसदी तक पहुंच चुकी है. मुद्रास्फीति की दर 9 फीसदी तक पहुंच चुकी है, जबकि उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति घट गई है. यह साफ है कि मोदी की बिजनेस फ्रेंडली छवि ही पर्याप्त नहीं होगी, अर्थव्यवस्था में ढांचागत बदलाव की जरूरत होगी. ऐसा करने के लिए मोदी वही रणनीति अपनाएंगे, जो उन्होंने बतौर मुख्तमंत्री अपनाई थी. वे आर्थिक मुद्दों पर जापान, सिंगापुर, अफ्रीकी देशों और यहां तक कि चीन से भी संबंध बनाएंगे.■

चंदन कुमार
feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
CHAUTHI DUNIYA

चौथी दुनिया की हर खबर अब आपके Android फोन पर भी उपलब्ध,
Play Store से Download करें | CHAUTHI DUNIYA APP

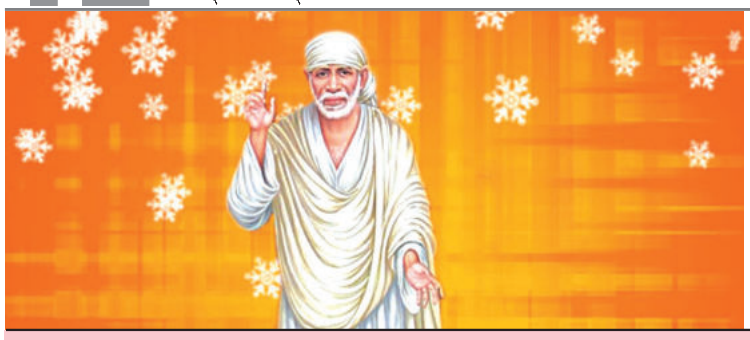

साईं बाबा अपने भक्तों को एक अज्ञात शक्ति द्वारा अपने खींचकर उन्हें एक माता की तरह प्रेम करते हैं. भक्तों को अनुभव हो जाता है कि बाबा का वरदहस्त उनके सिर पर है. यह बाबा की कृपा-दृष्टि का परिणाम है कि उन्हें सदैव सहायता प्राप्त होती रहती है.

साईं की लीला अपरंपार

चौथी दुनिया ब्यूरो

साईं बाबा के चरण धन्य हैं और उनका स्मरण सुखदायी है. साईं बाबा के भवभय विनाशक स्वरूप का दर्शन करके भक्त धन्य हो जाते हैं. बाबा के भक्त उनके श्रीचरणों में श्रद्धा रखें, तो उन्हें बाबा का प्रत्यक्ष अनुभव होता है. साईं बाबा अपने भक्तों को एक अज्ञात शक्ति द्वारा अपने खींचकर उन्हें एक माता की तरह प्रेम करते हैं. भक्तों को अनुभव हो जाता है कि बाबा का वरदहस्त उनके सिर पर है. यह बाबा की कृपा-दृष्टि का परिणाम है कि उन्हें सदैव सहायता प्राप्त होती रहती है. जब मन में अहंकार भर जाता है, तो उच्चकोटि के विद्वान एवं चतुर पुरुष भी इस भवसागर के दलदल में फंस जाते हैं, लेकिन साईं बाबा अपनी शक्ति से असहाय एवं सुहृदय भक्तों को इस दलदल से बाहर निकाल कर उनकी रक्षा करते हैं. साईं बाबा आज भी अदृश्य रहते हुए भक्तों का कल्याण कर रहे हैं. बाबा के संपूर्ण जीवन के बारे में कोई नहीं जान सका. इसलिए यही श्रेष्ठ है कि हमें हृदय से साईं के श्रीचरणों में आकर उनकी आराधना करनी चाहिए. पापों से मुक्त होने के लिए एकमात्र साईं नाम का स्मरण करते रहना चाहिए. साईं बाबा निष्काम भक्तों की समस्त इच्छाएं पूर्ण करके उन्हें परमानंद की प्राप्ति करा देते हैं. साईं बाबा के मधुर नाम का उच्चारण ही भक्तों के लिए अत्यंत सुगम पथ है. साईं बाबा के स्मरण से भक्तों में सात्विक गुणों का विकास होगा और

उन्हें विवेक एवं ज्ञान की प्राप्ति होगी. बाबा के स्मरण मात्र से मन का विचलन ख़त्म हो जाएगा. साईं बाबा सदा अपने भक्तों के समीप रहते हैं, चाहे भक्त कहीं भी क्यों न चला जाए, लेकिन वह तो किसी न किसी रूप में पहले ही वहां पहुंच जाते हैं. बाबा एक गुरु के समान अपने शिष्यों की योग्यताओं पर विशेष ध्यान देते हैं. भक्तों के चित्त को तनिक भी डांवाडोल नहीं होने देते और उन्हें उचित उपदेश देकर आत्मानुभूति की ओर प्रेरित करते हैं. साईं बाबा अपने भक्तों के कल्यार्थ उपदेश देते थे. जिन भक्तों ने उनके उपदेशों का पालन किया, वे अपने ध्येय की प्राप्ति में सफल हुए. साईं बाबा जैसे सद्गुरु ही ज्ञान-चक्षुओं को खोलकर आत्मा की दिव्यता का अनुभव करा देने में समर्थ हैं. वह भक्तों की विषय वासना नष्ट कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप भक्तों को ज्ञान की प्राप्ति होती है और वे उन्नति की ओर अग्रसर हो जाते हैं. साईं अपने भक्तों को कष्टों-दु:खों से मुक्त करके उन्हें सुखी बना देते हैं.

ऊदी का प्रताप

नासिक के नारायण मोतीराम जानी बाबा के परम भक्त थे. वह बाबा के दूसरे भक्त रामचंद्र वामन मोडक के अधीन काम करते थे. एक बार वह अपनी माता के साथ शिरडी गए और उन्होंने बाबा के दर्शन किए. बाबा ने उनकी मां से कहा, अब तुम्हारे पुत्र को नौकरी छोड़कर स्वतंत्र व्यापार करना चाहिए. कुछ दिनों में बाबा के वचन सत्य निकले. नारायण जानी ने नौकरी छोड़कर एक उपहार गृह आनंदाश्रम चलाना प्रारंभ कर दिया, जो अच्छी तरह चलने लगा. एक बार नारायण मोती के एक मित्र को बिच्छू ने काट लिया, जिससे उसे असहनीय पीड़ा होने लगी. ऐसे प्रसंगों में ऊदी तो रामबाण मानी जाती है, काटने के स्थान पर केवल उसे लगा ही देना है. नारायण ने उदी खोजी, लेकिन वह कहीं न मिल सकी. उन्होंने बाबा के समक्ष खड़े होकर उनसे सहायता की प्रार्थना की और उनका नाम लेते हुए उनके चित्र के सम्मुख जलती हुई ऊदबत्ती में से एक चुटकी भस्म लेकर उसे अपने मित्र के जख्म पर लेप दिया. उनके हाथ हटाते ही पीड़ा तुरंत मिट गई और दोनों अति प्रसन्न होकर चले गए. साईं बाबा इसी प्रकार अपने सभी भक्तों की रक्षा करते हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

साईं के ग्यारह वचन

1-जो शिरडी आएगा, आपद दूर भगाएगा.
2-चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुःख की पीढ़ी पर.
3-त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा.
4-मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस.
5-मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो.
6-मेरी शरण आ खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए.
7-जैसा भाव रहा जिस मन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का.
8-भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा.
9-आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वही नहीं है दूर.
10-मुझमें लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया.
11-धन्य-धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य.

साईं भक्तों!

आप भी चौथी दुनिया को साईं से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साईं से आप कब और कैसे जुड़े. साईं की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साईं को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साईं भक्त. साईं बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है. साईं बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा
(गौतमबुद्ध नगर), उत्तर प्रदेश,
पिन-201301
ई-मेल feedback@chauthiduniya.com

नवम ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ

भक्तों की पूरी होती हैं कामनाएं

धर्मेंद्र सिंह

भगवान शिव के दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है. भगवान शिव के बारह ज्योतिर्लिंग हैं. हमने आपको अभी तक उनके आठ ज्योंतिर्लिंगों के बारे में बताया. इस बार हम वाराणसी में स्थित बाबा विश्वनाथ के बारे में बताएंगे. वाराणसी पवित्र नदी गंगा के किनारे उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है. वाराणसी को काशी भी कहा जाता है. काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक है. काशी को विश्व के प्राचीनतम शहरों में से एक माना जाता है. ऐसा कहा जाता है कि बाबा विश्वनाथ का मंदिर कई हज़ार सालों से वाराणसी में स्थित है. काशी विश्वनाथ मंदिर का सभी बारह ज्योतिर्लिंगों में विशिष्ट स्थान है. गंगा में स्नान करके बाबा विश्वनाथ के केवल एक दर्शन मात्र से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है.

काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में मान्यता है कि प्रलयकाल के समय भगवान शिव काशी को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं, इसलिए उस समय भी इसका लोप नहीं होता. प्रलयकाल ख़त्म होने के बाद जब नई सृष्टि की रचना होती है, तब भगवान शिव काशी को नीचे उतार देते हैं. काशी को आदि सृष्टि स्थली भी कहा जाता है. इसी स्थान पर भगवान विष्णु ने सृष्टि की उत्पत्ति की कामना लेकर भगवान शिव की तपस्या की थी. भगवान आशुतोष प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु के शयन करने पर उनके नाभि कमल से ब्रह्मा

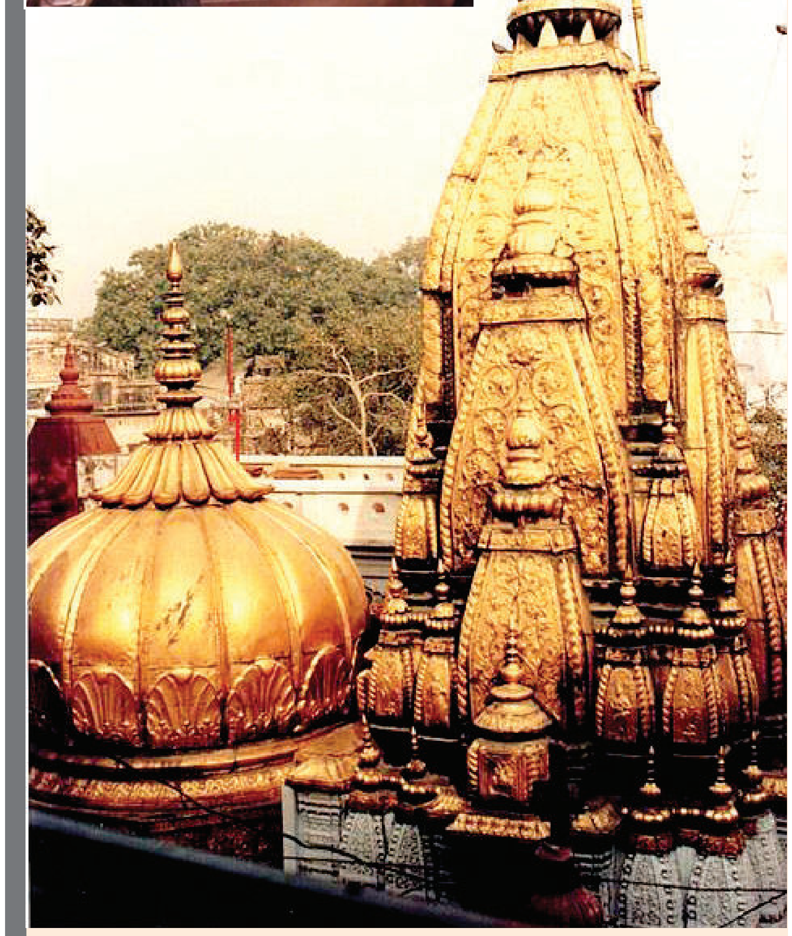

जी की उत्पत्ति हुई, जिन्होंने सृष्टि की रचना की. अगस्त्य मुनि ने भी बाबा विश्वनाथ की कठोर तपस्या की थी. यह भी मान्यता है कि जब पृथ्वी की संरचना हुई, तब प्रकाश की पहली किरण काशी की धरती पर पड़ी थी और इसलिए काशी को ज्ञान एवं आध्यात्म का केंद्र माना जाता है. कहा जाता है कि निर्वासन के कई सालों बाद भगवान शिव यहां आए थे और उन्होंने कुछ समय तक काशी में निवास किया था. ब्रह्मा जी ने उनका स्वागत दस घोड़ों का रथ दशाश्वमेघ घाट पर भेजकर किया था. दशाश्वमेघ घाट विश्वनाथ मंदिर के नज़दीक है. वाराणसी में गंगा के किनारे बहुत सारे घाट हैं और इसीलिए वाराणसी को घाटों का शहर कहा जाता है.

कहते हैं कि काशी में मृत्यु के समय भगवान विश्वनाथ प्राणियों के दाहिने कान में तारक मंत्र का उच्चारण करते हैं. तारक मंत्र सुनकर जीव भव-बंधन से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है. वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के अलावा और भी अनेक दर्शनीय तीर्थ स्थल हैं, जैसे संकट मोचन, अन्नपूर्णा माता, काल भैरव मंदिर, दुर्गा मंदिर (दुर्गा कुंड) एवं तुलसी मानस मंदिर. वाराणसी में प्रतिदिन गंगा आरती होती है, जो देखते ही बनती है. कार्तिक पूर्णिमा (देव दीपावली) के दिन घाटों को सजाया जाता है, भव्य गंगा आरती होती है और घाट दीपों से जगमगाते रहते हैं. हर वर्ष बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए विश्व से लाखों लोग आते हैं. माना जाता है कि काशी में जिसकी मृत्यु होती है, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है.

कैसे जाएं:- काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए वाराणसी जंक्शन जाएं. आप वहां भारत के हर क्षेत्र से रेल एवं सड़क मार्ग से जा सकते हैं. वाराणसी स्टेशन से ऑटो लेकर बाबा विश्वनाथ के मंदिर जा सकते हैं. हवाई मार्ग से जाने के लिए बाबतपुर हवाई अड्डे पहुंच कर वहां से आप टैक्सी, आटो द्वारा वाराणसी जा सकते हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

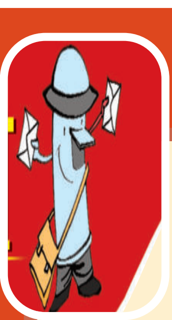

कांग्रेस की हार निश्चित

मनीष कुमार का आलेख-चुनाव से पहले ही राहुल हार गए (21-27अप्रैल) बताता है कि प्रधानमंत्री पद के अघोषित उम्मीदवार राहुल गांधी के नेतृत्व में आम चुनाव लड़ रही कांग्रेस पार्टी की करारी हार होने वाली है. कांग्रेस पार्टी चुनाव प्रचार में भारतीय जनता पार्टी से काफी पीछे है. भाजपा ने अपना चुनाव प्रचार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आम चुनाव से लगभग एक वर्ष पहले शुरू कर दिया था. कांग्रेस यूपीए सरकार की नाकामियों के कारण संकट से जूझ रही है. कांग्रेस में हार का डर इसी से नज़र आता है कि अब उसके नेता सारी मर्यादाएं तोड़कर बयानबाजी पर उतर आए हैं.

-अंकित सिंह, *जौनपुर, उत्तर प्रदेश.*

मुसलमान समझदार हैं

आलेख-कितने असरदार रह गए हैं इमाम बुखारी? (21-27 अप्रैल) पढ़ा. यह पहली बार नहीं है कि चुनाव के समय जामा मस्जिद के शाही इमाम सैय्यद अहमद बुखारी ने मुसलमानों से किसी एक पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए कहा हो. कभी भारतीय जनता पार्टी, तो कभी समाजवादी पार्टी को वोट देने की अपील मुसलमानों से करने वाले इमाम बुखारी ने इस बार कांग्रेस को वोट देने की अपील की. उन्होंने कहा कि सेक्युलर वोटों का बंटवारा नहीं होना चाहिए. सवाल यह है कि मुसलमान क्या किसी के गुलाम हैं कि वे किसी के कहने पर किसी पार्टी विशेष के पक्ष में मतदान करेंगे. वे भी स्वतंत्र हैं. जो पार्टी उनके हित में काम करेगी, वे उसके पक्ष में मतदान करेंगे. रही इमाम बुखारी की बात, तो अब मुसलमान जागरूक हो गए हैं, वे किसी के कहने पर बहकने वाले नहीं. पिछले कई चुनावों में मुस्लिम धर्मगुरुओं ने किसी न किसी पार्टी के पक्ष में मतदान की अपील की, लेकिन मुसलमान अब किसी कहने पर मतदान नहीं करते.

-रियाज अली, *अलीगढ़, उत्तर प्रदेश.*

जनता मालिक है

चौथी दुनिया में प्रकाशित आलेख-लोकसभा: 1952 से अब तक (21-27अप्रैल) पढ़ा. काफी जानकारीपरक है. पता चला कि कब किसने कहां से चुनाव लड़ा और किसे हार का सामना करना पड़ा. इससे साफ़ पता चलता है कि कोई कितना ही बड़ा या लोकप्रिय क्यों न हों, लेकिन जनता जिसे चाहेगी, वही सत्ता तक पहुंचेगा. 1952 से अब तक के चुनाव में लड़ने वाले बड़े-बड़े दिग्गजों और चुनाव परिणामों को देखकर पता चलता है कि राम मनोहर लोहिया जैसे लोकप्रिय नेताओं को भी हार का सामना करना पड़ा. इसलिए इस लोकसभा चुनाव में भी जनता ही फ़ैसला करेगी कि कौन सत्ता पर काबिज होगा.

-राकेश कुमार, *पटना, बिहार.*

एजेंडा बताइए

आलेख-आप इस देश को कैसे चलाएंगे (21-27अप्रैल) में कमल मोरारका ने सही सवाल किया है. यदि आप सत्ता में आते हैं, तो इस देश को कैसे चलाएंगे? लोगों और मीडिया की भविष्यवाणी मानी जाए, तो भाजपा की अगुवाई वाला एनडीए अकेले या दो-तीन सहयोगियों के साथ मिलकर सरकार बना सकता है. आलेख में सही कहा गया है कि हम कई वर्षों से गठबंधन सरकारें देख रहे हैं. हर कोई भ्रष्टाचार, क़ानून-व्यवस्था और कांग्रेस की विफलता की बात करता है, लेकिन समाधान नहीं बताता. अब एक नई, मजबूत सरकार आनी चाहिए, जो देश को पटरी पर ला सके.

-अलका सिंह, *ग्वालियर, मध्य प्रदेश.*

मुद्दाविहीन चुनाव

इस बार नामांकन पत्र में नरेंद्र मोदी द्वारा पत्नी वाले कॉलम में जशोदाबेन का नाम भरने और इससे पहले के चुनावों में यह कॉलम खाली छोड़ देने वाली बात दूसरी पार्टियों के लिए मुद्दा बन गई है. हर एक व्यक्ति की जीवन जीने की अपनी शैली होती है. नरेंद्र मोदी ने अधिक से अधिक समय जनता को देने के लिए अपनी पारिवारिक ज़िम्मेदारी का परित्याग किया था. कांग्रेस नेता एनडी तिवारी जिसे अब तक अपना बेटा नहीं मानते थे, जांच में सही पाए जाने और कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें उसको स्वीकार करना पड़ा. इसलिए कांग्रेस को दूसरों पर आरोप लगाने से पहले एक बार अपनी तरफ़ भी देखना चाहिए और नेताओं को ऐसी बयानबाजी से बचना चाहिए.

-लाल मीणा दास, *पटना, बिहार.*

चौथी दुनिया

सबको भाता है चौथी दुनिया,
हर हफ्ते आता है चौथी दुनिया.
पसंद की सामग्री लाता है चौथी दुनिया,
राजनीति की ख़बरें सुनाता है चौथी दुनिया.
कौन क्या कर रहा, बताता है चौथी दुनिया,
नेताओं का जमावड़ा दिखाता है चौथी दुनिया.
विदेशों की ख़बर सुनाता है चौथी दुनिया,
पर्यटन-साहित्य का रसपान कराता है चौथी दुनिया.
विविध दुनिया का नया रूप दिखाता है चौथी दुनिया,
खेल जगत का आनंद दिलाता है चौथी दुनिया.
बच्चों का संसार, कहानियों की कमी दिखाता है चौथी दुनिया,
यूपी-बिहार का अवलोकन कराता है चौथी दुनिया.

-बद्री प्रसाद वर्मा, *गोरखपुर, उत्तर प्रदेश.*

जनप्रतिनिधि

जिस दल का भी हो लेकिन
हो राष्ट्रप्रेम उसके अंदर,
जाति-धर्म, संप्रदाय से
कार्य करे ऊपर उठकर,
वोट की ख़ातिर इस समाज में
कभी नहीं वह विष घोले,
उन बातों को पूर्ण करें
जितना जनता से वह बोले,
स्वच्छ छवि रखे अपनी
और भ्रष्टाचार से दूर रहे,
सोचे जनता के हित में
नहीं अपने मद में चूर रहे,
शिष्ट आचरण अपनाए वह
संसद का सम्मान करे,
मिर्च का पाऊडर लहरा कर ना
देश का वह अपमान करे,
जब भी अवसर मिले क्षेत्र में
आने का वह प्रयास करे,
उचित तरीके से जितना
हो सके क्षेत्र का विकास करे.

-नंद किशोर शर्मा, *समस्तीपुर, बिहार.*

पाठक पूरा नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने स्वतंत्र विचार व प्रतिक्रियाएं इस पते पर भेजें :
चौथी दुनिया, एफ.2, सेक्टर-11, नोएडा (उत्तर प्रदेश) पिन-201301

देश के जाने-माने लेखकों, साहित्यकारों एवं कलाकारों ने मतदान शुरू होने से पहले भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के ख़िलाफ़ एक अपील जारी की और कहा कि इस चुनाव में वह ताकत सत्ता पर काबिज होने की कोशिश कर रही है, जो घोषित रूप से भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए वचनबद्ध है और एक कथित सांस्कृतिक संगठन का राजनीतिक मोर्चा है.

जादुई यथार्थवाद के चितेरे का जादू

अनंत विजय

एक इंटरव्यू में गाब्रिएल गार्सिया मार्केज से जब पूछा गया था कि अगर किसी लेखक को सफलता या प्रसिद्धि जल्द मिल जाती है, तो यह उसके लेखन के लिए अच्छा है या बुरा? इस पर मार्केज ने कहा था कि लेखक के लिए प्रसिद्धि किसी भी वय में बुरी होती है. मैं तो चाहता हूं कि मेरी किताबें मेरी मृत्यु के बाद प्रसिद्ध हों, खासकर उन देशों में, जहां किताबें भी माल की तरह से खरीदी-बेची जाती हैं. मार्केज की यह ख्वाहिश तो पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि वह अपने जीवन काल में ही इतने मशहूर हो गए. उनकी किताब-वन हंड्रेड ईयर ऑफ सालिड्यूड की, दुनिया के अलग-अलग देशों की भाषाओं में तक़रीबन 5 करोड़ प्रतियां बिक चुकी हैं और लगातार उसकी मांग बनी हुई है. मार्केज की इस किताब को कालजयी उपन्यास का दर्जा हासिल है. स्पेनिश में लिखने वाले इस महान लेखक की अन्य किताबें भी खासी लोकप्रिय रही हैं. मार्केज ने अपने करियर की शुरुआत बतौर पत्रकार की थी और ज़िंदगी के आख़िरी क्षणों तक वह अपने पत्रकार होने पर गर्व करते रहे. मार्केज का मानना था कि पत्रकार को बहुत सोच-विचार कर अख़बार के हितों को ध्यान में रखकर लिखना होता है, वहीं उपन्यासकार को तो अपनी पसंद, विचार और विचारधारा व्यक्त करने की पूरी आज़ादी होती है. अपनी उसी आज़ादी का उन्होंने अपनी रचनाओं में जमकर आनंद उठाया था, चाहे वह वन हंड्रेड ईयर ऑफ सालिट्यूड हो या फिर उनका पहला उपन्यास लीफ स्टॉर्म.

गाब्रियल गार्सिया मार्केज का जन्म एक लातिन अमेरिकी देश कोलंबिया में हुआ था. उनका बचपन सामान्य तरीके से नहीं गुजरा. अपने माता-पिता से अलग उन्हें अपने नाना-नानी के साथ रहना पड़ा था. बाद के दिनों में मार्केज ने माना था कि उनके लेखन पर उनके नाना-नानी की छाप गहरी रही है. कहानियों एवं उपन्यासों के कहने के स्टाइल पर उनकी नानी की किस्सागोई और नाना की विचारधारा की छाप होने की बात भी मार्केज ने स्वीकारी. मार्केज ने माना था कि उनकी रचनाओं में जादुई यथार्थवाद दिखाई देता है, वह उनकी नानी की कहानियों का आवश्यक तत्व हुआ करता था. मार्केज की नानी की कहानियों में अंधविश्वास एवं भूत-प्रेत आदि का समावेश हुआ करता था. उनकी नानी जब कहानी सुनाती थीं, तो उनका अंदाज इस तरह का होता था कि सुनने वाले को घटनाएं और परिस्थितियां एकदम से यथार्थवादी लगा करती थीं, हो चाहे वे बिल्कुल ही काल्पनिक. मार्केज ने अपनी नानी की इस कला में अपनी बौद्धिकता का पुट देकर उसे मैजिकल रियलिज्म के नाम से प्रतिपादित किया. बाद में वह विश्व में एक कला के तौर पर स्थापित हो गई.

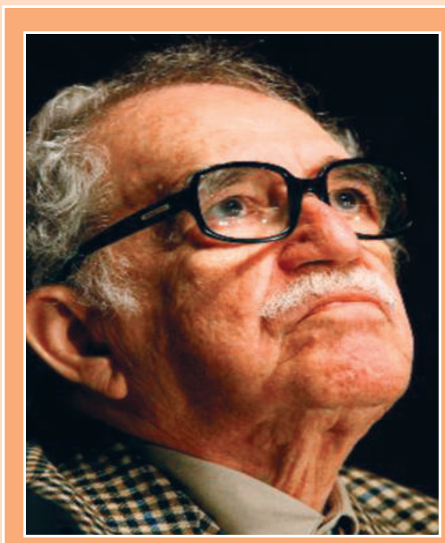

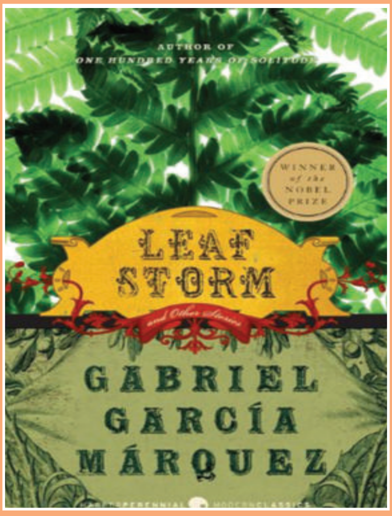

मार्केज का पहला उपन्यास-लीफ स्टॉर्म 1955 में छपा. इस उपन्यास के साथ भी एक दिलचस्प किस्सा जुड़ा हुआ है. उपन्यास लिखने के बाद मार्केज इसके लिए प्रकाशक की तलाश में जुट गए, लेकिन उन्हें लंबे समय तक निराशा हाथ लगी. मार्केज को अपने इस उपन्यास के लिए प्रकाशक मिलने में तक़रीबन सात साल लगे थे. 1949 में मार्केज ने यह उपन्यास लिख लिया था, लेकिन उसका प्रकाशन 1955 में हो सका. इस उपन्यास के प्रकाशन के बाद आलोचकों का ध्यान मार्केज की ओर गया और पाठकों ने इसे खासा पसंद किया. इस छोटे से उपन्यास का पूरा कथानक एक कमरे में बंद है और पूरी कहानी आधे घंटे की है, जिसमें एक कर्नल एक अलोकप्रिय फ्रेंच डॉक्टर को क्रिश्चियन रीति-रिवाजों के मुताबिक दफनाना चाहता है. इस काम में उसे अपनी बेटी और नाती का साथ मिलता है. इस छोटे से उपन्यास का कैनवास इतना बड़ा है कि इस दौरान ही एक बच्चे को मौत का फलसफा और एक महिला की नारीवादी सोच सामने आती है. लीफ स्टॉर्म से मार्केज को पहचान मिली और उनके उपन्यास-द हंड्रेड ईयर ऑफ सालिट्यूड ने उन्हें प्रसिद्धि और पैसा दोनों दिलाया. कहा जाता है कि वन हंड्रेड ईयर ऑफ सालिट्यूड की इतनी प्रतियां छपी हैं कि उससे ज़्यादा प्रतियां सिर्फ़ बाइबल की छपी हैं.

वन हंड्रेड ईयर ऑफ सालिट्यूड लिखने की एक रोचक कहानी मार्केज ने बताई थी. उनके मुताबिक, वह अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि पर किताब लिखना चाहते थे, लेकिन शुरु कैसे करें, इस बात को लेकर उन्हें परेशानी हो रही थी. एक दिन वह अपने पूरे परिवार के साथ कहीं जा रहे थे कि अचानक दिमाग में एक आइडिया आया और उन्होंने कार वापस घर की तरफ मोड़ ली. घर पहुंचते ही उपन्यास लिखने बैठ गए और फिर अट्ठारह महीने में वन हंड्रेड ईयर ऑफ सालिट्यूड को पूरा कर लिया. जहां मार्केज के पहले उपन्यास को प्रकाशक मिलने में सात साल लगे थे, वहीं इस उपन्यास के प्रकाशक ने तो मार्केज को भी चौंका दिया था. उस दौर में मार्केज की कोई भी किताब सात प्रतियों से ज़्यादा नहीं बिकी थी. मार्केज ने जब प्रकाशक को अपना उपन्यास वन हंड्रेड ईयर ऑफ सालिट्यूड छपने के लिए दिया, तो प्रकाशक ने उन्हें यह कहकर चौंका दिया कि वह इस उपन्यास की सात हज़ार प्रतियां छाप रहा है. उस वक्त के माहौल में यह अप्रत्याशित था, लेकिन प्रकाशक को यकीन था कि वन हंड्रेड ईयर ऑफ सालिट्यूड एक बेहतर कृति है और उसकी इतनी प्रतियां बिक जाएंगी. बिक भी गईं. उसके बाद तो मार्केज ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और फिर एक के बाद एक उपन्यासों और कहानियों ने उन्हें विश्व लेखक के तौर पर स्थापित कर दिया. उनकी रचनाओं का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद होने लगा और 1982 में उन्हें साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला. उनकी रचनाओं पर फिल्में बनीं. उनके उपन्यास-लव इन द टाइम ऑफ कॉलरा पर बनी फिल्म ने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले थे. एक पत्रकार के तौर पर करियर की शुरुआत करने वाले गाब्रियल गार्सिया मार्केज ने पत्रकारीय तकनीक का अपने लेखन में जमकर उपयोग किया. उनका मशहूर उपन्यास है-लव इन द टाइम ऑफ कॉलरा. दो बुजुर्गों की यह एक ऐसी प्रेम कहानी है कि इसे सिर्फ़ एक ही शब्द में व्याख्यायित किया जा सकता है-अद्भुत! बुजुर्गों के प्रेम पर मार्केज ने काफी लिखा है. 1999 में जब उन्हें कैंसर हुआ और उसके बाद उनका सफल इलाज हुआ, तो वहीं से मार्केज ने अपनी आत्मकथा लिखने की शुरुआत की. 2002 में मार्केज की आत्मकथा का पहला खंड-लीविंग टू टेल द टेल (कहानी कहने के लिए जी रहा हूं) प्रकाशित हुआ.

एक लेखक के तौर पर मार्केज की अमेरिका में भी काफी प्रतिष्ठा रही है. मार्केज क्यूबा के करश्माई नेता फिडेल कास्ट्रो से लेकर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के मित्र रहे. हवाना में तो उनका घर भी था. दोनों देशों के बेहतर संबंध बनाने की मार्केज ने कोशिश भी की थी. जादुई यथार्थवाद के सिद्धांत के प्रतिपादन के अलावा उनकी कृतियों के वन लाइनर भी काफी प्रसिद्ध रहे हैं और पूरी दुनिया के लेखक अपने तर्कों के समर्थन में उन्हें उद्धृत करते रहे हैं, जैसे, जीवन का कैनवास मौत से बड़ा है, क्योंकि जीवन अनंत है. आपके आंसुओं का किसी के लिए महत्व नहीं है. जिनके लिए है, वह रोने नहीं देते. इसके अलावा पति-पत्नी संबंधों पर भी मार्केज ने काफी लिखा है. मार्केज के निधन से साहित्य जगत का एक ऐसा सितारा चला गया, जिसकी चमक से साहित्य की दुनिया जगमगाती थी, लेकिन जैसा कि मार्केज की ख्वाहिश थी कि मौत के बाद ज़्यादा प्रसिद्धि मिले, तो वही हो रहा है. साहित्य जगत के अलावा विश्व भर के नेताओं ने उनके निधन पर शोक जताया है. पूरी दुनिया के अख़बारों के पहले पन्ने पर मार्केज के निधन का समाचार छपा. अलविदा गोबो. ■

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)

anant.ibn@gmail.com

कविताएं

इंसान कहां है?

आरती शर्मा

कई निज़ाम हैं यहां,
कई धर्म हैं यहां,
कई जाति हैं यहां,
कई मज़हब हैं यहां,
कई मौलवी हैं यहां,
कई पंडित हैं यहां,
बस इंसान नहीं कहीं,
यही इक गम है यहां. ■

सफर

योगेश समदर्शी

बस इतना है सफर जो सबको चलना है,
मिट्टी को मिट्टी से जाकर मिलना है.
बचपन, यौवन और बुढ़ापा जीवन में,
पहले से ही लिखी हुई कुछ घटना है.
कुछ दिन का यह ठौर बसेरा धरती पर,
आगे-पीछे सबको खाली करना है. ■

feedback@chauthiduniya.com

लोकसभा चुनाव और प्रबुद्ध वर्ग

निशाना बनाने में भेदभाव क्यों?

महेंद्र अवधेश

प्रत्येक लेखक-रचनाकार-कलाकार अपनी कृति-रचना-प्रस्तुति में वही कुछ कहने का प्रयास करता है, जो वह देश में, समाज में, अपने इर्द-गिर्द देखता और महसूस करता है. न केवल अपनी कृति-रचना-प्रस्तुति में, बल्कि उन खास मौक़ों पर भी, जब देश एवं समाज से जुड़े सवाल सामने हों, उसका रुख वही होना चाहिए, जो एक ज़िम्मेदार शख्स का होता है. विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाने वाला हमारा देश इस समय आम चुनाव के रूप में एक अहम मौक़े से दो-चार है. ऐसे में, साहित्यकारों, लेखकों एवं कलाकारों की ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है. हमेशा की तरह इस बार भी चुनाव के दौरान राजनीतिक दल और लेखक-साहित्यकार-कलाकार एक-दूसरे के निशाने पर रहे.

देश के जाने-माने लेखकों, साहित्यकारों एवं कलाकारों ने मतदान शुरू होने से पहले भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के ख़िलाफ़ एक अपील जारी की और कहा कि इस चुनाव में वह ताकत सत्ता पर काबिज होने की कोशिश कर रही है, जो घोषित रूप से भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए वचनबद्ध है और एक कथित सांस्कृतिक संगठन का राजनीतिक मोर्चा है. जनवादी लेखक संघ की ओर से जारी इस अपील पर केदारनाथ सिंह, नामवर सिंह, शेखर जोशी, विश्वनाथ त्रिपाठी, दूधनाथ सिंह, यू आर अनंतमूर्ति, अशोक वाजपेयी, असगर वजाहत, मैत्रेयी पुष्पा, पुरुषोत्तम अग्रवाल, सईदा हमीद एवं राजेश जोशी के हस्ताक्षर हैं. अपील में भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हुए कहा गया कि इस मुहिम का नेतृत्व एक ऐसा व्यक्ति कर रहा है, जिसके शासनकाल में वर्ष 2002 में मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, लेकिन उसे कभी पछतावा नहीं हुआ.

ग़ौरतलब है कि कुछ समय पूर्व ज्ञानपीठ विजेता एवं प्रख्यात कन्नड़ लेखक यू आर अनंतमूर्ति ने कहा था, मैं उस देश में नहीं रहना चाहूंगा, जहां नरेंद्र मोदी जैसा शख्स प्रधानमंत्री हो. दूसरे प्रख्यात कन्नड़ लेखक, अभिनेता एवं ज्ञानपीठ विजेता गिरीश कर्नाड ने भी नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ मोर्चा खोला. उन्होंने भाजपा का एकमात्र चेहरा होने को लेकर मोदी को निशाना बनाया, जबकि अनंतमूर्ति का मानना है कि भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी भारतीय सभ्यता और उसकी बहुलतावादी संस्कृति के लिए ख़तरा हैं. उधर भाजपा इन दोनों लेखकों को कांग्रेस का चापलूस बताती है. कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार ने कहा कि ऐसी बातें सिर्फ़ नक्सलियों एवं अपराधियों के समर्थक, वामपंथी विचारधारा के साहित्यकार कर रहे हैं. लेखक वसुंधरा भूपति, के मरुलासिदप्पा एवं जी के गोविंद राव ने अनंतमूर्ति और कर्नाड के साथ मिलकर समकालीन विचार वेदिके नामक बैनर बनाया है. सिद्धार्थ वरदराजन, अनन्या वाजपेयी एवं मुकुल केसवन ने अपने आलेखों में कहा कि नरेंद्र मोदी की जो छवि निर्मित की जा रही है, वह वास्तविक नहीं है.

बीते 17 अप्रैल को वाराणसी में एक सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लेखकों, संस्कृतिकर्मियों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया. वक्ताओं ने कहा कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह पहला मौक़ा है, जबकि औद्योगिक घराने किसी राजनीतिक दल अथवा व्यक्ति विशेष को इस तरह समर्थन दे रहे हैं. इसके पीछे उनका मकसद नव-उदारवादी आर्थिक नीतियों से उपजे संकट को छिपाना है. प्रो. प्रभात पटनायक ने कहा कि नरेंद्र मोदी के आने से देश में चल रहे सामाजिक आंदोलन को हानि पहुंचेगी और वह विपरीत दिशा में चला जाएगा. जर्मनी में भी हिटलर को सत्ता में लाने के पीछे उद्योगपतियों का बड़ा योगदान था, जिन्हें बाद में बंदी शिविर चलाने की छूट दी गई थी. मोदी के आने के बाद हमारे देश में भी वैसा होगा. पटनायक ने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री ने महबूब नगर में हुए रेल हादसे के बाद त्यागपत्र दे दिया था, पर मोदी ने 2002 में हुए गुजरात दंगों के लिए माफी तक नहीं मांगी. सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ ने कहा कि गुजरात में आर्थिक विकास नहीं, बल्कि सांप्रदायिकता, आतंक, नफरत का विकास हुआ. तीस्ता ने मीडिया पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जब बॉलीवुड के कुछ अभिनेताओं ने धर्मनिरपेक्ष उम्मीदवारों को वोट देने की अपील वाला बयान निकाला, तो कॉरपोरेट मीडिया ने उसे सही कवरेज न देते हुए इस तरह दिखाया, जैसे बॉलीवुड दो दलों में बंट गया हो.

देश के विभिन्न लेखकों, कलाकारों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इन दिनों वाराणसी में डेरा डाल रखा है. वे संदेश देना चाहते हैं कि देश को सांप्रदायिक ताकतों से बचाने की ज़रूरत है. इस सिलसिले में आयोजित एक बैठक में मुहिम की कमान प्रसिद्ध साहित्यकार काशीनाथ सिंह को सौंपी गई. प्रसिद्ध समालोचक वीरेंद्र यादव ने कहा कि वाराणसी और लखनऊ तहजीब, सभ्यता एवं संस्कृति के प्रतीक हैं. इसलिए धर्म की राजनीति करने वालों को प्रश्रय देकर इतिहास कलंकित नहीं करना है. विभूति नारायण राय ने कहा कि सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए यदि ज़रूरी हो, तो सिद्धांतों से समझौता भी किया जा सकता है. काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बलराज पांडेय का मानना था कि यदि बौद्धिक वर्ग तमाशबीन बन गया, तो आने वाला समय कभी माफ़ नहीं करेगा.

अब इस बौद्धिक वर्ग की अपीलें, कोशिशें कितनी कारगर होंगी, यह तो समय बताएगा, लेकिन यहां एक सवाल ज़रूर खड़ा होता है कि चुनाव के वक्त ऐसी लामबंदी, घेरेबंदी सिर्फ़ भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ क्यों की जाती है? अगर भाजपा को सांप्रदायिक मानकर ऐसा किया जाता है, तो भ्रष्टाचार और घोटालों को आधार बनाकर कांग्रेस को भी घेरा जाना चाहिए था. अगर नरेंद्र मोदी गुजरात दंगों के लिए दोषी हैं और इसलिए उन्हें वाराणसी में घेरा जा रहा है, तो कांग्रेस ने अपने दस सालों के शासनकाल में देश को खोखला बना दिया है, इसलिए रायबरेली में सोनिया गांधी को भी घेरा जाना चाहिए था. घेरा तो समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव को भी जाना चाहिए था, जो दंगा प्रभावित परिवारों के आंसुओं को नज़रअंदाज करके सैफई में सलमान खान का डांस देखते रहे. बहुजन समाज पार्टी को क्यों बख़्शा गया, जिसकी मुखिया मायावती ने सरकारी खजाना लुटाकर पत्थर की मूर्तियां लगवाने का एक नया इतिहास रच दिया? ■

mahendra.awdhesh@gmail.com

चौथी दुनिया
CHAUTHI DUNIYA

चौथी दुनिया की हर ख़बर अब आपके Android फ़ोन पर भी उपलब्ध,
Play Store से Download करें | CHAUTHI DUNIYA APP

यह स्पीकर ब्लूटुथ द्वारा किसी भी फोन से कनेक्ट हो सकता है और आप लाउड म्यूजिक प्ले कर सकते हैं. यह स्पीकर 5 घंटे तक का पावर बैकअप देता है. क़रीब 30 फीट की रेंज तक आप इसे वायरलेस तरीके से मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं. इसकी क़ीमत 2,995 रुपये है.

एलजी का 4-जी स्मार्ट फोन

एलजी ने अपना नया फोन ल्यूसिड-3 लॉन्च किया है, जो 4-जी है. अभी यह फोन अमेरिका में लॉन्च हुआ है. वहां इसकी क़ीमत 300 डॉलर (लगभग 18,000 रुपये) है. एलजी ल्यूसिड-3 1.2 जीएचजेड क्वाड कोर प्रोसेसर से चलता है और यह 4-जी को सपोर्ट करता है. यह फोन एंड्रॉयड किटकैट 4.4 ओएस पर आधारित है. इसकी रैम 1 जीबी है और इसकी स्टोरेज क्षमता 8 जीबी. इस फोन की खास बात यह है कि इसमें 64 जीबी माइक्रो एसडी स्लॉट है. इसकी स्क्रीन 4.7 इंच की है और इसमें कॉनिंग गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्शन है. यह 960 गुणा 540 पिक्सल (क्यूएचडी) का है. इसमें 5 एमपी ऑटो फोकस कैमरा है, जिसमें एलईडी फ्लैश पीछे है. इसके फ्रंट में वीजीए कैमरा है, जिससे वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती है. इसमें कई फीचर्स हैं, जैसे 4-जी, 3-जी, ब्लूटुथ, जीपीएस एवं वाई-फाई. यह फोन नॉक टेक्नोलॉजी पर आधारित है और स्क्रीन को दो बार टैप करने से एक्टिव हो जाता है. इसके लिए पॉवर बटन या लॉक बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है. इस फोन की बैटरी 12 घंटे का टॉकटाइम देती है.■

अगर मोबाइल में है ब्लूटुथ...

भारतीय बाज़ार में मोबाइल के साथ मोबाइल एक्सेसरीज की भी अधिक मांग है. यहां मोबाइल कवर से लेकर पोर्टेबल स्पीकर्स की मांग है. अगर आप कम क़ीमत में वायरलेस स्पीकर खरीदना चाहते हैं, तो हाल में लॉजीटेक ने भारतीय बाज़ार में कम क़ीमत वाला वायरलेस स्पीकर लॉजीटेक एक्स-100 के नाम से उतारा है, जो कई अलग-अलग रंगों में मौजूद है. यह स्पीकर ब्लूटुथ द्वारा किसी भी फोन से कनेक्ट हो सकता है और आप लाउड म्यूजिक प्ले कर सकते हैं. यह स्पीकर 5 घंटे तक का पावर बैकअप देता है. क़रीब 30 फीट की रेंज तक आप इसे वायरलेस तरीके से मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं. इसकी क़ीमत 2,995 रुपये है. इसके अलावा, लॉजीटेक एक्स-100 स्पीकर आप हैंड-फ्री कॉलिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं.■

महिंद्रा की 300 सीसी बाइक

300 सीसी सेगमेंट में मोजो का मुकाबला निंजा 300, सीबीआर-250 आर और केटीएम-390 ड्यूक जैसी बाइक्स से होगा. इस बाइक में फोर स्ट्रोक लिक्डि डीओरएचसी एसआई इंजन और 295 सीसी का डिस्प्लेमेंट है.

महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप ने अपनी 300 सीसी की बाइक मोजो लॉन्च की है. टू व्हीलर सेगमेंट में एंट्री के लिए यह महिंद्रा का फ्लैगशिप ब्रांड है. इसकी बिक्री आगामी जून माह से शुरू होगी, लेकिन क़ीमत का खुलासा नहीं किया गया है. 300 सीसी सेगमेंट में मोजो का मुकाबला निंजा 300, सीबीआर-250 आर और केटीएम-390 ड्यूक जैसी बाइक्स से होगा.

इस बाइक में फोर स्ट्रोक लिक्डि डीओरएचसी एसआई इंजन और 295 सीसी का डिस्प्लेमेंट है. इसमें मैक्स पॉवर 27 वीएचपी, मैक्स टार्क 25 एनएम, गियर शिफ्ट पैटर्न, वन डाउन 5 अप का इस्तेमाल किया गया है. इसकी लेंथ 2075 एमएम, विड्थ 805 एमएम, हाइट 1260 एमएम है इसमें 160 एमएम का ग्राउंड क्लीयरेंस, 1450 एमएम का व्हीलबेस है. प्यूल टैक 21 लीटर का है. इसमें फ्रंट ब्रेक- पेटल डिस्क, रियर ब्रेक-डिस्क 240 एमएम है.

पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर

भारत की जानी-मानी टू व्हीलर कंपनी महिंद्रा अपना पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर जेनजे एसटीएस लॉन्च करेगी. इसे कैलिफोर्निया में तैयार किया गया है. महिंद्रा जेनजे एसटीएस इलेक्ट्रिक स्कूटर अन्य ई-स्कूटरों से अलग है. इसमें बूट स्पेस काफी ज़्यादा है, जिसमें रोजमर्रा का सामान आसानी से लेकर चला जा सकता है. इसमें लैपटॉप एवं मोबाइल चार्जिंग की भी सुविधा है. इसमें 1.4 केडब्ल्यू इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल किया गया है, जो 1.8 वीएचपी पावर देने में सक्षम है. हल्के और कॉम्पेक्ट चेसिस की वजह से इसकी टॉप स्पीड 50 किमी प्रति घंटा है.■

टाटा मोटर्स का 3 सीटर मैजिक आइरिस

बाज़ार में मौजूदगी को देखते हुए मैजिक आइरिस नामक नया मॉडल लॉन्च करने का फ़ैसला किया है. मैजिक आइरिस 3 सीटर गाड़ी होगी, जिसे तिपहिया यानी ऑटो रिक्शा के विकल्प के तौर पर पेश किया जाएगा.

टाटा मोटर्स ने 3 सीटर मैजिक आइरिस लॉन्च करने की तैयारी कर ली है. कंपनी ने अन्य कंपनियों की क्वाड्री साइकिलों की बाज़ार में मौजूदगी को देखते हुए मैजिक आइरिस नामक नया मॉडल लॉन्च करने का फ़ैसला किया है. मैजिक आइरिस 3 सीटर गाड़ी होगी, जिसे तिपहिया यानी ऑटो रिक्शा के विकल्प के तौर पर पेश किया जाएगा. हालांकि यह गाड़ी चार पहियों वाली होगी. इसके लिए कंपनी ने सरकारी मंजूरी पाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, ताकि तिपहिया के परमिट पर चार पहिया वाहन चलाया जा सके. असम, बिहार, ओडिशा एवं पंजाब जैसे राज्यों में, जहां तिपहिया के लिए परमिट की ज़रूरत नहीं होती, टाटा मोटर्स पहले से चार पहिया मैजिक चला रही है.■

गूगल का नया कैमरा ऐप

एंड्रॉयड फोन यूजर्स के लिए गूगल ने एक खास कैमरा ऐप लांच किया है. फिलहाल यह कैमरा ऐप अभी एंड्रॉयड 4.4 किटकैट ओएस यूजर्स ही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जल्द ही यह ऐप एंड्रॉयड के अन्य वर्जन में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा. अगर आपका एंड्रॉयड फोन 4.4 किटकैट पर काम करता है, तो आप इस ऐप को गूगल प्ले से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं. इससे आप फोटो और वीडियो बेहतर ढंग से ले सकते हैं. गूगल कैमरा ऐप में एक लेंस ब्लर मोड है. इस मोड के जरिये आप फ्रंट का सब्जेक्ट निखारने केलिए बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हैं. इसमें 100 फ़ीसद व्यू-फाइंडर और बिग कैप्चर बटन है, जिससे आप बेहतर पनोरमा 360 डिग्री और शार्प फोटो भी खींच सकते हैं. ■

अगर आपका एंड्रॉयड फोन 4.4 किटकैट पर काम करता है, तो आप इस ऐप को गूगल प्ले से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं. इससे आप फोटो और वीडियो बेहतर ढंग से ले सकते हैं.

डिजिटल बोलेक्स डी-16

यह टीवी ब्रांड बोलेक्स का 16 एमएम कैमरा है. ओल्ड-स्कूल कंट्रोल्स से कैमरे को विंटेज लुक मिला है. इसके सी-माउंट लेंस से पिक्चर क्लीयरिटी मिलती है. इसकी डिजाइन बेशक रेट्रो है, लेकिन कैमरे के फंक्शन बहुत मॉडर्न हैं. आज का समय टेक्नोलॉजी के मामले में काफी एडवांस है. इस डिजिटल कर्व में एंड्रॉयड, वाई-फाई, 14 एमपी मेन सेंसर और 2 एमपी रीयर स्नैपर हैं. इससे हीट-एक्टिवेटेड जिंक पेपर पर फोटोग्राफी प्रिंट ले सकते हैं. ■

अब डॉक्टर्स बनाएंगे आपको वर्जिन

लडकियां ही नहीं शादी शुदा महिलाएं भी पति के साथ जाकर इस सर्जरी को करा रही हैं. डॉक्टरों का कहना है कि रिश्ते में खूबसूरत पलों को वापस पाने में हायम्नोप्लास्टी काफी कारगर है. डॉक्टरों का कहना है कि महिलाओं के कुंआरेपन यानी वर्जिनिटी को लेकर समाज में काफी संकुचित धारणा है.

एक ही कॉलेज में पढ़ने वाले दिव्या और रोहित एक दूसरे से प्यार करते थे. पढाई खत्म करने के बाद दोनों की प्लेसमेंट भी एक ही कंपनी में हो गई. दोनों ने जिंदगी भर साथ रहने का फैसला किया और लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे. शुरुआत में तो सब ठीक था, लेकिन कुछ समय बाद दोनों के रिश्ते खराब हो गए और दोनों अलग हो गए. इधर दिव्या के घर वाले इसकी शादी के लिए जोर डाल रहे थे. पर दिव्या को डर था कि उसका अतीत भविष्य को बर्बाद कर देगा.

एक दूसरे केस में बचपन में अपने ही रिश्तेदार द्वारा शोषण का शिकार हुई नम्रता की शादी होने वाली थी, लेकिन अब वह इस बात से परेशान थी की उसके पति को उसके पिछली जिंदगी के बारे में पता चल जाएगा. (दोनों केस में नाम बदल दिए गए है).

इन दोनों की समस्याओं का एक ही समाधान है हायम्नोप्लास्टी. वर्जिनिटी को वापस पाने के लिए हायम्नोप्लास्टी का सहारा आजकल लडकियां खूब ले रही हैं. इस तकनीक से उन्हें काफी मदद मिलती है जो नहीं चाहती कि उनके अतीत का प्रभाव आने वाले जीवन पर पड़े.

लडकियां ही नहीं शादी शुदा महिलाएं भी पति के साथ जाकर इस सर्जरी को करा रही हैं. डॉक्टरों का कहना है कि रिश्ते में खूबसूरत पलों को वापस पाने में हायम्नोप्लास्टी काफी कारगर है. डॉक्टरों का कहना है कि महिलाओं के कुंआरेपन यानी वर्जिनिटी को लेकर समाज में काफी संकुचित धारणा है. आज वैवाहिक जीवन के लिए लड़की की वर्जिनिटी काफी मायने रखता है. इस सर्जरी से लड़कियों और शादी शुदा महिलाओं के लिए वर्जिनिटी को वापस पाना आसान हो गया है. विदेशों में ही नहीं भारत में भी महिलाएं यह सर्जरी काफी संख्या में करा रही हैं.

एलएनजेपी अस्पताल, दिल्ली के सर्जन कनसल्टेंट पीएस भंडारी कहते हैं कि यह सर्जरी इतनी नैचुरल होती है कि इसकी पहचान कहीं से नहीं हो सकती. हाइमन एक पतली सी झिल्ली होती है जो वजाइनल एंट्रेंस को ब्लॉक करती है. डॉक्टर यह भी मानते हैं कि हाइमन के फटने की कई और वजहें भी हो सकती हैं. स्पोटर्स और फिजिकल ऐक्टिविटीज के दौरान भी लड़कियों में हाइमन टिशू टूट जाता है. ऐसी स्थिति में भी यह सर्जरी कारगर हो सकती है.

क्या है प्रक्रिया?

डॉक्टर पीएस भंडारी कहते हैं कि इस सर्जरी की खास बात यह है कि पेशेंट सुबह ऐडमिट होता है और शाम तक उसे अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है. सर्जरी में अधिकतम एक घंटे का वक्त लगता है. इसके लिए प्राइवेट पार्ट के टिशू से ही हाइमन का निर्माण किया जाता है. इसमें दिए गए स्टिच दो से तीन हफ्ते में अपने आप खत्म हो जाते हैं.

कहां है उपलब्ध

सरकारी और प्राइवेट दोनों अस्पतालों में यह सुविधा उपलब्ध है. यह सुविधा दिल्ली सरकार के एलएनजेपी अस्पताल में फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जा सकता है, जबकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 50 से 60 हजार रूपये का खर्च आता है. ■

प्रियंका प्रियम तिवारी

feedback@chauthiduniya.com

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

आईपीएल सट्टेबाजी और स्पॉट फिक्सिंग प्रकरण

क्या भारतीय क्रिकेट अपनी साख बचा पाएगा ?

यह वक्त भारतीय क्रिकेट की अग्नि परीक्षा का है. दुनिया के सबसे पैसे वाला क्रिकेट बोर्ड की और सबसे धनी क्रिकेट लीग की साख दांव पर लगी है. सुप्रीम कोर्ट के सामने मुद्गल कमेटी ने जांच के बाद 13 लोगों के नाम दिए थे उन पर गंभीर आरोप लगे थे. एक बार फिर से मुदगल कमेटी उन आरोपों की सघन जांच करेगी. जांच के बाद जो रिपोर्ट आएगी वह देश में खेलों खासकर क्रिकेट की दिशा तय करेगी.

नवीन चौहान

भारतीय क्रिकेट अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है. वह एक ऐसे दोराहे पर खड़ा है जहां एक रास्ता आपार धन और चकाचौंध की ओर ले जाता है, और दूसरा क्रिकेट के वजूद, सम्मान और उसकी जेंटलमेन्स गेम्स वाली छवि की ओर. लेकिन बीसीसीआई के वरिष्ठ अधिकारियों को खेल और खिलाड़ियों की चिंता नहीं है. बीसीसीआई अध्यक्ष एन श्रीनिवासन सहित बीसीसीआई का कोई भी सदस्य यह नहीं चाहता कि क्रिकेट सही रास्ते पर चले और फले फूले. भला हो सुप्रीम कोर्ट का जिसने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव आदित्य वर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मुकुल मुदगल की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय समिति को आईपीएल में सट्टेबाजी और स्पॉट फिंक्सिंग की जांच की जिम्मेदारी सौंपी. जिसने अपनी रिपोर्ट में एन श्रीनिवासन सहित 13 लोगों के ख़िलाफ गंभीर आरोप लगाए, जिसमें राष्ट्रीय टीम के लिए खेल चुके 6 खिलाड़ियों के भी नाम शामिल हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई अध्यक्ष एन श्रीनिवासन को पद छोड़ने को कहा, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार श्रीनिवासन के पद पर रहते हुए आईपीएल में फिक्सिंग की निष्पक्ष जांच कर पाना संभव नहीं है. पिछली बार जब ऐसी स्थिति आई तब उन्होंने जगमोहन डालमिया को अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा दिया था. लेकिन इस बार उन्हें कोर्ट ने समय दिया, इस मामले की सुनवाई के दौरान न्यायधीश ने श्रीनिवासन के वकील को रिपोर्ट दिखाते हुए कहा कि देखिए कितने गंभीर आरोप हैं, रिपोर्ट में तेरहवां नाम श्रीनिवासन का है इसलिए वह स्वयं पद छोड़ दें नहीं तो अदालत को ही कोई फैसला करना पड़ेगा. बावजूद इसके श्रीनिवासन ने पद नहीं छोड़ा और कोर्ट ने आदेश दिया कि फिक्सिंग मामले की जांच होने तक आईपीएल से जुड़े कामों की जिम्मेदारी पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर और बीसीसीआई के वरिष्ठ उपाध्यक्ष शिवलाल यादव संभालेंगे.

इसके बाद कोर्ट ने बीसीसीआई को आगे की जांच के लिए तीन सदस्यीय जांच समिति गठित करने को कहा. बीसीसीआई ने अपनी कमेटी में भारत के पूर्व कप्तान और कमेंटेटर रवि शास्त्री, कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व चीफ़ जस्टिस जे एन पटेल और सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर आर के राघवन को शामिल करने का निर्णय लिया. लेकिन इस समिति में शामिल सदस्यों पर भी सवाल उठे. बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष शशांक मनोहर ने शास्त्री के नाम पर आपत्ति दर्ज की थी. लेकिन बीसीसीआई वर्किंग कमेटी में उन्हे समर्थन नहीं मिला. उनकी आपत्ति थी कि रवि शास्त्री वर्तमान में बीसीसाई के कर्मचारी हैं तो वह अपने ही अधिकारियों की क्या जांच करेंगे? आर के राधवन चेन्नई में एक क्रिकेट क्लब के सेक्रेटरी हैं जो तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़ा हुआ है. इस वजह से उनके नाम पर भी आपत्ति हुई. जे एन पटेल भी बीसीसीआई के कार्यकारी अध्यक्ष शिवलाल यादव से जुड़े रहे हैं. बावजूद इसके बीसीसीआई ने इन तीनों लोगों के नाम सुप्रीम कोर्ट को सौंपे, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और जस्टिस मुद्गल समिति से आगे की जांच करने को कहा.

बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी आदित्य वर्मा ने स्पॉट फिक्सिंग मामले की जांच सीबीआई या एनआईए जैसी एजेंसी को सौंपने की मांग की थी. हालांकि वर्मा ने यह साफ किया कि वह इस मामले की अब तक जांच करने वाली जस्टिस मुद्गल कमेटी के काम से संतुष्ट हैं. उन्होंने किसी केंद्रीय जांच ऐजेंसी से जांच कराने की मांग इसलिए उठाई, क्योंकि जस्टिस मुद्गल ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया था कि चेन्नई पुलिस ने उनका जांच में अपेक्षित सहयोग नहीं किया था. वर्मा ने आरोप लगाया कि पुलिस ने ऐसा बीसीसीआई के रसूखदार लोगों को बचाने के लिए किया. यदि सीबीआई या एनआईए के हाथ में जांच के जाने से जांच के दायरे में आने से बच रहे लोगों को रास्ता नहीं मिलेगा.

आदित्य वर्मा की बात इस बात से भी साबित होती है कि चेन्नई सीबी-सीआईडी की जांच में धोनी और रैना जैसे खिलाड़ियों का नाम आया था, लेकिन सीबी-सीआईडी की रिपोर्ट मुद्गल समिति के सामने पेश नहीं की गई. जांच करने वाले आईपीएस अधिकारी वी संपत कुमार को आगे जांच करने की अनुमति देने के बजाए उनका ट्रांसफर कोच्ची रेल्वे में कर दिया गया. मुदगल कमेटी की जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश होने के बाद एक निजी समाचार चैनल में उन्होंने सार्वजनिक रूप से धोनी का नाम लेने के बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया. यह दर्शाता हैं कि एन श्रीनिवासन अपने दामाद गुरूनाथ मैयप्पन को बचाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं. वह अपने कद और पैसे के बल पर जांच को प्रभावित करना चाहते हैं. चेन्नई सुपर किंग्स टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और मालिक श्रीनिवासन दोनों ने मुद्गल समिति को दिए अपने बयान में मयप्पन को महज एक खेल प्रेमी बताया था जबकि जांच समिति ने जांच में यह पाया कि मयप्पन सीधे तौर पर चेन्नई सुपर किंग्स का मैनेजमेंट संभाल रहे थे. दोनों का झूठ पकड़ा गया. मीडिया में खबर दिखाई गई. लेकिन धोनी ने इस मामले में अपना मुह बंद रखा और कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. उन्होंने अपना नाम उछाले जाने पर जी न्यूज के ख़िलाफ 100 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा ठोक दिया. यह कोशिश मीडिया समूहों को उनके खिलाफ कुछ न दिखाने के लिए दबाव बनाने की थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम जारी रखा और आखिर में मुद्गल समिति को आगे की जांच के लिए अधिकृत कर दिया. ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि बीसीसीआई के अंदर हलचल क्यों मची हुई है? आईपीएल का आयोजन यूएई में क्यों किया गया? खासकर तब जबकि 2001 में भारत सरकार ने शारजाह में हैंसी क्रोन्ये मैच फिक्सिंग प्रकरण के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के खेलने पर तीन साल की रोक लगा दी थी. उसके बाद भारतीय टीम कभी शारजाह में खेलने नहीं गई. आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले के सामने आने के बाद ऐसा क्या हुआ कि बीसीसीआई को यूएई की शरण में जाना पड़ा. शायद यही उनके पास आखिरी रास्ता बचा था. बीसीसीआई ने इस बार यूएई सरकार से लिखित में आश्वासन लिया है कि वह फिक्सिंग पर रोक लगाएगी. यूएई में आईपीएल-7 के आयोजन को लेकर बीसीसीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ईएसपीएन क्रिकइन्फो को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि इस बात की क्या गारंटी है कि दक्षिण अफ्रीका या दुनिया के किसी अन्य स्थान में फिक्सिंग नहीं होगी. आईपीएल फिक्सिंग के जांच के दौरान मुंबई पुलिस ने एस श्रीसंत और अन्य खिलाड़ियों पर मकोका के तहत कार्रवाई करने का फैसला किया, क्योंकि स्पॉट फिक्सिंग के तार अंडरवर्ल्ड से जुड़ रहे थे. ऐसे में आईपीएल-7 का आयोजन यूएई में क्यों किया गया? यह बेहद गंभीर सवाल है. क्या भारतीय क्रिकेट के ऊपर अंडरवर्ल्ड का कब्जा हो गया है? इसलिए हर कोई अंडरवर्ल्ड के इशारे पर काम कर रहा है. फिक्सिंग के जाल में फंसी बड़ी मछलियों को बचाने की हर कोई कोशिश की जा रही है.

चाहे कुछ भी हो लेकिन भारतीय क्रिकेट की साख पर बट्टा लग गया है. बीसीसीआई किसी भी सूरत में सूचना के अधिकार के दायरे में नहीं आना चाहता है. बीसीसीआई के अंदर क्या चल रहा है लोग यह जानना चाहते हैं. लेकिन इस तरह की गई हर कोशिश को सोच-समझ कर नाकाम कर दिया गया. पूर्व केंद्रीय खेल मंत्री अजय माकन ने खेल बिल लाकर सभी खेल महकमों को सूचना के अधिकार के दायरे में लाने की पुरजोर कोशिश की, परिणाम स्वरूप उनसे खेल मंत्रालय वापस ले लिया गया. इस वक्त भारतीय क्रिकेट की इज्जत और साख दोनों ही दांव पर लगी हुई है. श्रीनिवासन को आईसीसी का अध्यक्ष चुना गया है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनील गावस्कर और शिवलाल यादव को क्रमशः आईपीएल और आईपीएल के अलावा अन्य मसलों के संचालन की जिम्मेदारी देने के बाद पूर्व खिलाड़ियों के संगठन अध्यक्ष पॉल मार्श ने श्रीनिवासन को आईसीसी की गतिविधियों से दूर रहने को कहा. उन्होंने यह भी कहा कि फिक्सिंग क्रिकेट का सबसे अहम और बड़ा मुद्दा है. क्रिकेट के वजूद को बचाए रखने के लिए हमें न केवल क्रिकेट को साफ सुथरा रखना होगा बल्कि फिक्सिंग की किसी संभावना को दूर करना अच्छा होगा इसलिए श्रीनिवासन जांच पूरी होने तक आईसीसी के कार्यक्रमों से दूर रहें. फिलहाल देश की सर्वोच्च अदालत सीधे तौर पर क्रिकेट में सट्टेबाजी और फिक्सिंग के मामले की निगरानी कर रही है. हम आशा करते हैं कि बिना किसी अड़चन के दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा. लोगों की भावनाओं से खेलने वालों का असल चेहरा लोगों के सामने आएगा.■

navinchauhan@chauthiduniya.com

क्या धोनी को बचाने की कोशिश हो रही है ?

क्या भारत के सबसे सफलतम कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को बचाने की कोशिश हो रही है? बीसीसीआई के अध्यक्ष एन श्रीनिवासन और धोनी के धनिष्ठ संबंधों की पुष्टि इस बात से ही हो जाती है कि उन्होंने धोनी को इंडिया सीमेंट्स का वाइस प्रेसिड़ेंट बना रखा है. धोनी शुरू से यह जानते हैं कि श्रीनिवासन के दामाद गुरुनाथ मयप्पन टीम का मैनेजमेंट संभाल रहे हैं, बावजूद इसके उन्होंने मुदगल कमेटी को दिए गए अपने बयान में उसे एक खेल प्रेमी बताया. यह सरासर झूठ है. सुप्रीम कोर्ट ने श्रीनिवासन को हटाकर सुनील गावस्कर और शिवलाल यादव को जिस दिन बोर्ड के कार्यों के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी, अगले दिन धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी और इंडिया सीमेंट्स का पद छोड़ने की बात कही थी. ठीक इसके उलट वह सीएसके टीम की कप्तानी संभाल रहे हैं अभी तक उन्होंने इंडिया सीमेंट्स के वाइस प्रेसींडेंट के पद से इस्तीफा भी नहीं दिया है. श्रीनिवासन खुद को पाक साफ साबित करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं.

मलिंगा बने श्रीलंका के नए टी-20 कप्तान

श्रीलंका को 18 साल बाद विश्व खिताब दिलाने वाली टीम की अगुआई करने वाले तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा को खेल के सबसे छोटे प्रारूप का कप्तान बनाया गया है. विश्व कप के लिए पहले दिनेश चांदीमल को टीम का कप्तान बनाया गया था. विश्व कप के दौरान ही खराब फॉर्म से जूझ रहे चांदीमल को टीम से बाहर कर कमान मलिंगा को सौंप दी गई थी, मलिंगा ने कार्यकारी कप्तान के रूप में श्रीलंका को विश्व चैंपियन का खिताब दिला दिया. जब 23 वर्षीय चांदीमल को श्रीलंका का कप्तान बनाया गया था, तब वह क्रिकेट के किसी फॉर्मेट में श्रीलंका की कप्तानी करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने थे. बल्लेबाज़ लाहिरू थिरिमाने को सभी फॉर्मेट के लिए उप-कप्तान बनाया गया है. जबकि टेस्ट और वनडे के कप्तान एंजेलो मैथ्यूज ही होंगे.■

बेंगलुरू एफसी ने जीता आई-लीग ख़िताब

पहली बार आई लीग में खेल रहे बेंगलुरू ने अंतिम मुकाबले में डेम्पो स्पोर्टस क्लब को 4-2 से हराकर खिताब अपने नाम किया. पदार्पण सत्र में ही आइ-लीग का खिताब जीतकर बेंगलूरू एफसी ने भारतीय फुटबॉल में नया इतिहास रचा है. कप्तान सुनील छेत्री ने टीम की तरफ से आखिरी गोल दागा. बेंगलूरु को खिताब हासिल करने के लिए इस मैच में जीत बेहद जरूरी थी. उसने मैच में शुरू से आखिर तक दबदबा बनाए रखा. उसकी तरफ से सीन रू नी ने दूसरे, रोबिन सिंह ने 56वें, जॉन मेयोंगर ने 79वें मिनट में गोल किए. सुनील छेत्री ने दूसरे हाफ के इंजरी टाइम में गोल किए. डेंपो की तरफ से राबर्टो सिल्वा ने 82वें और रोमियो फर्नांडिस ने 89वें मिनट में गोल दागे. बेंगलूरू के कप्तान सुनील छेत्री ने आई लीग फुटबॉल टूर्नामेंट में अपनी टीम की खिताबी जीत को अपने चमकदार करियर का महत्वपूर्ण क्षण करार दिया. ■

कप्तान सुनील छेत्री ने टीम की तरफ से आखिरी गोल दागा. बेंगलूरु को खिताब हासिल करने के लिए इस मैच में जीत बेहद जरूरी थी. उसने मैच में शुरू से आखिर तक दबदबा बनाए रखा.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

मेहनत से मुकाम बनाने की चाहत: अर्जुन

2 स्टेट्स एक पारिवारिक फिल्म है. यह कुछ वैसी है, जैसी 90 के दशक में फिल्में बनती थीं. काफी समय बाद 2 स्टेट्स के रूप में लोगों को एक बेहतरीन फिल्म मिली. लेखक चेतन भगत की शादी पर आधारित है 2 स्टेट्स. इसमें आलिया भट्ट और अर्जुन कपूर मुख्य भूमिका में हैं. फिल्म में दोनों स्टार किड्स के अभिनय की काफी सराहना हो रही है. आलिया और अर्जुन की खास बात यह है कि उन्होंने पिता का हाथ थामकर चलने की बजाय अपने बलबूते अपनी पहचान बनाने की सोची. आइए जानते हैं, क्या है इन स्टार किड्स की प्लानिंग और ये कितने गंभीर हैं अपने करियर को लेकर...

अर्जुन कपूर कहते हैं, दूसरे स्टार किड्स क्या सोचते हैं, यह तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने पापा की स्ट्रेंथ बनना चाहता हूं. फिल्म निर्माण एक बिजनेस है, इसमें पैसे खर्च किए जाते हैं और फिर कमाए जाते हैं. मेरे पिता बेहद भावुक इंसान हैं. वह अपनी फिल्म को बेहतर बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते. मैं तो उनका बेटा ही हूं, तो सोचिए, वह मेरी फिल्म के लिए क्या करते. उन्होंने एक समय में काफी महंगी फिल्म-रूप की रानी, चोरों का राजा बनाई थी और फिल्म पुकार का सिर्फ़ एक गाना शूट करने के लिए अलास्का चले गए थे. वह बिग बजट प्रोड्यूसर हैं. वह मेरे लिए फिल्म शुरू करेंगे, तो सब कुछ लगा देंगे, पर मैं नहीं चाहता था कि वह एक ऐसे इंसान पर दांव लगाएं, जो लागत भी वसूल करने की कूवत न रखता हो. मैं पिता के साथ काम करना चाहता हूं, पर उनकी कमजोरी बनकर नहीं. इतनी फिल्में करने के बाद मुझे लगता है कि अब मैं उनकी फिल्म में भी काम करके प्लस साबित हो सकता हूं. सरनेम की वजह से आपके लिए इंडस्ट्री के दरवाजे खुल सकते हैं, लेकिन कैमरे के सामने जाकर काम तो आपको ही करना है. ऑडियंस के साथ कनेक्ट भी आपको ही होना है. अगर आपका काम सराहा जाएगा, तो आपको ऑटोमैटिकली सक्सेस मिलेगी.

दरअसल, पैसे खर्च करके फिल्म देखने जाने वाले दर्शक हमारा सरनेम नहीं देखते. मेरा सरनेम खन्ना या कुमार होता और मेरा काम लोगों को पसंद नहीं आता, तो मैं यहां नहीं होता. अब वह समय जा चुका है, जब लोग स्टार किड्स को हाथों हाथ लेते थे. ऑडियंस अच्छी पिक्चर्स देखना चाहते हैं. अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो ऑडियंस यह नज़रअंदाज करने को तैयार हैं कि आप कहां से आए हैं. अर्जुन के पास 2 स्टेट्स के अलावा 2-3 और फिल्मों के ऑफर थे. उन्होंने किताब नहीं पढ़ी, सीधे स्क्रीन प्ले पढ़ा. यह दो परिवारों की लव स्टोरी है. नॉर्मली हिंदी फिल्मों में रिलेशनशिप लड़के-लड़की के बीच होता है. यह फिल्म दो परिवारों की रिलेशनशिप के बारे में है और इसी बात ने उन्हें फिल्म करने के लिए प्रेरित किया. अर्जुन कहते हैं कि ज़िंदगी का उतार-चढ़ाव उन्होंने बहुत कम उम्र में देख लिया. पहले मां एवं पिता का अलगाव और फिर मां की मृत्यु. वह अपने परिवार के बड़े बच्चे हैं, इसलिए कमजोर नहीं पड़ना चाहते थे. उनकी एक छोटी बहन हैं अंशुला. वह कुछ समय पहले ही अमेरिका से ग्रेजुएट होकर आई हैं. अर्जुन अंशुला में अपनी मां की छवि देखते हैं और इमोशनली उनके बहुत क़रीब हैं. ■

रानी और आदित्य की शादी

लंबे समय से एक-दूसरे के साथ डेट कर रहे फिल्मकार आदित्य चोपड़ा और बॉलीवुड अभिनेत्री रानी मुखर्जी ने शादी कर ली है. दोनों ने इटली के एक छोटे शहर में सात फेरे लिए. शादी में दोनों परिवारों के क़रीबी लोग और दोस्त ही शामिल हुए. रानी ने इस मौक़े पर कहा, मैं अपने जीवन के सबसे सुखद दिन को अपने फैन्स के साथ शेयर करना चाहती हूं. उन फैन्स के साथ जिन्होंने मेरे इतने लंबे सफर में हमेशा साथ दिया है. मेरे चाहने वाले इस दिन का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे. हालांकि रानी काफी भावुक भी थीं अपने ससुर यश चोपड़ा को मिस करके. उन्होंने कहा, इस मौक़े पर मैंने सबसे ज़्यादा यश अंकल को मिस किया. उनका आशीर्वाद मेरे और आदित्य के साथ हमेशा रहेगा. मैं हमेशा से परियों की कहानी में यकीन करती आई हूं और यह मौक़ा कुछ बिल्कुल वैसा ही था. अब मैं जीवन के सबसे महत्वपूर्ण अध्याय में क़दम रखने जा रही हूं. यशराज फिल्म की फिल्म चिराग से ही आदित्य के साथ रानी का नाम जोड़ा जाता रहा है, लेकिन उन्होंने कभी इस रिश्ते को सबके सामने नहीं स्वीकारा. रानी भी इस रिश्ते से इंकार करती रहीं. आदित्य ने इस मामले में हमेशा मीडिया से दूरी बनाए रखी और रानी के साथ कैमरे में कैद न होने की पूरी कोशिश करते रहे. इससे पहले ख़बर आई थी कि आदित्य और रानी जोधपुर के उम्मेद भवन में 10 फरवरी, 2014 को शादी करेंगे, लेकिन उनके प्रशंसकों के हाथ निराशा ही लगी. अब दोनों ने सभी अफवाहों को विराम देते हुए शादी कर ली है. अभिनेता उदय चोपड़ा रानी और आदित्य की शादी से काफी खुश हैं. उन्होंने भाभी रानी का चोपड़ा परिवार में खुले दिल से स्वागत किया. उदय ने ट्वीट किया कि हम रानी चोपड़ा का परिवार में स्वागत करते हैं. फिल्मकार करण जौहर ने भी नवदंपत्ति को ट्वीटर पर बधाई दी. ■

प्रीव्यू

कोयलांचल

- बैनर: एएमए एंटरटेनमेंट
- प्रोडक्शन: आशु त्रिखा
- स्टार कास्ट: विनोद खन्ना, सुनील शेट्टी, रूपाली, पूर्वा पराग ब्रिज गोपाल, दीपराज राणा, अवि सिंह, विपिन्नो, हिमायत अली, मंजीत सिंह, विश्वनाथ बसु
- लेखक: विशाल विजय कुमार, संजय मासूम
- रिलीज डेट: 9 मई, 2014

फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद धनबाद की पृष्ठभूमि एवं कोयले के अवैध कारोबार पर अब एक और फिल्म बनी है- कोयलांचल. इस फिल्म में विनोद खन्ना, सुनील शेट्टी, पूर्वा पराग, रूपाली एवं विपिन्नो मुख्य भूमिका में हैं. फिल्म का निर्माण एएमए इंटरटेनमेंट कंपनी ने किया है, निर्देशक हैं आशु त्रिखा. लेखक हैं विशाल विजय कुमार और संजय मासूम. कोयलांचल की अधिकांश शूटिंग झारखंड में हुई है. कुछ हिस्सा रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, मुंबई और उत्तर प्रदेश में भी शूट किया गया है. फिल्म की शूटिंग धनबाद में होनी थी, लेकिन बीसीसीएल ने अनुमति नहीं दी. इसमें कोलियरियों, उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों, भूमिगत आग, कोयले का अवैध उत्खनन और ढुलाई के सीन भी हैं.

फिल्म में झारखंड और पश्चिम बंगाल के कई युवा कलाकारों ने भी अभिनय किया है. नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की मदद से उनका चयन किया गया. अभिनेता विपिन्नो ने विलेन का किरदार निभाया है. यह फिल्म धनबाद और उसके आसपास कोयले के अवैध कारोबार में वर्चस्व कायम करने के लिए हो रहे खून-खराबे, माफियाओं, उनकी गुटबाजी पर केंद्रित है. इसमें कोयला उद्योग की आड़ में पनपी तमाम मज़दूर यूनियनों की राजनीति भी बखूबी दिखाई गई है. मज़दूरों के शोषण से उपजे नक्सलवाद और लाल झंडे की मजबूती को भी फिल्म में दिखाया गया है. इस देश में एक ही माफिया है और वह है भारत सरकार. यह कोयलांचल है, यहां आंख खोलकर चलिएगा, तो कोयला अंदर जाता है, बंद कीजिएगा, तो बाहर. यह कोयले की जात है, एक ही क़ानून समझती है, जल जाओ या जला दो...इन डायलॉग्स के साथ कोयलांचल का ट्रेलर यू-ट्यूब पर रिलीज किया गया, जो खूब देखा गया. रिलीज से पहले ही फिल्म हिट बताई जा रही है. फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में भी इस विषय को बखूबी दिखाया गया था. अब देखना है कि यह फिल्म उससे बेहतरीन साबित होगी या नहीं. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

मुझे शुरू से ही अपने दम पर कुछ करना था और मैंने किया. हालांकि, अभी तो मैंने शुरुआत की है और मुझे बहुत आगे जाना है. आलिया 2 स्टेट्स साइन करने की वजह बताती हैं कि उन्होंने किताब पढ़ी थी, बहुत समय पहले. तब पता भी नहीं था कि इस किताब पर फिल्म बनने वाली है और इसे करण जौहर ही बना रहे हैं साजिद नाडियाडवाला के साथ.

अभी तो शुरुआत है...

सोनी राजदान एवं महेश भट्ट की बेटी आलिया भट्ट की पहली फिल्म थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर. वह कम उम्र में ही कई बेहतरीन फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं कर चुकी हैं. आलिया कहती हैं, यह सच है कि मैं आसानी से पापा के बैनर से लॉन्च हो सकती थी. मेरे पापा ने बिपाशा बसु, जॉन अब्राहम, मल्लिका सहरावत और कई नए कलाकारों को लॉन्च किया, जो आज बड़े स्टार्स हैं, तो फिर मैं तो उनकी बेटी हूं.

हालांकि मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि मैं मात्र 17 साल की उम्र में करण जौहर की फिल्म में लांच हो जाऊंगी. दरअसल, उनके यहां से कॉल आई कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर के लिए ऑडिशन दूं. पता नहीं, इतनी अच्छी शुरुआत पापा के साथ भी कर पाती या नहीं. मुझे इसलिए फिल्म नहीं मिली कि मैं महेश भट्ट की बेटी हूं. कई सारे कलाकारों में से मेरा सेलेक्शन हुआ. मुझे शुरू से ही अपने दम पर कुछ करना था और मैंने किया. हालांकि, अभी तो मैंने शुरुआत की है और मुझे बहुत आगे जाना है. आलिया 2 स्टेट्स साइन करने की वजह बताती हैं कि उन्होंने किताब पढ़ी थी, बहुत समय पहले. तब पता भी नहीं था कि इस किताब पर फिल्म बनने वाली है और इसे करण जौहर ही बना रहे हैं साजिद नाडियाडवाला के साथ.

वह कहती हैं, उस समय जब मैंने किताब पढ़ी थी, तभी मुझे लगा था कि इसकी स्टोरी इतनी अच्छी है कि इस पर बॉलिवुड फिल्म बननी चाहिए. इसलिए जब मुझे यह रोल ऑफर हुआ, तो मेरे मन में कोई सवाल ही नहीं था. ■

चौथी दुनिया
CHAUTHI DUNIYA
चौथी दुनिया की हर खबर अब आपके Android फोन पर भी उपलब्ध,
Play Store से Download करें | CHAUTHI DUNIYA APP |

चौथी दुनिया

05 मई–11 मई 2014

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHI/2009/30467

बिहार – झारखंड

नब्ज़ पहचान नहीं पाए नीतीश कुमार

बस एक कदम उठा था गलत राह-ए-शौक में, मंजिलें तमाम उम्र ढूंढती रहीं मुझे.

यह शेर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश पर कुमार बिल्कुल सटीक बैठता है. कई बार ऐसा होता है कि राजनीति के पुराने धुरंधरों से भी ऐसे कदम उठ जाते हैं, जो उनकी मुसीबतों के कारण बन जाते हैं. भाजपा के साथ तोड़कर नीतीश से कुछ ऐसी ही गलती हो गई. उन्होंने सोचा था कि नरेंद्र मोदी का विरोध करने की वजह से उन्हें मुस्लिम मतों का लाभ मिल जाएगा, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट. राज्य के मुसलमानों का ध्रुवीकरण राजद की तरफ हो गया. वहीं भाजपा से अलग होने के कारण उससे अगड़ी जाति का वोटर भी लगभग पूरी तरह कट गया. नीतीश के लिए परेशानी ज्यादा बड़ी इसलिए भी है क्योंकि अगले साल विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं और लोकसभा चुनाव परिणामों का प्रभाव इन चुनावों पर भी पड़ सकता है.

सरोज सिंह

ऐसा कहा जाता है कि राजनीति में सत्यानाश के लिए महज एक गलत चाल काफी है. देश के कई नेता इसके शिकार भी हो चुके हैं. इस कड़ी में ताजा उदाहरण नीतीश कुमार का दिया जा रहा है. बिहार की जनता ने बड़े ही अरमानों से 2010 के विधानसभा चुनाव में भाजपा-जदयू गठबंधन को दो तिहाई बहुमत देकर राज्य के विकास की जिम्मेदारी दी थी. जदयू को जहां 2005 में 88 सीटें मिलीं थी तो 2010 में यह आंकड़ा 115 तक पहुंच गया. यही हाल भाजपा का था. जहां इस पार्टी को 2005 में 55 सीटों पर संतोष करना पड़ा था, वहीं 2010 में जनता ने अपार समर्थन दिखाया और उसकी सीटें 91 तक पहुंचा दी. लेकिन लगता है नीतीश कुमार जनता से मिले इस प्यार को संभाल नहीं पाए और इसके पीछे जो भावना थी, उसकी भी कद्र नहीं कर पाए. छोटी-मोटी नोकझोंक को अगर छोड़ दिया जाए तो बिहार में भाजपा-जदयू गठबंधन की सरकार में कोई दिक्कत नहीं थी. भाजपा तो गठबंधन को लेकर इतनी नरम रही कि लोग बिहार में इस पार्टी को जदयू की बी टीम तक कहने लग गए थे. अब सवाल यह उठ रहा है कि जब गठबंधन में इतना लचीलापन था तो फिर नीतीश कुमार ने गठबंधन तोड़ने जैसा बड़ा फैसला क्यों किया? नीतीश कुमार कहते हैं कि वह सिद्धांत से कोई समझौता नहीं कर सकते थे लेकिन जनता उनसे पूछ रही है कि आपको समर्थन नरेंद्र मोदी के नाम पर नहीं विकास के नाम पर दिया गया था इसलिए कम से कम आपको बिहार की जनता की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए था. लेकिन पूर्व विधान पार्षद पी.के. सिन्हा कहते हैं कि भाजपा से सम्बंध तोड़ने में कहीं कोई सिद्धांत नहीं है इसके पीछे महज अपनी तथाकथित धर्मनिरपेक्ष छवि को चमकाना है.

सिन्हा कहते हैं कि नीतीश कुमार के दिमाग में कुछ चाटुकरों ने यह भ्रम पैदा कर दिया कि वह देश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं. भाजपा के साथ रहते इसकी गुंजाइश कम है क्योंकि यहां बहुत तेजी से नरेंद्र मोदी आगे बढ़ रहे हैं. नीतीश कुमार को उम्मीद थी कि लालकृष्ण आडवाणी उनके लिए कहीं से भी रास्ता निकाल देंगे लेकिन जब लालकृष्ण आडवाणी ही किनारे कर दिए गए तो नीतीश कुमार की उम्मीद भाजपा के साथ खत्म हो गई. इसके बाद ही सिद्धांत को ढाल बनाकर नीतीश कुमार ने भाजपा से नाता तोड़ लिया ताकि अपनी धर्मनिरपेक्ष छवि वह लालू प्रसाद से बेहतर बना सकें. इसका लाभ उन्हें यह बताया गया कि मुसलमानों के सारे वोट जदयू के खाते में चले जाएंगे. अतिपिछड़ा और महादलित तो पहले से हैं ही. इसमें कुछ अन्य जातियों के खुदरा वोट भी जोड़ दिए जाएं तो फिर जीत का स्वाद चखना तय है. सिन्हा कहते हैं कि नीतीश कुमार जब पूरी तरह से आश्वस्त हो गए कि तीसरे मोर्चा का नेता बनकर वह देश की बागडोर संभाल सकते हैं तो उन्होंने भाजपा से नाता तोड़ने जैसा आत्मघाती कदम उठाया और इसका कितना बुरा असर हो रहा है इसे सभी देख रहे हैं.

सिद्धांत को ढाल बनाकर नीतीश कुमार ने भाजपा से नाता तोड़ लिया ताकि अपनी धर्मनिरपेक्ष छवि वह लालू प्रसाद से बेहतर बना सकें. इसका लाभ उन्हें यह बताया गया कि मुसलमानों के सारे वोट जदयू के खाते में चले जाएंगे. अतिपिछड़ा और महादलित तो पहले से हैं ही. इसमें कुछ अन्य जातियों के खुदरा वोट भी जोड़ दिए जाएं तो फिर जीत का स्वाद चखना तय है.

भाजपा से नाता तोड़ने के बाद नीतीश कुमार ने मुस्लिम वोट के लिए अपने प्रयास और तेज कर दिए. इस समाज के लोग शुरू के दिनों में नीतीश की तरफ आए भी इसकी संख्या आज भी है लेकिन जब चुनावी बिसात बिछी तो सारे समीकरण बदल गए. नरेंद्र मोदी के आक्रामक प्रचार अभियान ने मुस्लिम वोटों का ध्रवीकरण तेज कर दिया. धीरे-धीरे यह राय बनी कि जो पार्टी नरेंद्र मोदी के रथ को रोक सकन की स्थिति में होगी, उसी को वोट दिया जाएगा. इसकी पहली झलक 10 अप्रैल के मतदान के ही दिन दिख गई. मुस्लिम वोटरों ने राजद को जमकर वोट दिया क्योंकि उन्हें लगा कि जदयू के प्रत्याशी भाजपा गठबंधन के प्रत्याशी को हराने की स्थिति में नहीं है. इससे साफ हो गया कि नीतीश के करे-कराए पर पानी फिर गया. दरअसल भाजपा को छोड़ने से सबसे बड़ा नुकसान जदयू को यह हुआ कि अगड़ी जाति के वोटर नीतीश कुमार से करीब-करीब अलग हो गए.

दूसरी तरफ रामविलास पासवान व उपेंद्र कुशवाहा के साथ तालमेल हो जाने से पासवान और कुशवाहा जाति के वोटरों का भी झुकाव भाजपा की तरफ हो गया. इसका सीधा नुकसान जदयू को हुआ और लोकसभा की लड़ाई में ज्यादातर सीटों पर इस पार्टी के प्रत्याशी मजबूती से नहीं उभर पाए. इसका असर यह हुआ कि मुसलमानों को लगा कि जदयू की तुलना में राजद के प्रत्याशी ही नरेंद्र मोदी का विजय रथ रोकने की स्थिति में हैं इसलिए राजद को उन्होंने थोक के भाव में वोट दे दिया. चुनाव के दूसरे और तीसरे चरण में तो मामला और भी साफ हो गया. इस बीच किशनगंज के जदयू प्रत्याशी अख्तारुल ईमान के बीच में ही मैदान छोड़ देने से नीतीश कुमार की स्थिति और भी हस्यास्पद हो गई. ईमान ने कहा कि वह नहीं चाहते हैं कि साम्प्रदायिक ताकतें मजबूत हों. ईमान के इस बयान का असर सीमांचल की चार सीटों के अलावा भागलपुर और बांका पर भी पड़ा. मुस्लिम वोट तो नीतीश कुमार के हाथ से गए ही जहां तक अतिपिछड़ा वोटों का दावा था वह भी कमजोर पड़ गया. मुसलमानों ने जब एकतरफा वोट गिराना शुरू किया तो प्रतिक्रिया में कई बूथों पर इसी तरह की गोलबंदी हिंदू वोटरों में देखने को मिली. वे जात पात से ऊपर उठ गए और लगा कि दो धाराओं में वोट गिराए जा रहे हैं. खासकर पूर्णिया, कटिहार और अररिया में यह तेवर ज्यादा देखा गया. कहने का अर्थ यह है कि नीतीश कुमार ने एक गलती कर अपना दोहरा नुकसान कर लिया. मुस्लिम वोट तो नहीं ही मिले अतिपिछड़ा वोट बैंक में भी सेंधमारी हो गई. नीतीश कुमार को एक और झटका महिलाओं के मुद्दे पर लग रहा है. नीतीश कुमार बार-बार महिला सशक्तिकरण का मुद्दा उठाते रहे हैं. बिहार सरकार इसे लेकर बड़े-बड़े दावे भी करती रही है. पिछले चुनाव में इसका लाभ भी जदयू भाजपा गठबंधन को मिला लेकिन नीतीश कुमार के विरोधी अब उनसे पूछ रहे हैं कि अगर आप महिलाओं की भलाई के प्रति इतने ही संजीदा रहे हैं तो एक-एक कर आपकी पार्टी की महिला प्रतिनिधि आपका साथ क्यों छोड़ रही हैं? परवीन अमानुल्लाह, अन्नू शुक्ला, सुजाता कुमारी और रेणु कुशवाहा जैसी महिला नेताओं ने जदयू का साथ क्यों छोड़ दिया? अगर यह सरकार महिलाओं के लिए इतना ही काम कर रही है तो फिर इन नेताओं ने साथ क्यों छोड़ दिया? इनमें दो महिलाएं तो मंत्री पद पर थीं. दरअसल स्कूली बच्चों को पोशाक और लड़कियों को साइकिल देकर नीतीश सरकार ने जो इमेज बनाई थी, उसे सिस्टम की खामियों ने धूमिल कर दिया. इसलिए इस बार के चुनावों में महिला वोटरों का ज्यादा झुकाव जदयू के प्रति दिखाई नहीं पड़ रहा है और इसका सीधा नुकसान पार्टी के प्रत्याशियों को हो रहा है. देखा जा रहा है कि ज्यादातर सीटों पर जदयू के उम्मीदवार दूसरे स्थान पर आने के लिए ही मारा-मारी कर रहे हैं. नाम न छापने की शर्त पर जदयू के कुछ नेता कहते हैं कि भाजपा से तालमेल तोड़कर नीतीश कुमार ने बड़ी गलती कर दी. मुसलमान वोट तो नहीं ही मिला दूसरे वोटों से भी हाथ धोना पड़ा. वे कहते हैं कि आज अगर हमलोग भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ते तो चालीस में चालीस सीट जीतने की स्थिति में रहते. लेकिन अब तो दहाई अंक में ही आ जाएं तो बड़ी बात होगी. असल में जदयू के नेताओं का यह दर्द इसलिए भी है कि एक गलती ने जदयू को पीछे धकेल दिया और राजद को आगे कर दिया. अभी तक जो संकेत मिले हैं उनमें ज्यादातर सीटों पर भाजपा गठबंधन का सीधा मुकाबला राजद गठबंधन से हो रहा है. ऐसे में जदयू के नेताओं का दर्द स्वाभाविक है. कोई सत्ताधारी पार्टी अगर अपने राज्य में ही मुख्य मुकाबले में न हो तो उसकी पीड़ा आसानी से समझी जा सकती है. अगले साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं ऐसे में अगर हालात न बदले तो जदयू की चुनावी संभावनाओं पर ग्रहण लगना तय है. ■

feedback@chauthiduniya.com

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

शिवहर में ज़ोरदार होगी टक्कर

गोली की तड़तड़ाहट और बम के धमाकों से चुनाव का एहसास कराने वाले शिवहर जिले में 16 वें लोकसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर है. बदले हालात में न गोली की गुंजाइश है और न ही बम विस्फोट का भय. मतदाताओं में जागरूकता एवं प्रशासनिक सक्रियता का आलम है कि सभी प्रमुख दल के प्रत्याशियों को एड़ी-चोटी एक कर वोट बटोरना पड़ रहा है. इनमें वर्तमान से लेकर पूर्व जनप्रतिनिधि तक शामिल हैं. इस चुनाव में खास तौर पर भाजपा सांसद रमा देवी, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री शाहिद अली खान, पूर्व सांसद मो अनवारुल हक और लवली आनंद की प्रतिष्ठा दांव पर है...

वाल्मीकि/विनोद feedback@chauthiduniya.com

नक्सली व आपराधिक घटनाओं के लिए बिहार में चर्चित शिवहर जिले में कभी मतदान कर्मी जाने से पहले अपने कुल देवता की पूजा करना नहीं भूलते थे. कारण कि चुनाव का समय करीब आने के साथ ही कहीं गोली की तड़तड़ाहट तो कहीं बम धमाके होना आम बात थी. अब हालात बदले हैं, माहौल में बदलाव आया है. चुनाव में बैलेट बॉक्स की जगह ईवीएम ने ली है. मतदाताओं में मतदान के प्रति जागरूकता भी आई है. चुनाव आयोग ने सख्ती के साथ मतदान कराना शुरू कर दिया है. नतीजा है कि अब बंदूक की बदौलत सत्ता पर काबिज होने वाले सूरमाओं को भी मतदाताओं के सामने हाथ जोड़ कर एक अदद वोट की गुहार लगानी पड़ रही है. बाढ़ की वजह से बदहाली झेलने वाले शिवहर लोकसभा क्षेत्र में कुल 6 विधान सभा क्षेत्र आते हैं. इसमें एक शिवहर के अलावा सीतामढ़ी के बेलसंड व रीगा के साथ पूर्वी चम्पारण के तीन (मधुबन, ढाका व चिरैया) विधान सभाओं को शामिल किया गया है. 16 वें लोकसभा चुनाव में इस क्षेत्र के तकरीबन पौने 13 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग 7 मई को करने वाले हैं. इनमें 6 लाख 77 हजार 666 पुरुष एवं 5 लाख 91 हजार 390 महिला मतदाता शामिल है.

लोकसभा के इस चुनावी समर में भाजपा की स्थानीय सांसद रमा देवी को पार्टी ने पुन: चुनाव मैदान में उतारा है. राजद गठबंधन से पूर्व सांसद मो. अनवारुल हक को तो जदयू से राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री शाहिद अली खान बतौर प्रत्याशी चुनावी अखाड़े में जमे हुए हैं. इनके अलावा सपा के टिकट पर पूर्व सांसद लवली आनंद तो बसपा से अंगेश कुमार सिंह हैं. आम आदमी पार्टी की टिकट पर मुकुन्द साहु चुनावी समर में हाथ आजमा रहे हैं. निर्दलीय के रूप में संजय सहनी, हरि शंकर सहनी, रामशरीफ महतो, सुधीर कुमार सिंह, लक्ष्मण पासवान, जटा शंकर आत्रेय, अमजद हुसैन अनवर, जानम्मा खातुन, नसरुद्दीन अंसारी, शिवनंदन प्रसाद, राम लोचित पासवान व राम शोभित सिंह समेत 16 ने नामांकन दाखिल किया है.

चुनावी समीकरणों पर गौर करने वालों की मानें तो इस चुनाव में सभी अपनी-अपनी जीत सुनिश्चित करने को लेकर अथक परिश्रम कर रहे हैं. वर्तमान सांसद और भाजपा प्रत्याशी रमा देवी इस बार नमो मिशन 2014 के सहारे चुनाव जीतने को प्रयासरत है. उन्हें वैश्य, पिछड़ा व दलित के अलावा सवर्ण मत मिलने की उम्मीद है. वहीं जदयू से भगोड़े साबित हुए साबिर अली की जगह चुनावी समर में उतरे मंत्री शाहिद अली खान विकास की दुहाई देकर दिल्ली तक का सफर करने का मन बना चुके हैं. स्वजातीय मुस्लिम मत के अलावा महादलित, यादव, अति पिछड़ा व सवर्ण मत पर उनकी भी नजर टिकी है. पूर्व सांसद मो. अनवारुल हक यादव व मुसलमान के अलावा समाज के सभी तबके के लोगों में अपनी मजबूत पकड़ होने का दावा करते हुए चुनावी अखाड़े में डटे हैं. माय(मुसलमान-यादव) समीकरण के साथ सवर्ण व अन्य मत मिलने की उम्मीद उन्हें भी है. सपा प्रत्याशी व पूर्व सांसद लवली आनंद अपने पति पूर्व सांसद आनंद मोहन के कार्यकाल का याद दिला कर वोट बटोरने में लगी हैं, लेकिन बसपा के टिकट पर चुनावी समर में उतरे उनके स्वजातीय स्थानीय प्रत्याशी अंगेश कुमार सिंह राह का रोड़ा बन कर डटे हैं. वैसे तो सभी प्रत्याशी अपनी जीत का दावा करने में लगे हैं. परंतु चुनावी समीकरणों में चल रही अदला-बदली के कारण फिलहाल कुछ भी कहना मुश्किल हैं. जाति व पार्टी के बीच भंवर से कौन अपनी चुनावी नौका पार लगाएगा, यह तो आने वाला वक्त ही बतायेगा. फिलहाल शिवहर के चुनावी चक्रव्यूह में दिग्गजो की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है. ■

> चुनावी समीकरणों पर गौर करने वालों की मानें तो इस चुनाव में सभी अपनी-अपनी जीत सुनिश्चित करने को लेकर अथक परिश्रम कर रहे हैं. वर्तमान सांसद और भाजपा प्रत्याशी रमा देवी इस बार नमो मिशन 2014 के सहारे चुनाव जीतने को प्रयासरत है. उन्हें वैश्य, पिछड़ा व दलित के अलावा सवर्ण मत मिलने की उम्मीद है.

feedback@chauthiduniya.com

फाइनल में पहुंचा मिशन 2014 का मुकाबला

लोकतांत्रिक व्यवस्था के 16 वें महापर्व के अवसर पर 7 मई को आम-अवाम महत्वपूर्ण योगदान देने वाली है. सीतामढ़ी में चुनावी मैच की पिच बन कर तैयार है. त्रिकोणीय मुकाबले को लेकर विकेट पर मचलने वाले प्रत्याशियों की कसरत अंतिम चरण में है. मैच का कप पाने को चुनावी फिक्सिंग से लेकर मेल-जोल व आपसी सहमति का दौर भी लगभग मुकाम पर पहुंचने लगा है. जाति-पार्टी एवं खरीद-फरोख्त के दौर में चुनावी रेफरियों की रणनीति भी रंग दिखाने लगी है...

वाल्मीकि कुमार feedback@chauthiduniya.com

सीतामढी लोकसभा सीट के चुनावी स्टेडियम में राजनीतिक दल के खिलाड़ियों का अभ्यास सत्र अब समापन के करीब पहुंच गया है. दल से निर्दलीय तक के करीब डेढ़ दर्जन से अधिक प्रत्याशी सफल कप्तानी पारी खेलने को लेकर जी तोड़ मेहनत कर रहे है. विकेट कीपिंग से लेकर फिल्डींग तक में कोई कसर न रह जाए, इसका विशेष ख्याल रखा जा रहा है. खास तौर से मजबूत होने का दावा करने वाली जदयू, राजद, रालोसपा, बसपा, सपा, आप एवं टीएमसी अपनी ओर से कोई कसर छोड़ने को तैयार नहीं हैं. वहीं मतदाताओं को अपने-अपने पक्ष में करने को लेकर कोई बैलगाड़ी की सवारी कर रहा है तो कोई पार्टी की पहचान वाले टोपी धारी कार्यकर्ताओं की पलटन सड़क पर निकाल रहा है. निर्दलीय खेमा भी कम हाथ-पैर नहीं मार रहा है. इतने के बाद चुनावी बाउंड्री लाइन के ऊपर से बॉल निकालने में कौन सफल होगा कहना मुश्किल है. अब राजनीतिक दल के प्रत्याशियों के हालात पर चर्चा भी आवश्यक है. सत्ताधारी जदयू के प्रत्याशी व सांसद डॉ. अर्जुन राय अपने ही दल के कार्यकर्ताओं की नाराजगी से नहीं उबर पा रहे हैं. जदयू की ओर से उन्हें चुनाव मैदान में उतारा गया है. टिकट पर नजरें जमाए पार्टी के ही अन्य सूरमाओं को यह रास नहीं आया और उसी वक्त लगभग यह साफ हो गया था कि सांसद की चुनावी राह किसी चुनौती से कम नहीं है. सांसद के विरोध में मोर्चा संभालने वाले दर्जन भर से अधिक सक्रिय कार्यकर्ता अब भी खुद को चुनावी अभियान से अलग रख रहे हैं. चर्चा है कि कार्यकर्ताओं की इस टोली के रेफरी की भूमिका एक कद्दावर पूर्व पार्टी नेता निभा रहे हैं. जिनकी मंशा चुनाव में सांसद को सबक सिखाने एवं खुद को मजबूत स्तम्भ साबित करने की है. हालांकि बदलते चुनावी समीकरण का मिजाज बीते दिनों की तुलना में अब अलग नजर आने लगा है. टिकट के दावेदार रहे एक पूर्व सांसद का भी स्वर अब बदल चुका है. प्रत्याशी डॉ. अर्जुन राय का दावा है कि चुनावी मैदान में सब कुछ ठीक-ठाक है.

राजद-कांग्रेस व राकांपा गठबंधन से चुनावी समर में ताल ठोंक रहे पूर्व सांसद सीताराम यादव को जातीय वोट के अलावा पिछड़ा, सवर्ण, मुसलमान एवं महादलित समेत अन्य वोट पर पूर्ण भरोसा है. वैसे दलगत विरोध से सीताराम भी अछूते नहीं हैं. टिकट मिलने के साथ ही उनको भी टिकट दावेदारों के विरोध का सामना करना पड़ा है. पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद की पहल पर मामला शांत नजर तो आ रहा है, लेकिन अब भी चुनावी समर की राह आसान नजर नहीं आ रही है. लालू प्रसाद के अस्तित्व के सवाल पर उन्हें यादव मिलने की उम्मीद है तो वहीं उन्हें यह भरोसा भी है कि नमो विरोधी मुसलमान वोट भी मिलेगा. इसके अलावा कांग्रेस के आधार मतों की संभावना भी उनके लिए संजीवनी साबित हो सकती है. गठबंधन दल की ओर से राकांपा भी उनके पक्ष में जोरदार अभियान चला रही है. दूसरी ओर पार्टी के ही पूर्व विधायक जयनंदन प्रसाद यादव की सीताराम के नामांकन में उपस्थिति भी मजबूती के संकेत दे रही है. इसका कारण यह है कि पूर्व विधायक की क्षेत्र में अति पिछड़ा, मुसलमान व महादलित वर्ग समेत अन्य में मजबूत पकड़ बताई जाती है. सीताराम यादव का दावा है कि चुनावी मैदान में जनता राजद गठबंधन के साथ है.

भाजपा-रालोसपा-लोजपा गठबंधन प्रत्याशी राम कुमार शर्मा चुनावी मैदान में भाजपा के नमो मंत्र के सहारे अपना विकेट बचाने की पुरजोर कोशिश में लगे हैं. गठबंधन दल भाजपा एवं लोजपा की फील्डिंग पर यकीन करते हुए उनका दावा है कि बेहतर स्कोर उनके नाम दर्ज होगा. जबकि भाजपा संगठन की सक्रियता कुछ ओहदेदार पार्टी नेताओं की उदासीनता के कारण अब भी आम लोगों में संदिग्ध बनी है. कारण कि भाजपा के ही उमा शंकर गुप्त ने बतौर निर्दलीय प्रत्याशी नामांकन दाखिल कर दिया. चर्चा है कि जब गठबंधन के तहत प्रत्याशी रालोसपा ने मैदान में उतारा तो भाजपा के नेता को चुनाव में नामांकन का साहस हुआ कैसे? वैसे चुनावी चौपाल पर चर्चा यह भी जोरों पर है कि जाति व पार्टी के दवाब में गुप्त चुनावी समर में हाथ खड़े भी कर सकते हैं. वहीं प्रत्याशी का दावा है कि सभी वर्गों में भाजपा के प्रधानमंत्री पद के घोषित प्रत्याशी नरेंद्र मोदी के पक्ष में आम-अवाम एकजुट है. उनके अलावा सीतामढ़ी लोकसभा सीट से पिछले चुनाव में बतौर निर्दलीय प्रत्याशी दस्तक देकर 40 हजार 596 मत लाने वाले सैयद अबु दोजाना इस बार सपा के टिकट पर अपना भाग्य आजमा रहे हैं. वे पूरे ताम-झाम के साथ अपना नामांकन दाखिल कर चुनावी अभियान को मुकाम तक पहुंचाने में लगे हैं. वहीं पहली बार टीएमसी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे डॉ. राजीव रंजन नए अंदाज में मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की जुगत कर रहे हैं. बैलगाड़ी पर सवार होकर नामांकन के बाद जुलूस निकालना इसी कड़ी का हिस्सा रहा. बसपा के डॉ. महेश कुमार तो आप से प्रो. किशोरी दास भी चुनावी पिच पर चौका- छक्का मारने को लेकर प्रयासरत हैं. सीतामढ़ी लोकसभा सीट से इस चुनाव को लेकर कुल 22 लोगों ने अलग-अलग दल से नामांकन दाखिल किया था. इनमें तकरीबन डेढ़ दर्जन से अधिक प्रत्याशी निर्दलीय समेत चुनाव मैदान में रहे. जिनमें डॉ. अर्जुन राय, सीत-राम यादव, राम कुमार शर्मा, उमा शंकर गुप्त, महेश कुमार, महेश नंदन सिंह, मो. फैयाज अहमद, नरेंद्र मिश्र, प्रो. किशोरी दास, महेंद्र प्रसाद, विनोद साह, भारत भूषण सहनी, जय कुमार चौधरी, चंद्रिका प्रसाद, सैयद अबु दोजाना, राजीव रंजन, अजय कुमार, सोनेलाल साह, सत्येंद्र भंडारी व सुरेंद्र कुमार शामिल रहे. चुनावी पिच पर कौन अपनी सफल पारी खेल पाता है. यह तो आने वाला कल ही बताएगा. कारण कि हर दिन हर पल चुनावी समीकरण एक नए मोड़ पर नजर आने लगे हैं. फिलहाल चुनावी घोषणाओं के साथ प्रत्याशियों का जमघट शहर से लेकर गांव तक लग रहा है. वोट मांगने के बाद नोट बांटने का दौर शुरू होने का कयास भी लगाया जा रहा है. दिलचस्प यह भी होगा कि इस चुनावी खेल का जाति व पार्टीगत रेफरी कितनी ईमानदारी के साथ अपने खिलाड़ी को पिच तक पहुंचा कर सफलता दिलाता है. मैदान में वोट फिक्सिंग का आलम क्या है, इसका खुलासा भी 7 मई को होने की सम्भावना प्रबल है. वैसे चुनाव आयोग के निर्देश के आलोक में जिला प्रशासन की पैनी नजर सभी प्रत्याशियों पर है. जो नतीजा सामने आ रहा है, उसमें त्रिकोणीय मुकाबले की सम्भावना बनने लगी है. जदयू, राजद व रालोसपा प्रत्याशी के बीच मिशन 2014 का फाइनल चुनावी मुकाबला तय माना जाने लगा है. विजेता कप पर कब्जा करने वाला कौन होगा, इसका फिलहाल सभी को इंतजार है.■

आमिर को ताक रहा माउंटेन मैन का परिवार

सुनील सौरभ

जब गेहलौर की वादियों में 'सत्यमेव जयते' की शूटिंग हो रही थी, तो माउंटेन मैन दशरथ मांझी के परिजन को यह खुशी थी कि उनकी दारुण दशा से देश-दुनिया के लोग वाकिफ होंगे. उन्हें टीवी सीरियल पर देखा जाएगा. लोग माउंटेन मैन के कृतित्व व व्यक्तित्व से रूबरू तो होंगे ही, साथ ही उनके दिन भी बहुरेंगे. सबसे ज्यादा कोई खुश था, तो वो थीं दशरथ मांझी की पुत्रवधु बसंती देवी. बसंती ने तो उस समय गेहलौर पहुंचे आमिर खान के लिए मडुए की रोटी, कुलथी का दाल, फूलगोभी की सब्जी, अरवा चावल का भात बना कर रखा था. आमिर खान माउंटेन मैन के घर नहीं पहुंच पाए थे. नतीजा यह हुआ कि अरमान धरा का धरा रह गया था. खैर, बसंती इस आश्वासन पर ही खुश हो गई थीं कि आमिर खान ने उन्हें अगली बार गांव आने व उनकी स्थिति को सुधारने का भरोसा दिया है. अब आमिर खान जब कभी माउंटेन मैन के गांव भी आएंगे, तो बसंती से उनकी मुलाकात नहीं हो पाएगी. बस बसंती की यादें फिजा में रहेंगी. आश्वासन और टीवी सीरियल में 'अपनों' को देखने का अरमान लिए बसंती देवी इस दुनिया को छोड़ गईं. महान लोगों की महानता और उनके महान कार्यों तथा गरीबों की बेबसी-लाचारी पर इन दिनों फिल्म, टीवी कार्यक्रम बनाकर लाखों-करोड़ों कमाने का चलन चल पड़ा है, लेकिन ऐसे लोगों पर फिल्म एवं टीवी सीरियल बनाने वाले इनके परिजन से अपना मतलब तो साध लेते हैं, लेकिन बदले में वैसे लोग इन परिवारों को केवल आश्वासन की घुट्टी पिलाते रहते हैं. कुछ ही ऐसा हुआ है गेहलौर घाटी को तोड़कर रास्ता बनाने वाले दशरथ मांझी के परिवार वालों के साथ. दशरथ मांझी पर अब तक दर्जनों वृत चित्र, लघु चित्र एवं टीवी कार्यक्रम बनाये जा चुके हैं. गत 25 फरवरी को बॉलीवुड के विख्यात अभिनेता आमिर खान गेहलौर घाटी आए थे और अपने चर्चित टीवी कार्यक्रम 'सत्यमेव जयते' के लिए स्व. दशरथ मांझी के कृतित्व की शूटिंग की थी. समयाभाव कहें या फिर कुछ और, आमिर खान दशरथ मांझी के घर नहीं जा पाए थे. आमिर, दशरथ मांझी के परिवार को कुछ गिफ्ट देकर वापस मुंबई लौट गए. उन्होंने कहा था कि जल्द ही इनकी टीम के लोग उनसे आकर पुन: मिलेंगे. इसके बाद गेहलौर घाटी में ग्रामीणों ने प्रयास कर बिजली के तार तथा ट्रांसफार्मर ठीक कराए, टीवी कार्यक्रम सत्यमेव जयते देखने के लिए, लेकिन आज दो माह बीत गए. सहायता की बात तो छोड़िए, माउंटेन मैन की स्टोरी को भी सत्यमेव जयते कार्यक्रम में अब तक नहीं दिखाया जा सका है. सत्यमेव जयते कार्यक्रम में अपने तथा अपने परिवार को देखने की लालसा लिए माइंटेन मैन की पुत्रवधु बसंती देवी दुनिया भी छोड़ चुकी. 19 अप्रैल को बसंती देवी का निधन हो गया. 45 वर्षीय बसंती देवी को फेफड़े में संक्रमण की शिकायत थी. नीमचक बथानी के एसडीओ ने आर्थिक सहायता देकर बसंती देवी का दाह संस्कार कराया. हालांकि अब भी दशरथ मांझी के पुत्र भगीरथ मांझी के साथ ही पोती लक्ष्मी, परपोती निभा व विभा के अलावा माउंटेन मैन की बेटी लौंगी देवी, बड़ा नाती सुबोध मांझी व उसकी पत्नी देवरमिया देवी के साथ परिवार के अन्य सदस्यों को यह उम्मीद है कि उनकी सुनी जाएगी.

एक सप्ताह पूर्व भी एक पत्रकार से बसंती देवी ने कहा था कि आमिर खान मुंबई जाकर हमनीं के भूला गेलथीन. फोनवा से बातो न होवाऽ हो. कहलथिन हल के फिनो हम सब तोर दुआरी पर अइबोऽ टीबी पर कार्यक्रमों न अइलो. सवाल है कि सत्ता की राजनीति करने वाले लोग या फिल्म बनाने वाले लोग आखिर कब तक ऐसे लोगों से अपना मतलब साधते रहेंगे और बदले में कभी न भरने वाला दर्द दे जाएंगे.■

feedback@chauthiduniya.com

मतदाता रहे चुस्त, जनप्रतिनिधि सुस्त

सुनील सौरभ

तीन लोकसभा क्षेत्रों में पड़ने वाले गया जिले के दस विधानसभा क्षेत्रों मे मतदान तो सम्पन्न हो गया. लोगो के मत ईवीएम में बंद हो गए लेकिन गया जिले के लोगों को इसबार के चुनाव प्रचार में विभिन्न दलों के जनप्रतिनिधियों, विधायकों की उदासीनता समझ में नहीं आ रही है. इसबार के चुनाव में मतदाताओं विशेषकर युवा मतदाताओं मे जो उत्साह नजर आया, वह अद्भुत था. वहीं दूसरी ओर अपने-अपने दलों के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करने में विधायक, विधान पार्षद बहुत सक्रिय नजर नहीं आए. कई विधायकों के प्रति तो दल के कार्यकर्ता खुलेआम यह कहते नजर आए कि चुनाव प्रचार में सक्रिय नहीं होकर विधायकों ने एक तरह से अपने दल के प्रत्याशी का विरोध किया है. गया जिले में कुल दस विधानसभा क्षेत्र हैं. इसमें इमामगंज, शेरघाटी, बाराचट्टी, टिकारी और अतरी पर जदयू, गया शहर, गुरुआ, बोधगया और वजीरगंज पर भाजपा तथा बेलागंज विधान सभा क्षेत्र पर राजद का कब्जा है. इनमें बेलागंज के राजद विधायक डॉ. सुरेन्द्र प्रसाद यादव जहानाबाद से लोकसभा के राजद प्रत्याशी हैं तो इमामगंज के जदयू विधायक और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जमुई सुरक्षित लोकसभा क्षेत्र से जदयू प्रत्याशी हैं. ये दोनों तो अपने-अपने चुनाव में व्यस्त थे लेकिन जदयू के शेष विधायक तथा भाजपा के विधायकों को गया संसदीय क्षेत्र में अपने-अपने दल के प्रत्याशी के लिए लोकसभा चुनाव प्रचार में बहुत सक्रिय नही देखा गया. क्षेत्र में जब दल के बड़े नेताओं की चुनावी सभा हुई तो मंच पर विधायकगण जरूर देखे गए. ऐसे चुनाव प्रचार में विधायकों की सक्रियता नहीं के बराबर रही. इस बात की शिकायत आम मतदाताओं की भी रही. गया शहर में ही अधिकतर बड़े मोहल्ले में जनप्रतिनिधियों, विधायकों को तो छोडिए, दल का कोई जिला स्तरीय पदाधिकारी भी नहीं आया. हां, मुख्य सड़कों पर रोड शो जरूर हुआ. इसके बावजूद मतदाताओं ने अपने-अपने मताधिकार का उपयोग किया. हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में यह बात नहीं थी. सभी विधायक अपने-अपने दल के प्रत्याशी के लिए सक्रिय देखे गए थे. भाजपा के वरिष्ठ नेता अखौरी निरंजन ने तो गया शहर के भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री डॉ. प्रेम कुमार पर खुलेआम भाजपा प्रत्याशी हरि मांझी पर मदद नहीं करने का अरोप लगाया है. भाजपा के जिला स्तरीय अनेक नेताओं ने इसी प्रकार अपने-अपने क्षेत्र के विधायकों पर भी यही आरोप लगाया है. औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में पड़ने वाले गुरुआ विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुरेन्द्र प्रसाद सिन्हा पर भी पार्टी प्रत्याशी सुशील कुमार सिंह की उचित मदद नहीं करने का अरोप है. हालांकि इसके विपरित जदयू विधायकों की स्थिति कुछ ठीक थी. गया संसदीय क्षेत्र से जदयू प्रत्याशी जीतनराम मांझी फिलहाल राज्य सरकार में मंत्री है और जहानाबाद के मखदुमपुर सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं. लेकिन उनका घर गया शहर में ही है. वाराचट्टी में जदयू विधायक ज्योति देवी उनकी रिश्तेदार हैं. इस हिसाब से वे अपने क्षेत्र में सक्रिय थीं. शेरघाटी के जदयू विधायक विनोद यादव भी अपने क्षेत्र में अपने दल के प्रत्याशी जीतन राम मांझी के लिए वोट मांगते देखे गए. औरंगाबाद और जहानाबाद में पड़ने वाले विधान सभा क्षेत्रों में जदयू के प्रतिनिधियों की रुचि अपने लोकसभा क्षेत्रों के प्रत्याशी के बदले गया संसदीय क्षेत्र से खड़े जदयू प्रत्याशी जीतन राम मांझी के प्रति अधिक देखी गई. राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के विधान पार्षद संजीव श्याम सिंह जहानाबाद लोकसभा से अपने दल के प्रत्याशी और प्रदेश अध्यक्ष अरुण कुमार के लिए अतरी विधानसभा क्षेत्र समेत पूरे संसदीय क्षेत्र में काफी सक्रिय थे. कहा जाए तो इस बार के लोकसभा चुनाव में तीन लोकसभा में पड़ने वाला दस विधान सभा क्षेत्र में दलीय कार्यकर्ताओं मे ही एक तरह से पार्टी धर्म का निर्वाह करते हुए चुनाव प्रचार में लगे रहे. इन सबसे बड़ी बात यह रही कि जनप्रतिनिधियों, विधायक या किसी भी दल के कार्यकर्ता सक्रिय दिखे या नहीं, लोगों तक वोट मांगने गए या नहीं, इसका कोई मायने नही था. मतदाताओं के उत्साह के सामने चुनाव प्रचार में विधायकों की उदासिनता पूरी तरह गौण हो गई थी. हां, गया शहर विधान सभा क्षेत्र में मतदान का प्रतिशत कम होना भाजपा प्रत्याशी हरि मांझी के लिए सोचनीय है तथा इसके लिए यहां के विधायक डॉ. प्रेम कुमार को सवालों के कटघरे मे जरूर खड़ा करता है.■

feedback@chauthiduniya.com

संक्षिप्त ख़बरें

मेयर चुनाव की तैयारियां कर रहे संभावित प्रत्याशी

राजधानी रांची में लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद मेयर का चुनाव होगा. मेयर चुनाव में क्षेत्रीय दलों के नेताओं के अलावा स्थानीय कई समाजसेवियों के भी चुनाव मैदान में आने की संभावना है. सम्भावित प्रत्याशियों ने तो अभी से ही अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं. इंतजार तो बस चुनाव तिथियों के घोषणा भर का है. रांची नगर निगम प्रशासन भी चुनावी तैयारी में जुट गया है. 899 मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन कर इसकी रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. लोगों में ऐसी चर्चा है कि लोकसभा चुनाव के बाद राजधानी में जून माह में मेयर चुनाव का बिगुल बज जाएगा. भाजपा, कांग्रेस, झामुमो, आजसू, टीएमसी, झाविमो सहित कई दलों द्वारा प्रत्याशी उतारेगी. चुनाव में भ्रष्टाचार व स्थानीय मुद्दे अहम होंगे. विभिन्न दलों व निर्दलीय सहित करीब एक दर्जन मेयर प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने की चर्चा है.

- मंगलानंद

कुप्रथा को रोकने में विफल हो रहा प्रशासन

जनजाति बहुल प्रदेश के गुमला जिले में डायन-बिसाही कुप्रथा जैसे अंधविश्वास के कारण हर साल गुमला जिले में तीन दर्जन से अधिक ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसमें बेबस और लाचार महिलाओं को अंधविश्वास की बलिवेदी पर चढ़ा दिया जा रहा है. डायन और बिसाही होने के आरोप में गांव की महिलाओं का जीना दुश्वार हो गया है. इस दिशा में सरकार और प्रशासन की हर पहल लाचार दीख रही है. डायन बिसाही के खिलाफ विभिन्न स्तरों से ग्रामीणों को जागरूक करने का अभियान महज एक औपचारिकता बन कर रह गया है. आए दिन जिले के किसी न किसी क्षेत्र में डायन बिसाही के आरोप में घटनाएं घटित हो रही हैं. वहीं खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में आज के आधुनिक युग में भी लोग डायन बिसाही के चक्कर में पड़कर हत्या जैसी घटनाओं को अंजाम देने एवं इसके परिणाम की तनिक भी चिंता नहीं करते. पिछले वर्ष डेढ़ दर्जन से ज्यादा घटनाएं डायन बिसाही को लेकर घटित हुई थी. जबकि इस साल में अब तक आधा दर्जन घटनाएं घट चुकी हैं. इस पर रोक लगाने, कानून में इसके खिलाफ बने कड़े कानून एवं लोगों को जागरूक करने के लिए समय-समय पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाता है. बावजूद इसके ग्रामीणों में जागरूकता अभियान अपना कोई खास प्रभाव नहीं दिखा पा रही है. डायन और बिसाही पूरे प्रदेश भर की समस्या बन गई है लेकिन आदिवासी बाहुल गुमला जिले में इसका प्रभाव काफी अधिक है. लोग डायन और बिसाही के चक्कर में आर्थिक और मानसिक दोनों स्तर पर कमजोर हो रहे हैं.

- लक्ष्मीनारायण सिंह

कोडरमा में कब दूर होगा पेयजल संकट

हैदराबाद की निर्माण कंपनी के अधिकारियों की लापरवाही के कारण कोडरमा में पेयजल संकट दूर होने का नाम नहीं ले रहा है. 2011 में हैदराबाद की कंपनी आईबीआरसीएल को पानी टंकी का निर्माण कर पीएचईडी विभाग को सौंपना था लेकिन आज 3 साल अधिक बीत जाने के बाद भी निर्माण कंपनी का काम अधूरा पड़ा हुआ है. पीएचईडी के एई गणपति शर्मा बताते हैं कि सारा काम पूरा करा लिया गया है लेकिन टंकी का काम पूरा नहीं हो सका है. पाइप लाईन, सिविल वर्क, इलेक्ट्रिक सहित अन्य काम को पूरा करा लिया गया है. एक से दो माह के भीतर कोडरमा में पेयजल की आपूर्ति शुरू करा दी जाएगी. वर्तमान में जलमीनार के निकट दो नल लगाए गए है जिससे किसी तरह लोगों को पानी मिल रहा है. चंदवारा में जलमिनार का निर्माण का कार्य जब तक पूरा नहीं होता है लोगों की समस्या बनी रहेगी. इधर, भीषण गर्मी के कारण झारखंड-बिहार की सबसे अधिक चौड़ी नदियों में एक सतगावां की सकरी नदी पूरी तरह सूख चुकी है.

- उमेश बर्णवाल/देवेन्द्र कुमार

एक नज़र

पटना में 'कोणार्क डीएसपी सीमेंट' लॉन्च

कोणार्क सीमेंट ने शनिवार को पाटलिपुत्र एग्जॉटिका में नए उत्पाद 'कोणार्क डीएसपी सीमेंट' को लॉन्च किया. भवन निर्माण में गुणवत्तापूर्ण ढलाई के लिए इस विशेष सीमेंट को बाजार में उतारा गया है. कम्पनी के उपकार्यकारी निदेशक सेल्स एंड मार्केटिंग इंद्रजीत चटर्जी ने इसकी खूबियां बताईं. इस मौके पर मार्केटिंग प्रमुख अनजान भद्र, कम्पनी की तकनीकी सेवा टीम के प्रमुख शकुन वैद्य तथा बिहार में चैनल सेल्स प्रमुख संजय सिंह भी मौजूद थे.अधिकारियों ने बताया कि भवन निर्माण के दौरान तय मानकों का पालन अक्सर नहीं हो पाता है. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए 'कोणार्क डीएसपी' में अत्यधिक मजबूती प्रदान की गई है. हर बोरी पर कम्पनी के एक मोबाइल नम्बर जारी किया है, जिस पर कम्पनी के प्रतिनिधि से सीधा सम्पर्क हो सकेगा. रविवार से यह उत्पाद राजधानी में बिक्री के लिए उपलब्ध होगा.

– अमृता कुमारी

शोक सभा आयोजित

परम्बा शक्तिपीठ के प्रांगण में आज मुंशी सिंह महाविद्यालय के पूर्व हिन्दी विभागाध्यक्ष स्व. प्रो. रामाश्रय प्रसाद सिंह के निधन पर शोक सभा आयोजित की गई और उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई. परम्बा शक्ति पीठाधीश्वर श्री शक्तिशरण जी उर्फ चंचल बाबा ने स्व. रामाश्रय बाबू के चित्र पर अंगवस्त्र पहनाकर दिवगंत विद्वान को सम्मान दिया. इस अवसर पर प्रो. शोभाकान्त चौधरी ने स्व. रामाश्रय बाबू के जीवन पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि स्व. रामाश्रय बाबू एक विद्वान होने के साथ अध्याय पुरुष भी थे. मौके पर प्रो. राम स्वार्थ ठाकुर ने उन्हे उच्च कोटि के मनुष्य के रूप में रेखांकित किया और कहा कि समाज के नवनिर्माण में उनके द्वारा दी गई कुर्बानी को कभी भुला नहीं जा सकता. मौके पर प्रो. भृगेन कुमार, प्रसाद रत्नेश्वर, संजय पाण्डेय, डॉ. अरुण कुमार, डॉ. नन्द कुमार प्रसाद, बलराम द्विवेदी, ब्रजकिशोर सिंह, प्रो. रामनिरंजन पाण्डेय, जयराम सिंह, पंडित दीनदयाल मिश्रा, डॉ. रामप्रवेष मिश्रा, डॉ. अनिल प्रसाद श्रीवास्तव, राय सुन्दरदेव शर्मा, विश्वजीत सिंह आदि इपस्थित थे.

– इन्तेजारुल हक

साहू को हुआ नुकसान

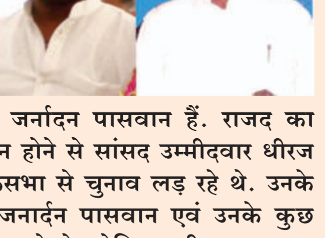

चतरा जिला के अन्तर्गत दो विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं. चतरा विधानसभा एवं सिमरिया विधानसभा. चतरा विधानसभा से राजद के विधायक जर्नादन पासवान हैं. राजद का कांग्रेस के साथ गठबंधन होने से सांसद उम्मीदवार धीरज प्रसाद साहु चतरा लोकसभा से चुनाव लड़ रहे थे. उनके साथ राजद विधायक जनार्दन पासवान एवं उनके कुछ समर्थक चुनाव प्रचार कर रहे थे. लेकिन नतीजा यह हुआ कि जिन मतदाताओं का लगाव राजद से था उन सभी ने विधायक का खुल्मम- खुल्ला विरोध कर दिया और विधायक अलग- थलग दिखाई पड़ने लगे. राजद का 'माय' समीकरण बिल्कुल बिखरता चला गया और इसका भरपूर नुकसान कांग्रेस प्रत्याशी धीरज प्रसाद साहु को उठाना पड़ा. यादव जाति राजद का वोट बैंक माना जाता है. वहीं विधायक से बगावत कर झाविमो की प्रत्याशी नीलम देवी के साथ खड़े हो गए और मुस्लिम जाति का वोट भाजपा एंटी माना जाता है सो कांग्रेस के पाले में लाचारी में जाना पड़ा .

पद का दुरुपयोग

भूमि संरक्षण के सहायक निर्देशक डॉ. दिलीप कुमार गुप्ता द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत अपने पद का खुल्लम खुल्ला दुरुप्रयोग किया है. विरसा पक्का चेक डैम की तकनीकी स्वीकृति एवं अंतिम सत्यापन गलत ढंग से किया गया है. जिसका खुलासा चतरा जिला कृषक महासंगठन के अध्यक्ष गोविन्द सिंह ने बताया कि सहायक निर्देशक को तकनीकी स्वीकृति पांच लाख रुपये तक ही देने का अधिकार है लेकिन गुप्ता द्वारा चेक डेम साढ़े सात लाख एंव इसमें मेक्रोलिफ्ट साढ़े चार लाख एवं लूज बॉल्डर साढ़े तीन लाख यानि कुल मिलाकर साढ़े पन्द्रह लाख रुपये का योजना का तकनीकि स्वीकृति दिया गया जो नियम विरुद्ध माना जा रहा है.■

– अमरेंद्र प्रताप

Enjoy with Nature
MOULDED FURNITURE
NATURE
MOULDED FURNITURE
WINNER OF NATIONAL AWARD
1 YEAR GUARANTY
शर्तें लागू।
Contact : 9386595926, 9334115955

डायबिटिज और ब्लड प्रेशर से पायें निजात
ariskon Pharma Pvt.Ltd.
An ISO 9001 : 2008 Certified Co.
डॉ साबिर अन्सारी
एम.बी.बी.एस. नाथनगर, भागलपुर

आज डायबिटिज रोग वालों की संख्या दिनप्रतिदिन बढ़ती जा रही है इसके प्रतिशत में लगतार इजाफा होता जा रहा है। दैनिक दिनचर्या सही नहीं होने के कारण ब्लड प्रेशर और डायबिटिज जैसे रोगों का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। इसी पर बातचीत की नाथनगर, भागलपुर के विशेषज्ञ डॉ. साबिर अन्सारी ने जिन्होंने दोनों बिमारियों के बारे में जानकारी दी और बताया कि यदि किसी कारण से दोनों रोग लग जाते हैं तो मरीज को हार्ट अटैक आने का खतरा बढ़ जाता है। बल्ड प्रेशर होने की स्थिति में आदमी को चक्कर आना, नींद की कमी, सर में दर्द आदि लक्षण होते हैं। यह दो प्रकार का होता है प्राइमरी और सकेन्डरी हाइपर टेंशन। इस स्थिति में नमक कम खायें फैटी खाना नहीं खायें। आगे डॉ. साबिर ने डायबिटिज पर चर्चा करते हुआ बताया कि चीनीया बीमारी नाम से प्रचलित यह रोग दो प्रकार का होता है इन्सूलिन सेंसेटिव जिसका इलाज इन्जेक्शन द्वारा होता है तथा दूसरा इन्सूलिन रजिस्टेन्स जिसका इलाज दवाई से होता है। डायबिटिज रोग आदमी के 80 प्रतिशत ब्लड में होता है जिसका कारण यह भी है कि यह अनुवांशिकी रोग भी माना जाता है । जिन्हें यह रोग हो जाता है उनका घाव जल्द नहीं ठीक होता है और यदि मां बाप को यह रोग है तो होने वाला बच्चा अंधा भी पैदा हो सकता है साथ ही बच्चों में ग्रोथ की कमी होगी। बार-बार पेशाब होने की बिमारी होगी। इन रोगियों के खान-पान का ध्यान रखें साथ ही मीठा से परहेज करायें। इनके होने पर तुरंत योग्य चिकित्सक से परामर्श लें। ■ प्रस्तुति:अमृता कुमारी

URSLIV Tab. Ursodeoxycholic Acid 300 mg
Rabinok-DSR Entenic Coated Rabeprazole & Domeridone Sustained Release Cap.
AREX Dextromethorphan, Guaiphenesine Ammonium chloride Cough Syp.
DUCORT Deflazacort Tab/Sus.
ARISKONZYME Syrup. For Proper Digestion & Normal gastric functions
NOKSIRA Pharma Pvt.Ltd.
A Division of AriskonPharma

केसरिया प्रखण्ड के बैरिया पंचायत के वार्ड नम्बर 9ए, 10ए, 11 व 12 के ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें अभी तक बिजली मयस्सर नहीं हुई है और बार–बार आवेदन के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नही की गई. स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा केवल घोषणाएं कर उनकी भावना के साथ खिलवाड़ किया गया. बीते दिनों गांव में ग्रामीणों एक बैठक की और इसके बाद यह निर्णय लिया.

कई इलाकों में वोट का होगा बहिष्कार

केसरिया प्रखण्ड के बाराडीह बैरिया, तुरकौलिया प्रखण्ड के उतरी, जयसिंग पुर, चारगाहां, तथा सुगौली प्रखंड क्षेत्र के श्रीपुर के कोरैया यादव बस्ती समेत कई इलाकों के लोग इसबार का चुनाव बहिष्कार करेंगे और नेताओं को सबक सिखाने के मूड में हैं. ये ग्रामीण समय–समय पर बैठकें कर रहे हैं और अपनी मांगें पूरी कराने के लिए जिद पर अड़े हुए हैं. हालांकि उन्हें मनाने के लिए प्राय: सभी दलों के नेता व उम्मीदवार वहां भ्रमण कर चुके हैं किन्तु उन्हें सफलता नहीं मिली है.

इन्तेजारुल हक

निर्वाचन आयोग एक तरफ लोकसभा चुनाव में मतदाताओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित कराने व मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए अनेक कार्यक्रम चला रहा है. वहीं दूसरी तरफ चम्पारण की जर्जर सड़कें, बंद पड़े ट्रांसफारमर, बंद पड़ी चीनी मिलें, किसानों की ज्वलन्त समस्याएं व विद्युत विभाग की लचर व्यवस्था इस इलाके में चुनाव आयोग की मंशा पर पानी फेरते नजर आ रहे हैं. उक्त समस्याओं का निपटारा बार–बार सम्बंधित अधिकारियों को आवेदन देने व स्थानीय सांसदों द्वारा की गई घोषणाओं पर अमल नहीं किए जाने से आक्रोशित यहां की जनता इन मुद्दों को अपना हथियार बनाकर सड़क पर उतर गई है और मतदान का बहिष्कार करने का मन बना चुकी है. केसरिया प्रखण्ड के बाराडीह बैरिया, तुरकौलिया प्रखण्ड के उतरी, जयसिंग पुर, चारगाहां, तथा सुगौली प्रखंड क्षेत्र के श्रीपुर के कोरैया यादव बस्ती समेत कई इलाकों के लोग इसबार का चुनाव बहिष्कार करेंगे और नेताओं को सबक सिखाने के मूड में हैं. ये ग्रामीण समय–समय पर बैठकें कर रहे हैं और अपनी मांगें पूरी कराने के लिए जिद पर अड़े हुए हैं. हालांकि उन्हें मनाने के लिए प्राय: सभी दलों के नेता व उम्मीदवार वहां भ्रमण कर चुके हैं किन्तु उन्हें सफलता नहीं मिली है.

केसरिया प्रखण्ड के बैरिया पंचायत के वार्ड नम्बर 9ए, 10ए, 11 व 12 के ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें अभी तक बिजली मयस्सर नहीं हुई है और बार–बार आवेदन के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नही की गई. स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा केवल घोषणाएं कर उनकी भावना के साथ खिलवाड़ किया गया. बीते दिनों गांव में ग्रामीणों एक बैठक की और इसके बाद यह निर्णय लिया. समाजसेवी मो. नबीजान, मो. नन्हे, शाहिद इकबाल, मुखिया मुन्ना खां, अब्दुल सत्तार, मो. अब्बास, मदन साह, विनोद महतो, डॉ. मकबूल, असल असगरी, अलाउद्दीन शाह, मोसरक खातून, सबीना खातून, इरफाना खातून, नजाम खातून समेत सैकड़ों ने बताया कि इस गांव में लोग बिजली के लिए कई वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं. वे बताते हैं कि यहां के लोगों ने बिजली के लिए बड़ी संख्या में लोगों ने आवदेन दिया था. वर्ष 1979 में स्थानीय लोगों के प्रयास से कुछ बिजली के खम्भे जरूर गाड़ गए लेकिन आज तक इन बिजली के खम्भों पर तार नहीं लगाया जा सका. 1996 में दूसरी बार प्रोजेक्ट तैयार किया गया किन्तु वह प्रोजेक्ट विभाग के संचिकाओं में ही दब कर रह गया. सबसे दिलचस्प बात तो यह है बिजली भले नहीं पहुंची लेकिन कई उपभोक्ताओं के पास बिजली के बिल पहुंच चुके हैं. इन समस्याओं को लेकर स्थानीय विधायक, सांसद व विभाग के पदाधिकारियों के यहां चक्कर लगाते–लगाते ग्रामीण थक चुके हैं और लोकतंत्र के इस महापर्व से अपने को अलग रखते हुए वोट का बहिष्कार कर रहे हैं. अवस्था यह है कि पूरे गांव में यह पोस्टर लगे हुए हैं कि 'बिजली नहीं तो वोट नहीं'.

कुछ इसी तरह के हालात सुगौली प्रखण्ड के श्रीपुर के कोरैया यादव टोला बस्ती, तुरकौलिया प्रखण्ड के चारगाहां पंचायत व घोड़ासहन प्रखण्ड के लौखान पंचायत के लाला टोला का है. विद्युत विभाग की लचर व्यवस्था व खराब ट्रांसफॉरमर के नही बदले जाने से ग्रामीण आक्रोशित हैं और वोट न देने का फैसला कर चुके हैं. यहां के भी ग्रामीण स्थानीय जनप्रतिनिधियों की कार्यशैली से काफी क्षुब्ध हैं. स्थानीय ग्रामीण बताते हैं कि यहां करीब 12 महीने से ट्रांसफॉरमर जला हुआ है और बार–बार आवेदन देने के बावजूद कोई कार्रवाई नही होती. इधर घोड़ासहन प्रखण्ड के लौखान पंचायत स्थित लाला टोला में आजादी के 67 साल बाद बिजली मयस्सार नही हुई. ग्रामीण शम्भू यादव, धर्मदेव यादव, मेघनाथ कुशवाहा, सरपंच फूलकुमारी, सुभाष राम, नवल प्रसाद, सुदन राम, भजू महतो, श्री ठाकुर, दिनेश्वर ठाकुर, राजेन्द्र महतो, उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र यादव आदि बताते हैं कि केवल चुनाव के दौरान ही यहां की जनता की याद नेताओं को होती है और हर चुनाव में बिजली मुहैया कराने के लिए बड़ी–बड़ी घोषणाएं प्रत्याशियों द्वारा की जाती है किन्तु चुनाव समाप्त होते ही सभी वादे भूला दिए जाते हैं.

इधर तुरकौलिया प्रखण्ड के उतरी जयसिंघपुर पंचायत के ग्रामीण सड़क के लिए परेशान हैं और वे अपने को आज भी गुलाम समझते हैं. उनका मानना है कि प्रखण्ड मुख्यालय से महज 10 किलोमिटर की दूरी पर स्थित यह पंचायत सरकार की विकास योजनाओं से काफी दूर है. पंचायत के मुखिया दिलीप यादव बताते हैं कि सड़क नहीं होने से जनता को काफी परेशानी होती है और बारिश के मौसम में अनेक तरह की चुनौतियों से जनता को जूझना पड़ता है.■

feedback@chauthiduniya.com

चम्पारण की तीन सीटों पर होगा रोचक चुनाव

दिग्गजों की होगी अग्निपरीक्षा

राजनीतिक धुरंधरों, फिल्मी जगत की नामचीन हस्तियों के अलावा कई अन्य दिग्गजों की यहां अग्निपरीक्षा होगी और उनके भाग्य का फैसला होगा. भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है, यह तो कोई नहीं जानता किन्तु वर्ष २००९ के चुनाव में जब भाजपा-जदयू साथ थे तब चम्पारण के तीनों संसदीय क्षेत्रों मोतिहारी, बेतिया व वाल्मीकिनगर पर एनडीए का कब्जा हुआ था और राजद-कांग्रेस व लोजपा समेत सभी दलों का पत्ता साफ हो गया था. मोतिहारी से भाजपा प्रत्याशी राधामोहन सिंह, बेतिया से भाजपा प्रत्याशी डॉ. संजय जायसवाल व वाल्मीकिनगर से जदयू प्रत्याशी वैद्यनाथ महतो की जीत हुई थी.

इन्तेजारुल हक

चम्पारण के तीन संसदीय क्षेत्रों में इस बार का चुनाव काफी रोचक होगा और सियासी जंग की पटकथा इसी भूमि में लिखी जाएगी. आखिरी चरण में यहां तीन सीटों पर 12 मई को चुनाव होगा. राजनीतिक धुरंधरों, फिल्मी जगत की नामचीन हस्तियों के अलावा कई अन्य दिग्गजों की यहां अग्निपरीक्षा होगी और उनके भाग्य का फैसला होगा. भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है, यह तो कोई नहीं जानता किन्तु वर्ष 2009 के चुनाव में जब भाजपा–जदयू साथ थे तब चम्पारण के तीनों संसदीय क्षेत्रों मोतिहारी, बेतिया व वाल्मीकिनगर पर एनडीए का कब्जा हुआ था और राजद–कांग्रेस व लोजपा समेत सभी दलों का पत्ता साफ हो गया था. मोतिहारी से भाजपा प्रत्याशी राधामोहन सिंह, बेतिया से भाजपा प्रत्याशी डॉ. संजय जायसवाल व वाल्मीकिनगर से जदयू प्रत्याशी वैद्यनाथ महतो की जीत हुई थी. उक्त चुनाव में बेतिया संसदीय क्षेत्र से प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक प्रकाश झा लोजपा–राजद गठबंधन के प्रत्याशी थे किन्तु जनता ने उनका साथ नहीं दिया और वे चुनाव हार गए. इस बार प्रकाश जदयू के प्रत्याशी हैं. इसी तरह की स्थिति राजद के वरिष्ठ नेता व भारत सरकार के पूर्व मंत्री पं. रघुनाथ झा के साथ थी. बेतिया से वर्ष 2004 के चुनाव में भाजपा को हराकर चुनाव जीतने वाले रघुनाथ को वर्ष 2009 में क्षेत्र बदलकर वाल्मीकिनगर से चुनाव लड़ना काफी महंगा पड़ा था और अपनी जमानत भी बचाने में कामयाब नहीं हो सके थे. राजद ने रघुनाथ को फिर बेतिया से ही प्रत्याशी बनाया है. इसी तरह वर्ष 2004 के चुनाव में भाजपा में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान स्थापित करने वाले राधामोहन सिंह राजद के डॉ. अखिलेश प्रसाद सिंह से चुनाव हार गए थे.

यहां के करीब तीन लाख मुस्लिम व दो लाख यादव वोटरों पर सब की नजर है. जदयू के प्रत्याशी व प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक प्रकाश झा के अलावा राजद के पं. रघुनाथ झा, भाजपा के डॉ. संजय जायसवाल, बसपा के ई. शमीम अख्तर अपनी किस्मत अजमा रहे हैं. यहां अगर राजद का माय समीकरण कायम रहा और पंडित मतों का बंटवारा नहीं हुआ तो लड़ाई काफी रोचक होगी और परिणाम चौंकाने वाला होगा. अगर मुस्लिम वोटरों का बिखराव हो गया तो भाजपा प्रत्याशी डॉ. संजय जायसवाल की राह और आसान हो जाएगी.

किन्तु इस बार के राजनीतिक हालात पूर्व के चुनाव से काफी भिन्न हैं. इस बार भाजपा व जदयू के जहां अलग–अलग उम्मीदवार मैदान में हैं और जोड़–घटाव की राजनीति में लगे हुए हैं तो वहीं दूसरी तरफ यूपीए गठबंधन के राजद प्रत्याशी ही चुनावी दंगल में हैं. जानकार बताते हैं कि भाजपा–जदयू के अलग होने से दोनों को इस चुनाव में काफी नुकसान हो सकता है. ऐसी स्थिति में भाजपा नमो की लहर का सहारा ले अपनी क्षति की भरपाई कर चुनावी वैतरणी पार करने की कोशिश कर रही है तो वहीं जदयू अपनी मजबूत स्थिति दर्ज कराने के लिए संघर्ष कर रही है. पूर्वी चम्पारण संसदीय क्षेत्र से राजद सूप्रीमो लालू यादव ने अपने निजी सचिव विनोद श्रीवास्तव को मैदान में उतारकर कायस्थ समाज को अपनी झोली में डालने की भरपूर कोशिश की है तो दूसरी तरफ जदयू ने भी बिहार विधान सभा में शून्यकाल के सभापति रहे अवनीश सिंह को प्रत्याशी बनाकर भूमिहार मतदताओं को अपनी ओर खींचने का प्रयास किया है. अगर कायस्थ्य वोट राजद की झोली में गए और भूमिहार वोटरों पर जदयू अपना कब्जा जमाने में सफल हो जाती है तो ऐसी स्थिति में भाजपा की राह काफी कठिन हो जाएगी. इसके अलावा राजद का माय समीकरण अगर कायम रहा तो लड़ाई काफी दिलचस्प होगी और कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दाव पर रहेगी. ठीक इसी तरह की हालत बेतिया लोकसभा क्षेत्र की है.

यहां के करीब तीन लाख मुस्लिम व दो लाख यादव वोटरों पर सब की नजर है. जदयू के प्रत्याशी व प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक प्रकाश झा के अलावा राजद के पं. रघुनाथ झा, भाजपा के डॉ. संजय जायसवाल, बसपा के ई. शमीम अख्तर अपनी किस्मत अजमा रहे हैं. यहां अगर राजद का माय समीकरण कायम रहा और पंडित मतों का बंटवारा नहीं हुआ तो लड़ाई काफी रोचक होगी और परिणाम चौंकाने वाला होगा. अगर मुस्लिम वोटरों का बिखराव हो गया तो भाजपा प्रत्याशी डॉ. संजय जायसवाल की राह और आसान हो जाएगी. वहीं वाल्मीकिनगर संसदीय क्षेत्र से भाजपा ने नरकटियागंज के विधायक सतीशचन्द्र दुबे को मैदान में उतारा है, वहीं जदयू ने निवर्तमान सांसद बैद्यनाथ महतो व कांग्रेस ने पूर्णमासी राम को अपना उम्मीदवार बनाया है. इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने पूर्व सांसद धर्मेश प्रसाद वर्मा, बसपा ने एके दिवाकर, सीपीआईएमएल ने विरेन्द्र गुप्ता को इस चुनावी महासंग्राम में उतारा है. ■

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

05 मई-11 मई 2014

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHI/2009/30467

उत्तर प्रदेश – उत्तराखंड

सात मई को डाले जाएंगे मतदान

पूर्वांचल में चढ़ा राजनीतिक पारा

बारह मई को डुमरियागंज बस्ती मण्डल के साथ गोरखपुर एवं आजमगढ़ मंडल के संसदीय क्षेत्रों में मतदान होना है. यहां व्यापक रूप से दलों के भितरघात एवं प्रत्याशियों के चयन में उपेक्षा और जमीनी नेताओं की अपेक्षाओं पर कुठाराघात से नेताओं की छवि पर असर पड़ रहा है, वहीं, पार्टी के नाम पर जोड़ने का प्रयास जारी है. डुमरियागंज में कांग्रेस प्रत्याशी वसुंधरा के पक्ष में प्रचार करने के आरोपों से निष्ठावान भाजपा विधायक जयप्रताप सिंह को निलंबित कर दिया गया है और वे जोर-शोर से कांग्रेस के प्रचार में लग गए हैं, जबकि जिप्पी तिवारी के सपा में आ जाने से तथा राजा साहब शोहरतगढ़ के समर्थन एवं राम नाथ कठवतिया के चौधरी सहित ब्रजभूषण तिवारी के राज्यसभा सदस्य पुत्र तथा सपा नेता लाल जी यादव चन्द्रभूषण मिश्रा के सहयोग से मुस्लिम मतदाताओं को सपा से जोड़ने का काम किया जा रहा है.

दशरथ प्रसाद यादव

पूर्वांचल में चुनाव की सरगर्मियां बढ़ गई हैं. इसे नरेन्द्र मोदी द्वारा काशी में भद्राकाल में नामांकन दाखिल करने के साथ एक बड़ा रण क्षेत्र तैयार हो गया है. अभी समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के साथ भाजपा के योगी आदित्य नाथ, सपा के माता प्रसाद पाण्डेय, भाजपा के जगदम्बिका पाल कांग्रेस के आरपीएन सिंह, भाजपा के कलराज मिश्र, रमाकान्त यादव, सपा के राधेश्याम सिंह, बसपा के राम प्रसाद चौधरी, रविशंकर सिंह उर्फ पप्पू सिंह, सपा के हरिवंश सहाय, भालचन्द्र यादव, कांग्रेस के भोला पाण्डेय, सपा के नीरज शेखर, बसपा के कुशल तिवारी, काग्रेस के हर्शवर्धन सिंह, सपा के अखिलेश सिंह, भाजपा के कमलेश पासवान, पंकज सिंह, भरत सिंह हरीश द्विवेदी, बसपा के मुकीम, केएन मिश्रा सहित पीस पार्टी के डॉ अयूब, कांग्रेस के अम्बिका सिंह जैसे दिग्गज प्रत्याशियों ने नामांकन कर दिया है. आजमगढ़, बलिया, सलेमपुर, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, बांसगांव, महराजगंज, सिद्धार्थनगर संसदीय क्षेत्रों में भी सरगर्मी बढ़ गई हैं, जबकि बस्ती मण्डल के बस्ती एवं सन्तकबीर नगर के संसदीय क्षेत्र के लिए नामांकन का कार्य पूरा हो चुका है. नोटा के साथ एक ही ईवीएम मशीन से फिलहाल यहां मतदान प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी, क्योंकि प्रत्याशियों की संख्या 16 से कम हैं.

बस्ती संसदीय क्षेत्र से कुल 13 उम्मीद्वारों के पर्चे वैध घोशित किए गए. इनमें कांग्रेस प्रत्याशी अम्बिका सिंह का पर्चा भी शामिल है. अम्बिका सिंह को अन्तिम वक्त में कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया, जब उनके पूर्व घोशित प्रत्याशी संजय जायसवाल द्वारा नामांकन पत्र दाखिल कर दिया गया था. लेकिन उसके साथ पार्टी सिंबल नही था. इसी आधार पर इनका पर्चा खारिज किया गया है जबकि उन्होंने पूर्व में घोशणा कर दी थी की वे संसदीय चुनाव नहीं लड़ेंगे. उनके खिलाफ लखनऊ में दाखिल मामले को देखते हुए यह परिवर्तन किया गया है. सपा से बृजकिशोर सिंह डिम्पल ने पहले दिन बारह अप्रैल को ही नामांकन दाखिल किया था. बसपा की ओर से राम प्रसाद चौधरी, भाजपा के हरीश द्विवेदी ने भी पहले ही पर्चा भर दिया था. इनके अलावा पंजीकृत पार्टियों से भी प्रत्याशियों ने नामांकन किया है.

बस्ती मण्डल में बड़े नेताओं की रैलियों की बारी आ गई है. बसपा सुप्रीमो को जैसे 26 तारीख और बस्ती, सन्तकबीर नगर का दौरा मुफिद होने लगा हैं क्योंकि 26 अप्रैल से ही वे बस्ती और संन्तकबीर नगर के साथ पूर्वांचल में अभियान छेड़ रही हैं. सपा भी पीछे नहीं है और 29 अप्रैल को मुलायम सिंह यादव का बस्ती मण्डल में आगमन होने की सम्भावना है, तो सात मई को मुलायम सिंह यादव गोरखपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं. उन्होंने आजमगढ़ से इसकी शुरुआत कर दी है.

भाजपा के नेताओं के बयान के अनुसार नरेन्द्र मोदी का कार्यक्रम अभी पूर्वांचल के लिए नहीं मिला है, जबकि अन्य कई शीर्शस्थ नेताओं के आने की पुष्टि भी की जा रही है. पीस पाटी के डॉ अयूब का कार्यक्रम चल रहा है. आप पार्टी की ओर से अभी केजरीवाल या विश्वास या शाजिया या संजय सिंह के आने की कोई सूचना नही है. कांग्रेस की ओर से पूर्वांचल में राहुल गांधी का कार्यक्रम लेने की सुगबुगाहट है. लब्बोलुआब की अब एक पखवारा पूर्वांचल में राजनीतिक सरगर्मियां शीर्ष पर होंगी. आप पाटी की ओर से गोरखपुर से लेकर बस्ती तक जो तत्परता पहले दिख रही थी वह अब नहीं दिखाई पड़ रही है. बस्ती एवं सन्तकबीर नगर संसदीय क्षेत्रों में सात मई को मतदान होगा और बस्ती में प्रेक्षक विकास गुप्ता के साथ प्रशासनिक अम्ला की बैठक हो चुकी है. क्रमिक प्रबंधन सीडीओ एवं डीडीओ डॉ बब्बन उपाध्याय नोडल अधिकारी द्वारा तथा सामान्य प्रशासन अपर जिलाधिकारी भदौरिया के नेतृत्व में एवं चुनाव खर्च पर नजर रखने की व्यवस्था प्रेक्षक के साथ मुख्य कोशाधिकारी एसपी सिंह के नेतृत्व में जारी है. सर्विलान्स टीमें लगा दी गई है.

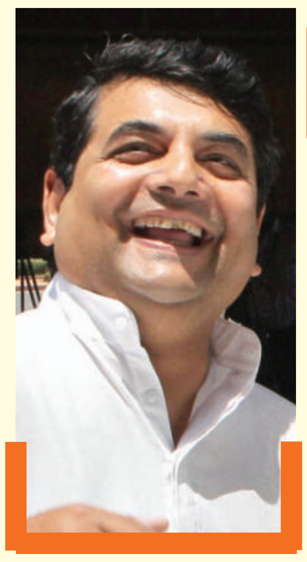

बस्ती मण्डल में बड़े नेताओं की रैलियों की बारी आ गई है. बसपा सुप्रीमो को बस्ती, सन्तकबीर नगर का दौरा मुफिद होने लगा हैं, वे बस्ती और सन्तकबीर नगर के साथ ही पूर्वांचल में अभियान छेड़ रही हैं. उधर, सपा भी पीछे नहीं है और सात मई को मुलायम सिंह यादव गोरखपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं. उन्होंने आजमगढ़ से इसकी शुरुआत कर दी है. भाजपा के नेताओं के बयान के अनुसार नरेन्द्र मोदी का कार्यक्रम अभी पूर्वांचल के लिए नहीं मिला है, जबकि अन्य कई शीर्षस्थ नेताओं के आने की पुष्टि भी की जा रही है.

पुलिस बल सक्रिय है. यह अलग बात है कि सम्भवत प्रशासन को प्रत्याशियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रो में दिए जा रहे लाभ व प्रलोभन को ध्यान में नहीं या कम ही रखा जा रहा हैं. चुस्त व्यवस्था का परिणाम यह है कि अब डंडे, झंडे, को छोड़ हथकंडे पर लोग उतर आ रहे हैं. सन्तकबीर नगर संसदीय क्षेत्र में भी तैयारियां जारी हैं. तीन विधानसभा क्षेत्रों की तैयारी जहां जिला प्रशासन सन्तकबीर नगर द्वारा की जा रही है. वहीं आलापुर विधानसभा क्षेत्र के लिए फैजाबाद मंडल के अंबेडकर नगर जिला प्रशासन द्वारा एवं खजनी क्षेत्र के लिए गोरखपुर मंडल के गोरखपुर जिला प्रशासन द्वारा तैयारियां जारी हैं. प्राप्त खबरों मे भालचन्द्र यादव सपा, कुशल तिवारी बसपा, शरद त्रिपाठी भाजपा एवं आर पाण्डेय कांग्रेस से यहां प्रत्याशी हैं. अन्य प्रत्याशियों में पंजीकृत एंव अन्य दलो के लोग शामिल हैं.

मुख्य लड़ाई में आने के लिए सभी दल प्रयत्नशील हैं, जिसमें भालचन्द्र एवं कुशल तिवारी और शरद त्रिपाठी के बीच टक्कर हो सकती है. मतदाताओं को कोई भी भ्रम नहीं है, जबकि मध्यस्थ भाइयों द्वारा तरह-तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जिस पर जिला एवं पुलिस प्रशासन के साथ गोरखपुर जोन की ओर से नजर रखी जा रही है.

बारह मई को डुमरियागंज बस्ती मण्डल के साथ गोरखपुर एवं आजमगढ़ मंडल के संसदीय क्षेत्रों में मतदान होना हैं. यहां व्यापक रूप से दलों के भितरघात एवं प्रत्याशियों के चयन में उपेक्षा तथा जमीनी नेताओं की अपेक्षाओं पर कुठाराघात से नेताओं की छवि पर असर पड़ रहा है, जबकि पार्टी के नाम पर जोड़ने का प्रयास जारी है. डुमरियागंज में कांग्रेस प्रत्याशी वसुंधरा के पक्ष में प्रचार करने के आरोपों से निष्ठावान भाजपा विधायक जयप्रताप सिंह को निलंबित कर दिया गया है और वे जोर-शोर से कांग्रेस के प्रचार में लग गए हैं, जबकि जिप्पी तिवारी के सपा में आ जाने से तथा राजा साहब सोहरतगढ़ के समर्थन एवं राम नाथ कठवतिया के चौधरी सहित ब्रजभूषण तिवारी के राज्यसभा सदस्य पुत्र तथा सपा नेता लाल जी यादव चन्द्र भूषण मिश्रा के सहयोग से मुस्लिम मतदाताओं को सपा से जोड़ने का काम किया जा रहा है.

भाजपा के जगदम्बिका पाल एवं बसपा के मोहम्मद मुकिम के साथ पीस पार्टी के आयूब खान को यहां व्यापक प्रचार करते देखा जा रहा है. वैसे यहां से कांग्रेस के केशवदेव मालवीय की परम्परा को ये बढ़ा सकते हैं या नहीं भविष्य के गर्त में हैं. हां, डुमरियागंज से सपा या अन्य कांग्रेस अथवा भाजपानीत दलों के प्रत्याशी के रूप में जब देखा जाए, तो सपा या इसके समानान्तर दलों से ब्राह्मण प्रत्याशी ही यहां से जीते हैं. इनमें माधव प्रसाद तिपाठी एवं ब्रजभूषण तिवारी भी शामिल हैं. इस बार यह कारनामा माता प्रसाद पाण्डेय कर सकते हैं या नहीं भविष्य बताएगा.

महराजगंज में सपा प्रत्याशी के समर्थन में उनके भाई कांग्रेस विधायक के आने का लाभ उन्हें मिल रहा है, तो कांग्रेस के सांसद को इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है. अन्य दल अपने परंपरा गत ढंग से प्रचार में हैं. त्रिपाठी परिवार इस बार काफी खामोश बताया जा रहा है, जिसका परिणाम किसी को भी चौंका सकता है. गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ, राजमती देवी, राधेमोहन मिश्र सहित अन्य प्रत्याशियों में चयन यहां की जनता करने में समर्थ है. बांसगांव में सपा से सांसद रहीं सुभावती देवी एवं योगी आदित्य नाथ के समर्थन से सांसद कमलेश पासवान किसी से कमजोर नहीं है.

अन्य प्रत्याशी सामान्य तौर से बेहतर परिणाम की आशा में है. सपा में अवधेश यादव के नेतृत्व का लाभ पूरे क्षेत्र में मिल सकता है. बलिया में भरत सिंह भाजपा तथा नीरज शेखर कुशीनगर, देवरिया, सलेमपुर में अपने पुराने मतों को जो सहेज ले जाएंगे. उन्हें बढ़ोतरी मिल सकती है. आजमगढ़ इस समय राजनीति के शिखर पर हैं. यहां बनारस की तरह हलचल काफी तेज है. इन दोनों स्थानों से कौन जीतेगा मतदान के पहले कहना उचित नहीं होगा.■

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

आवश्यकता है

संवाददाता, विज्ञापन प्रतिनिधि, प्रसार प्रतिनिधि

चौथी दुनिया के लिए उत्तर प्रदेश के सभी मंडल और जिला मुख्यालयों पर अनुभवी संवाददाताओं, विज्ञापन और प्रसार प्रतिनिधियों की. पारिश्रमिक योग्यता अनुसार. शीघ्र आवेदन करें.

E-mail- konica@chauthiduniya.com
ajaiup@chauthiduniya.com
चौथी दुनिया F-2, सेक्टर 11, नोएडा
(गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश-201301,
PH : 120-6450888, 6451999

देवीपाटन मंडल में बाहुबलियों के सामने अस्तित्व का संकट

जानकी शरण द्विवेदी

सोलहवीं लोकसभा के लिए होने जा रहे चुनाव में देवीपाटन मंडल की चार में से तीन लोकसभा सीटों पर प्रदेश के कई बाहुबली अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं. लोकतंत्र के किशोरावस्था में अटल बिहारी वाजपेयी और नाना जी देशमुख सरीखे नेताओं ने इस क्षेत्र को अपनी कर्मभूमि बनाकर समाजसेवा की, तो बाद के दिनों में यहां की उर्वरता देख बाहरी नेताओं का स्वच्छंद विचरण होने लगा. परिणाम यह रहा कि देवीपाटन मण्डल की सीटों गोंडा, बहराइच, कैसरगंज और बलरामपुर (अब श्रावस्ती) से अनेक बार बाहरी नेताओं पर भरोसा जताकर यहां की जनता ने इन्हें लोकसभा पहुंचाया, लेकिन आजादी के 66 वर्षों के बाद भी यह उत्तर प्रदेश के जिले सबसे निचले पायदान पर हैं. राजनेताओं के फलने फूलने की प्रचुर संभावना के कारण ही एक बार इन सीटों पर बाहुबलियों के बीच मुकाबला हो रहा है.

अयोध्या से सटा इलाका होने के कारण देवीपाटन मण्डल आजादी के समय से ही जनसंघ का गढ़ रहा है. इसी कारण गैर प्रांतों से आकर अटल बिहारी बाजपेयी, नाना जी देशमुख, केके नैयर, शकुंतला नैयर सरीखे नेताओं ने इसे अपनी …

सुचेता कृपलानी, बसंत कुमारी, हैदर अली, आरिफ मोहम्मद खान जैसे बाहर से आने वाले नेताओं को भी यहां की जनता ने चुनकर लोकसभा भेजा. इतना ही नहीं, यहां के मतदाताओं ने मुन्नन खान के रूप में निर्दलीय प्रत्याशी को भी चुनकर लोकसभा भेजने में गुरेज नहीं किया. समय बदलने के साथ-साथ परिस्थितियां भी बदलती गईं और नब्बे का दशक आते-आते अपने आकाओं के लिए काम करने वाले बाहुबलियों ने खुद चुनाव लड़ना शुरू किया. परिणाम स्वरूप पंद्रहवीं लोकसभा में चुनकर कई बाहुबली देश की सर्वोच्च पंचायत में पहुंचे.

… सुभद्रा जोशी कांग्रेस के टिकट पर सांसद चुनी गईं. वे भी बाहरी थीं. इनके पिता वीएन दत्ता जयपुर रियासत के पुलिस अधिकारी थे. 67 में पुन: अटल बिहारी बाजपेयी निर्वाचित हुए. 71 में … रुद्रसेन चौधरी तथा 91 में भाजपा के ही लक्ष्मी नरायन मणि त्रिपाठी निर्वाचित हुए. इसके साथ ही 96, 98, 99 और 2004 के चुनाव में सपा के बेनी प्रसाद वर्मा लगातार जीतते रहे. 2009 के … लगातार छठवीं बार लोकसभा पहुंचने को बेताब हैं, तो इन्हें चुनौती देने के लिए भाजपा ने दो बार सांसद रहे व मनकापुर राजघराने के कीर्तिवर्धन सिंह 'राजा भैया' को मैदान में उतारा है. सपा ने …

… चुनाव जीते. बाजपेयी जी भी मूलत: मध्य प्रदेश के विदिशा के मूल निवासी हैं. 62 में यहां से … 77 में जनता पार्टी के रुद्रसेन … में कांग्रेस के रानावीर सिंह …

feedback@chauthiduniya.com

फैजाबाद में खिल सकता है कमल

राकेश कुमार यादव

लोकसभा चुनाव 2014 के लिए फैजाबाद संसदीय क्षेत्र से नामांकन वापसी के बाद चुनावी समर में 11 उम्मीदवार शेष रह गए हैं. प्रमुख दलों के अलावा सभी प्रत्याशियों ने अपने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है. वहीं प्रमुख चार दल भाजपा, कांग्रेस, सपा और बसपा स्टार प्रचारकों के जरिये सेंधमारी की कवायद कर रहे हैं. जो अभी तक बेअसर दिखाई पड़ रहा है. फैजाबाद क्षेत्र से भाजपा के लल्लू सिंह, कांग्रेस के डा. निर्मल खत्री और समाजवादी पार्टी के मित्रसेन यादव में स्पष्ट त्रिकोणीय मुकाबला दिखाई पड़ रहा है. बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जितेन्द्र सिंह बब्लू के हाथ से परंपरागत दलित मत भी खिसकता दिखाई पड़ रहा है. करीब–करीब वह चुनावी समर से बाहर दिखाई पड़ने लगे हैं. भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह के लिए मोदी लहर प्लस साबित हो रही है. जिससे अबतक वह चुनावी दौर में सबसे आगे दिखाई पड़ रहे है. वैसे कांग्रेस और सपा भी दौड़ में पहले नम्बर पर पहुंचने के लिए पूरी ताकत लगा रही हैं. …

बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जितेन्द्र सिंह बब्लू के हाथ से परंपरागत दलित मत भी खिसकता दिखाई पड़ रहा है. करीब-करीब वह चुनावी समर से बाहर दिखाई पड़ने लगे हैं. भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह के लिए मोदी लहर प्लस साबित हो रही है, जिससे अबतक वह चुनावी दौर में सबसे आगे दिखाई पड़ रहे हैं. वैसे कांग्रेस और सपा भी दौड़ में पहले नम्बर पर पहुंचने के लिए पूरी ताकत लगा रही है. कांग्रेस, सपा और बसपा मुस्लिम वोट बैंक के जरिए जहां चुनाव परिणाम अपने पक्ष में करने की कवायद कर रहे हैं. वहीं यह तय नहीं हो पा रहा है कि मुस्लिम मतदाता किसे वोट देगा. यही वजह है कि इन तीनों प्रमुख दलों ने मुस्लिमों को अपने दलों में शामिल करवाने के प्रयास को तेज कर यह संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि मुस्लिम मतदाता उसी के साथ है.

फैजाबाद लोकसभा चुनाव 2014 के प्रत्याशी

नाम	दल	चुनाव चिन्ह
निर्मल खत्री	कांग्रेस	हाथ का पंजा
मित्रसेन यादव	सपा	साइकिल
लल्लू सिंह	भाजपा	कमल का फूल
जितेन्द्र सिंह बब्लू	बसपा	हाथी
मयूरी तिवारी	आप पार्टी	झाड़ू
आर प्रसाद पांडे	सर्वण समाज पार्टी	फलों से युक्त टोकरी
मकसूद अली	पीस पार्टी	छत का पंखा
नसरीन बानो	राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल	केतली
राम जनम	मौलिक अधिकार पार्टी	ऑटो रिक्शा
शैलेंद्र कुमार शुक्ल	नैतिक पार्टी	आलमारी
जयरामसिंह जय	लोकप्रिय समाज पार्टी	गैस सिलेंडर

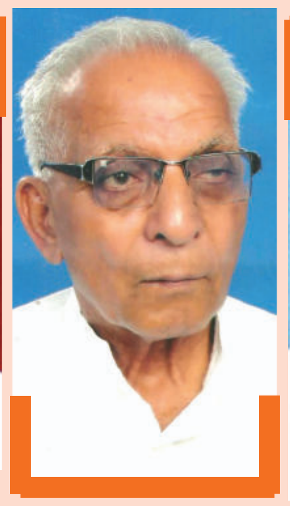

दिखाई पड़ रहा है. करीब–करीब वह चुनावी समर से बाहर दिखाई पड़ने लगे हैं. भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह के लिए मोदी लहर प्लस साबित हो रही है. जिससे अबतक वह चुनावी दौर में सबसे आगे दिखाई पड़ रहे है. वैसे कांग्रेस और सपा भी दौड़ में पहले नम्बर पर पहुंचने के लिए पूरी ताकत लगा रही हैं. … रही है. फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 1690436 हैं. संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत अयोध्या, बीकापुर, मिल्कीपुर, रूदौली और दरियाबाद विधान सभा समाहित है. रूदौली विधान सभा क्षेत्र पर भाजपा का कब्जा है और वहां रामचन्द्र यादव विधायक हैं. इसी तरह शेष चार विधानसभा क्षेत्रों पर सपा का कब्जा है, जिसमें अयोध्या में तेजनरायण पाण्डेय पवन, बीकापुर में मित्रसेन यादव, मिल्कीपुर में अवधेश प्रसाद और दरियाबाद में राजीव कुमार सिंह विधायक हैं.

गौरतलब है कि 1981 के चुनाव में जहां बसपा को 11.7 …

feedback@chauthiduniya.com

लखपति से करोड़पति कैसे बने साकेत बहुगुणा: भाजपा

रेनु शर्मा

वर्ष 2012 में टिहरी लोकसभा इप निर्वाचन के समय पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के पुत्र एवं टिहरी क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी साकेत बहुगुणा लखपति थे. इस बार वह करोड़पति हो गए हैं. महज एक साल एवं आठ माह में साकेत बहुगुणा किस तरह करोड़पति की श्रेणी में आ गए. यह मुद्दा भाजपा के लिए चुनावी बहस का मसला हो चुका है. प्रदेश भाजपा मुख्यालय में चुनाव अभियान समिति के प्रदेश प्रवक्ता मुकेश महेंद्र ने कहा कि वर्ष 2012 के उप चुनाव के दौरान साकेत ने नामांकन के समय जो शपथ पत्र दिया है, उसमें साफ–

जब विजय बहुगुणा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो उस समय साकेत पर भी कई तरह के आरोप लगे. उसमें अपने मुख्यमंत्री पिता की दलाली करना भी शामिल है. कांग्रेस की ओर भाजपा नेता ने एक अंगुली क्या उठाई की इन पर चार अंगुलियां उठ गई.

साफ है कि इनकी कुल संपत्ति 99 लाख 83 हजार है, जबकि इस बार साकेत ने अपने शपथ पत्र में यह दर्शाया है कि उनकी संपत्ति अब 11 करोड़ हो गई है. महेंद्र ने आरोप लगाया कि साकेत बहुगुणा ऐसा कौन–सा काम कर रहे हैं, … राजनीति से अपराधीकरण को खत्म करने की बात मंच से क्या किया कि इनका माखौल उड़ गया. कांग्रेस के दिग्गज हरीश रावत ने उनकी चुटकी लेते हुए कही, क्या मोदी जी को येदियुरप्पा, निशंक नहीं दिख रहे है.

feedback@chauthiduniya.com

भाजपा को डुमरियागंज में अपनों से ही मिल रही चुनौती

सुनील मिश्रा

लोकसभा चुनाव 2014 चुनावी संग्राम न कहकर महाभारत कहा जा सकता है. इसबार का चुनाव अपने आप में ही एक अलग बिगुल फूंक रहा है. कोई कहता है कि मोदी की लहर है, तो कोई इसे लहर मानने से साफ किार कर रहा है. हालांकि, इस बीच यह जरूर है कि सभी अपने लिए सुरक्षित सीट देख रहे हैं. दूसरा पहलू यह है कि इस चुनावी महाभारत में कई पार्टी के बड़े नेता इधर–उधर हुए हैं. जिसे जो समझ में आया, वह उसी पार्टी में जाकर मिल गया. कुछ बड़े नेताओं ने तो भाजपा की लहर को देखते हुए कई सालों का रिश्ता तोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया. उनका मानना है कि बहती गंगा में एक बार डुबकी लगाया जा सकता है. जैसे–जैसे मतदान का दिन करीब आ रहा है, वैसे ही नेता एक दूसरे पर निशाना साधाना तेज कर रहे हैं. उत्तर प्रदेश सबसे बडा प्रांत होने की वजह से भाजपा एवं कांग्रेस की निगाहें उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में वोटर बिखरे हुए हैं. एक तरफा कोई भी पार्टी को निकालना नाकों चना चबाने के बराबर है. फिलहाल यह सच होता दिखाई दे रहा है कि राहुल बनाम मोदी ही केन्द्र में आ सकते हैं. वहीं चर्चा इस बात की भी है कि अगर भाजपा केन्द्र में आ भी जाए, तो क्या मोदी प्रधानमंत्री बनेगे? जबकि भाजपा में हर एक बड़ा नेता दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं. टिकट बंटवारे को लेकर भाजपा में सबसे अधिक आपसी कलह भाजपा में हुआ. टिकट का आस लगाए लोगों का ही टिकट काटकर किसी …

… कर दिया है.वहीं, बसपा प्रत्याशी मो मुकीम भी डुमरियागंज सीट से रह चुके हैं. … ठोके हुए हैं. जहां तक विकास की बात करे, तो डुमरियागंज लोकसभा क्षेत्र आज भी … आज भी बिजली, पानी और सड़क की समस्या है.

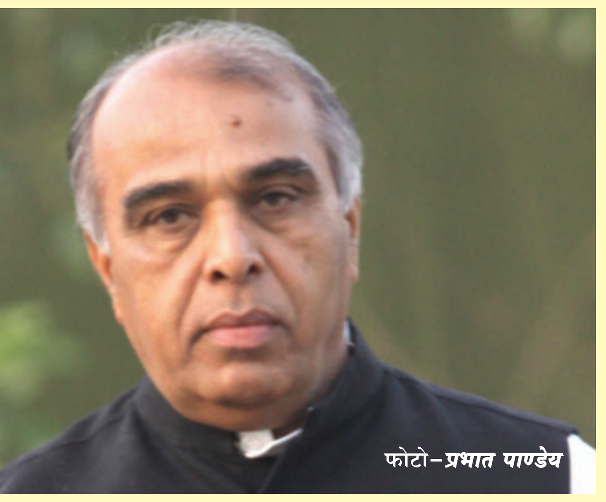

फोटो–प्रभात पाण्डेय

भाजपा के बांसी विधानसभा के विधायक राजा जयप्रताप सिंह को विश्वास था कि उन्हें डुमरियागंज से टिकट मिलेगी. अंत में पार्टी ने इनको टिकट न देखकर कांग्रेस से टूटकर आए जगदम्बिका पाल को भाजपा प्रत्याशी बना दिया. वहीं, राजा जयप्रताप सिंह ने कांग्रेस से डुमरियागंज प्रत्याशी अपनी पत्नी श्रीमती वसुंधरा को बनवा दिया. फिर डुमरियागंज क्षेत्र में यह नारा लगने लगा कि 'रानी नही यह आंधी हैं, सिद्धार्थनगर की गांधी हैं'.

feedback@chauthiduniya.com

काशी: केजरीवाल और अजय राय पर भारी मोदी

अजय कुमार

भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेन्द्र मोदी के वाराणसी से पर्चा भरते ही काशी की सियासी बिसात पूरी तरह से बिछ गई. काशी के रण में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी(आप), कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी सहित कुछ और छोटे–छोटे दलों के अलावा निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में ताल ठोंक रहे हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला कांग्रेस–भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच सिमटता दिख रहा है. हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेता मोदी की जीत को लेकर काफी आश्वस्त हैं. वहीं, विरोधी ऐसा कतई नहीं मानते हैं. खासकर,आप नेता अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के बाहुबली प्रत्याशी अजय राय को तो कतई ऐसा नहीं लगता है. अरविंद केजरीवाल और स्थानीय प्रत्याशी होने का दावा करने वाले अजय राय दोनों की ही नजर मोदी विरोधी मुस्लिम वोटरों पर लगी है, लेकिन नामांकन के दिन जिस तरह से मुसलमानों ने मोदी की हौसला बढ़ाया, वह कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लिए किसी बुरे …

वाराणसी मे चुनावी दंगल में कोई भी प्रत्याशी खर्च के मामले में पीछे नही दिख रहा है. पांच बड़े प्रत्याशियों में कांग्रेस के अजय राय,आप के अरविंद केजरीवाल और भाजपा के नरेन्द्र मोदी ने नामांकन के दौरान खुल कर शक्ति और धनबल प्रदर्शन किया. यह और बात थी कि मोदी के आगे अरविंद और अजय राय का प्रदर्शन काफी फीका रहा. मोदी के रोड शो में जहां लाखों की भीड़ थी. वहीं अरविंद के रोड शो में यह आकड़ा 25–30 हजार से अधिक नहीं पहुंच पाया.

… में जहां लाखों की भीड़ थी. वहीं अरविंद के रोड शो में यह आकड़ा 25–30 हजार से अधिक नहीं पहुंच पाया. फिर भी प्रदर्शन के हिसाब से अरविंद को दूसरा स्थान दिया जा सकता है, लेकिन नतीजे भी ऐसे ही होंगे कोई नहीं जानता.

मोदी पीएम बनेगें या नहीं यह तो बाद की बात है, लेकिन … पटेल और नामांकन कराने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश और पंडित मदन मोहन मालवीय के पौत्र गिरधर मालवीय, पद्म भूषण पं छन्नूलाल मिश्र, बुनकर प्रतिनिधि अशोक और वीर भद्र निषाद की मोदी के साथ मौजूदगी वोट बैंक की राजनीति का ही हिस्सा था.

feedback@chauthiduniya.com

देवभूमि में स्टार प्रचारकों के सहारे भाजपा प्रत्याशी

रेनु शर्मा

उत्तराखंड में मतदाताओं पर मोदी लहर की गलतफहमी में भाजपा द्वारा लड़ा जा रहा चुनाव आत्मघाती साबित हो सकता है. मोदी के प्रधानमंत्री बनने के सपने को पहाड़ की जनता के संदर्भ में कही गई एक कहावत 'सूर्यास्त पहाड़ मस्त' को बखूबी भाजपा को समझना चाहिए. पिछले साल राज्य के चुनाव में जिस तरह दिग्गज नेता जनरल खंडूड़ी भितरघात की वजह से हारे, यह इसका प्रमाण है. प्रदेश की पांचों संसदीय सीटों पर भाजपा प्रत्याशी अब तक तो अपने बूते पर …

… समिति का ऐलान किया है. इन समितियों की बैठकें भी हो चुकी हैं, जमीनी स्तर पर जिस तरह की कसरत होनी चाहिए. इन समितियों की ओर से नहीं हो पाई है. अमीर प्रत्याशी तो अपनी 'जेब' ढीली कर रहे हैं, पार्टी की ओर से भेजे जाने वाले आवश्यक झंडे और पोस्टरों की कमी … स्टार प्रचारकों के इंतजार में हैं. उनका … कि प्रदेश के स्टार प्रचारकों से ज्यादा … केंद्रीय स्टार प्रचारक ही होंगे. … केंद्रीय स्टार प्रचारकों का आना बेहद … भाजपा के बड़े दिग्गज रोजाना ही प्रदेश मुख्यालय में आकर बैठकें करते हैं. …

feedback@chauthiduniya.com